छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **सप्तम् सत्र**

रविवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 23, शक सम्वत् 1947)

[अंक 02]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रविवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 23, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय, (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, नई विधान सभा भवन में आपका स्वागत है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप नई विधान सभा में बिना घंटी के आ गए। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि आप आ रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- अजय जी इतने मग्न थे।

अध्यक्ष महोदय :- आज नवीन विधान सभा भवन में सत्र के प्रथम दिन सदन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

जन्मदिन की बधाई

श्री नीलकंठ टेकाम, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- आज सदन के सदस्य माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी का जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, कामना करता हूं, आप सदैव स्वस्थ, सुखी प्रसन्न रहें।

श्री नीलकंठ टेकाम :- महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे उपर बना रहे। मैं आपसे और पूरे सदन से यही अपेक्षा करता हूं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षीय उद्बोधन

अध्यक्ष महोदय :- आज 14 दिसम्बर है छत्तीसगढ़ विधान सभा की स्थापना का 25 वर्ष पूर्ण हो रहा है। यह **रजत जयंती वर्ष** हमारे लिए उपलब्धि पूर्ण रहा है। बीते 25 वर्षों में हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए सम्मानजनक मुकाम हासिल किया है

इसके लिए प्रथम विधानसभा से लेकर षष्ठम् विधानसभा के कार्यकाल तक सभा के सदस्य रहे सभी सदस्यगणों को स्मरण करते हुए आज मैं उन्हें याद करता हूं, मैं उन सबको नमन करता हूं।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवीन भवन में आयोजित यह **प्रथम कार्य दिवस** है। छत्तीसगढ़ विधान सभा सदन के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने इस अवसर का हमें साक्षी होने का सौभाग्य प्रदान किया। (मेजों की थपथपाहट)

हमारे नवीन छत्तीसगढ़ विधान सभा भवन में सचिवालय द्वारा यह पूरी कोशिश की गयी है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो उसके बावजूद मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में और व्यवस्था के परिर्वतन में कहीं न कहीं असुविधा हो जाती है, मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी आपको इस विधान सभा परिसर में प्रवेश से लेकर अपने सीट में बैठने तक यदि आपको लगता है कि आपकी व्यवस्था में कुछ छोटी-मोटी परिवर्तन की जरूरत है तो उस परिर्वतन के लिए आने वाले विधान सभा सत्र के पहले हमारी तैयारी हो जाएगी, कृपया आप लिखित में सूचना करेंगे तो अच्छा रहेगा।

नवीन विधान सभा के लोकार्पण अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अपेक्षा की थी कि यह केवल एक नई ईमारत का उद्घाटन का समारोह नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव है। उन्होंने यह भी कहा था कि **ये भवन लोकतंत्र का तीर्थस्थल है,** इसका हर स्तम्भ पारदर्शिता का प्रतीक है, इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है और इस भवन का हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिम्ब है, यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी भावना को सम्मान देते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा ने अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर आहूत शीत कालीन सत्र 14 दिसम्बर, 2025 को कल इस भवन की प्रथम बैठक में विज़न 2047 पर चर्चा निर्धारित की है। यह महत्वपूर्ण चर्चा राष्ट्र और राज्य के हित, सर्वांगीण विकास पर केन्द्रित होगी। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 प्रदेश के समग्र कल्याण को प्रतिबिम्बित करता है, इसलिए इस विषय में सर्वसहभागिता और सर्वसहमति का पवित्र भाव समाहित है। इस विषय को लेकर होने वाली चर्चा में से प्राप्त निष्कर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के समृद्ध, सुखद व सफल भविष्य का निर्धारण करेगा। साथ ही राष्ट्रीय परिदृश्य में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भूमिका का निर्धारण भी करेगा।

अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर छत्तीसगढ़ विधान सभा में पक्ष-प्रतिपक्ष के मध्य एक गम्भीर, सार्थक, परिणाममूलक चर्चा की अपेक्षा थी, परंतु प्रतिपक्ष द्वारा इस चर्चा में उपस्थित नहीं होने का निर्णय प्रदेश के विकास के प्रति उनके किस दृष्टिकोण को इंगित करता है और कहां तक संसदीय व्यवस्था के लिए उचित है, यह मैं उनके विवेक पर ही छोड़ता हूं। साथ ही मेरा विश्वास है कि सरकार द्वारा जो अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर अपना पक्ष रखा जाएगा, उनके यह विचार भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य की दशा और दिशा को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है-नागरिक देवो भव:, आज हम उस मंत्र को आत्मसात कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी अपेक्षा की है कि लोकतंत्र में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सब सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावाना को आत्मसात करते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान सत्र जो 14 से 19 दिसम्बर, 2025 के मध्य इस नवीन विधान सभा भवन में आहूत है, इसमें इस सभा की प्रतिबद्धता दिखती है कि यह सभा शनिवार और रविवार सामान्य तौर पर जब सदन का अवकाश होता है और हम कार्य कर रहे हैं। आपकी यह सहभागिता संसदीय मूल्यों के प्रति आपकी निष्ठा को परिभाषित करती है।

मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की जनता-जनार्दन को यह आश्वस्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का यह नवीन भवन माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से कार्य करने को संकल्पित है।

मैंने आरंभ में ही आपसे अनुरोध किया और अंत में भी आप सभी माननीय सदस्यगणों से मेरा यह सादर अनुरोध है कि यह नवीन भवन है जिसमें हमको, आपको सभी को मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करना है। प्रारंभिक तौर पर नवीन भवन की व्यवस्थाओं में हमारे अधिकतम समन्वय के बावजूद भी व्यावहारिक ढंग से कुछ असुविधाएं हमारे समक्ष आएंगी, इसमें आपका सादर सहयोग विधान सभा को अपेक्षित रहेगा। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर वित्त मंत्री, श्री ओ.पी. चौधरी जी अपने विचार रखेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम सबका सौभाग्य है कि इस नये सदन में पहली बार हम सब आपके सहयोग से यहां पर पहुंचे हैं और सामने वाले कितने दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि ये इस पवित्र सदन के पवित्र दिन के समय में अनुपस्थित हैं और बहानेबाजी करके अनुपस्थित हैं। किसी को रैली में जाना है, लेकिन सदन की अवमानना करके इन्होंने बहिष्कार किया है तो जनता इनको हमेशा बहिष्कार करती रहेगी और यह इसी तरह से बाहर रहेंगे। मैं इनके बहिष्कार की भर्त्सना करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

समय :
11.09 बजे

छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन भवन की सभी को बहुत-बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा 25 वर्षों में आज इस उत्कृष्ट भवन तक पहुंची है, इसमें आपका भी बड़ा योगदान रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात आदरणीय धर्मजीत जी ने कही, मेरे

मन में भी वही विचार आ रहा था कि जिस दिन सेन्ट्रल विस्टा बना था, जिस दिन सेन्ट्रल विस्टा का पहला सत्र हुआ था, उस दिन भी विपक्ष के लोगों ने बहिष्कार किया था। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने अपने 5 प्रणों में रखा है कि गुलामी के जो प्रतीक हैं, उनको समाप्त करना है। कहीं न कहीं देश का संसद भवन अंग्रेजों के कार्यकाल में बना था इसलिए उन्होंने नया सेन्ट्रल विस्टा बनाया और उसमें जो पहला सत्र हुआ था, उसमें भी विपक्ष ने बहिष्कार किया था और आज यहां पर जो विधान सभा की कार्यवाही हो रही है, उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया है इसलिए जनता इनको हमेशा बहिष्कृत करती रहेगी और पूरा देश इनका बहिष्कार करता रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ अनजोर विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है और एक प्रयास किया है कि भविष्य के लिए हम अपने प्रदेश को एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा तक लेकर जायेंगे। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी अमृत काल में भारत देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाया जाये, इसके लिए एक रोडमैप बनाकर योजनाबद्ध तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। उसी प्रेरणा से छत्तीसगढ़ भी इस विकास यात्रा में अपनी बराबर की भागीदारी दे सके, इस सोच के साथ छत्तीसगढ़ अनजोर विजन डाक्यूमेंट, 2047 तक के लिए सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया है।

अध्यक्ष महोदय, जब विजन डाक्यूमेंट, 2047 की बात होती है और आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी अमृत काल में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि यह लोग 2047 के लिये बात कर रहे हैं और अभी के लिये बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष यह अनर्गल आरोप लगाने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, जब तक हम कुछ बड़ा सपना देखकर बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चलेंगे तब तक किसी बड़े बिंदु तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी क्रमबद्ध तरीके से धीरे-धीरे ही उस फतह को प्राप्त किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि इसमें वर्ष 2047 तक का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, अल्पकालिक रूप से वर्ष 2030 के लिए भी अनेक रणनीतियों पर काम होगा, वर्ष 2035 तक के लिये मध्यकालिक रूप से अनेक रणनीतियों पर काम होगा और वर्ष 2047 तक दीर्घकालिक रूप से अनेक रणनीतियों पर काम होगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, अमृत काल में नरेन्द्र मोदी जी ने देश को लगातार आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारा देश जिस मोड़ पर खड़ा है, हमारा देश वहां से बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। हमारे देश की डेमोग्राफी आज पूरी तरह से युवाओं की डेमोग्राफी है। आज हमारे देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की हैं। जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जब जापान की औसत आयु 47 वर्ष है, जब यूरोप की औसत आयु हम 46 वर्ष देखते हैं, वैसी परिस्थिति

में हमारे देश की औसत आयु आज मात्र 28-29 वर्ष के बीच में है और इस तरह से देश एक युवा आबादी के रूप में खड़ा है। हम जब हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की औसत आबादी देश की औसत आयु से भी कम है और वह लगभग 24 वर्ष के आस-पास है तो हमारा डेमोग्राफी और भी युवा है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के पहले इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे भिलाई से संबंध रखते हैं। उन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में उन्होंने भारत की कंपाउंडिंग स्टोरी के बारे में पूरा जिक्र किया है कि देश की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर सकती है। जिस तरह से मोदी जी की लीडरशिप में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिस तरह से हमारी डेमोग्राफी है, तो किस तरह से हमारे देश में आर्थिक विकास की कंपाउंडिंग हो सकती है, इस पर उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने माना है कि भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, इस मोड़ पर 8 प्रतिशत के आस-पास ग्रोथ रेट अचिव्ह किया जा सकता है और 8 प्रतिशत का ग्रोथ रेट उन्होंने एचिव्ह किया है और उन्होंने 5 प्रतिशत का inflation केलकुलेट किया है। जब हम नॉमिनल जी.डी.पी. की चर्चा करते हैं तो 8+5=13 होता है। उन्होंने रूपये का डॉलर से comparison में -1 प्रतिशत का depreciation count किया है तो 8+5=13 और 13-1=12 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. से देश की इकोनॉमी की कंपाउंडिंग स्टोरी की गणना की है। अध्यक्ष महोदय, अगर 12 प्रतिशत के रेट से भारत देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, भारत देश की अर्थव्यवस्था अगर 12 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. से कंपाउंडिंग करती है तो 6 साल में इकोनॉमी की साईज डबल हो सकती है और आने वाले लगभग 24 वर्षों बाद 2047 के संदर्भ में हम बात करते हैं तो आने वाले 24 वर्षों में इस इकोनॉमी के साईज की चार बाद डबलिंग होगी, जिसके कंपाउंडिंग के कारण इकोनॉमी की साईज 16 गुना बढ़ सकती है और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. की सरकार बनी थी, जब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 2004 से 2014 तक 10 साल तक यू.पी.ए. की सरकार ने राज किया और वर्ष 2014 में जब जनता ने सत्ता से इन्हें बाहर किया, तब भी दुर्भाग्य से हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर ही थी। 10 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था रैंक की दृष्टि से कोई छलांग नहीं लगा पाई। लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने जब 2014 में देश का नेतृत्व संभाला, उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और आज हम 11 वर्षों बाद देश और दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था third lorgest economy, तीसरें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जायेगी। अगर हम कहते हैं कि चार ट्रिलियन डालर की आज इकानामी है और भारत की compounding story में अगर हम sixteen times आने वाले 24 सालों के लिये इस्टीमेट करें तो भारत देश की अर्थव्यवस्था 64 ट्रिलियन डालर की हो सकती है। मैंने एक बेसिक

एस्टीमेशन, एक बेसिक केलकुलेशन प्रस्तुत किया है। चलिये 64 न हो, 50 हो, 50 न हो 40 भी हो, अगर 40 न हो, 30 ट्रिलियन डालर भी हो, तब भी हमारी इकानामी में आने वाले 24-25 सालों में 26 ट्रिलियन डालर की नई वेल्यू क्रियेट होने वाली है। मैं मानता हूं कि आज जो पीढ़ी हमारे देश और प्रदेश में जी रही है, यह अवसर हमारी इस पीढ़ी के पास है। अपने खुद के आर्थिक विकास की दृष्टि से, खुद के बिजनेश की दृष्टि से, खुद के इंटरप्रिन्योरशिप की दृष्टि से, हमारे युवाओं के पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक बहुत बड़ा विकास का अवसर है। आज दुनिया के किसी देश के पास इस तरह की opportunity नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के भी हमने केलकुलेशन करके छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास किये हैं। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जी.डी.पी. वर्ष 2000 में 21 हजार करोड़ रुपये थी, वह आज 5 लाख 67 हजार करोड़ रुपये 2024 तक पहुंच गई थी। इसको 2047 तक लगभग fifteen times तक बढ़ाते हुए, जब हमने बेस स्टार्ट किया था, तब जी.एस.डी.पी. 5 लाख करोड़ के आसपास थी, उसे 15 गुना बढ़ाते हुए 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने की, एक सपना, एक विजन, एक रोडमैप हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है और भारत की इकानामी की जो compounding story होगी, उसी तरह की compounding story हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उससे बेहतर हो, इस दिशा में हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, इस सोच के साथ ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार का प्रथम बजट आया था, उसमें प्रथम बजट भाषण में उनके निर्देश पर हमने कहा था कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और ये विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढाते हुए ये तैयार करने का काम किया गया है। जो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिये है, 27 मई 2024 को इस परियोजना पर काम प्रारंभ किया गया और काम करते-करते 17 जुलाई 2024 को इसे संपन्न किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में लोगों को ज्यादा से ज्यादा परामर्श, उनका सहयोग, उनके विचार अलग-अलग सेक्शन से लिये गये। अध्यक्ष महोदय, जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया थी, उसमें लगातार स्टेयरिंग कमेटी की बैठक की जाती रही, लगातार लोगों से ऑनलाईन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, शिक्षाविदों के वेबीनार के माध्यम से, अलग-अलग ग्रूप के प्रदेश भर के एक्सपर्टस के माध्यम से अलग-अलग तरह के सुझाव लिये गये। सम्माननीय विधायकों से, सम्माननीय मंत्रियों से अलग-अलग विभागवार चर्चा करके इसे तैयार करने की दिशा में किया गया। अलग-अलग टीम बनाई गई और 1 लाख से ज्यादा कंसलटेशन के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो डेमोग्राफी का विवरण है, जो ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें जो डेमोग्राफी का विवरण है, वह 3 करोड़ की लगभग हमारी जनसंख्या है जो आने वाले 2047 में 3 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़ 80 लाख तक होने का अनुमान है। जो औसत उम्र है, वह उस समय 36 से 37 साल तक होगी। उस समय जो

life expectancy हैं, वह 65 से बढ़कर 84 के लगभग होगी। जो शहरी जनसंख्या अभी 27 प्रतिशत है, वह 40 से 45 प्रतिशत के बीच में होगी । इसमें जो सामाजिक इंडिकेटर्स हैं । जो सामाजिक सूचकांक हैं उसमें बेरोजगारी की दृष्टि से इसमें कमी लाने की दिशा में प्रयास होगा । महिला श्रम शक्ति की सहभागिता, चूंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 60 प्रतिशत महिलाओं की है वह बढ़कर लगभग 75 प्रतिशत तक होगी ।

अध्यक्ष महोदय, साक्षरता दर को लगभग 100 प्रतिशत, 99 प्रतिशत से ऊपर तक ले जाने का भी इसमें लक्ष्य है । शिशु मृत्यु दर जो लगातार कम होता रहा उसे भी और कम करते हुए राष्ट्रीय औसत से भी कम ले जाकर के इसे Less than 10 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है । आर्थिक रूप से जो जी.डी.पी. का साईज है वह 5 लाख करोड़ से बढ़कर 75 लाख करोड़ होगा । कृषि से जी.डी.पी. लगभग 10 से 11 लाख करोड़ के लगभग उस समय होगी, जो उद्योग से जी.डी.पी. है । वह 25 से 27 लाख करोड़ के लगभग होगी और सेवा क्षेत्र से जो जी.डी.पी. है वह लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास होगी । इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिये जो हमारे हमारे छत्तीसगढ़ का शॉर्ट एनालिसिस, मैनेजमेंट के टर्मिनोलॉजी में जो किया जाता है, वह किया गया । स्ट्रेन्थ पर आधारित 6 प्रकार के विकासमूलक थीम बनाये गये, वीकनेस पर आधारित जो हमारे स्टेट की ग्रोथ के लिये वीकनेस हैं उनको दूर करते हुए 4 अलग थीम बनाये गये और प्रमुख रूप से 3 इनेबलर्स इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे गये हैं । इसमें एक बड़ा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन और तीसरा बिंदु है अधिकाधिक प्राईवेट इन्वेस्टमेंट । इन रणनीतियों के आधार पर इन 13 थीमों के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सम्माननीय मंत्रीगण हैं । हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों का, हमारे उप मुख्यमंत्रियों का भी इस विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में चर्चा होगी । मैं इसमें विशेष रूप से जो कुछ थीम के तहत् अभी जो कुछ काम हुए हैं, छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में जो यात्रा की है और आने वाले वर्षों के लिये जो रणनीतियां हैं, मैं उसके संदर्भ में कुछ बिंदु रखना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ ने जो बड़ी छलांग लगायी है उसके संदर्भ में हम सबको गर्व भी है और आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति के तहत् काम करने की भी आवश्यकता है । सन् 2000 में जब आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था तब हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 तक आपने प्रदेश का नेतृत्व किया । वर्ष 2003 से 2018 के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में I.I.T. भी आया । Indian Institute of Technology, I.I.M. भी आया Indian Institute of Management, AIMS भी आया All India Institute for Medical Science, H.N.L.U. भी आया Hidayatullah National Law University, NIT भी बना National Institute for

Technology, IIIT भी बना International Institute for Information Technology, प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिये सीपेट भी बना । वहीं मैं आपके माध्यम से इस सदन को और इस प्रदेश को कहना चाहूंगा और यह अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रखर नेतृत्व के साथ पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में 3 और राष्ट्रीय संस्थानों के लिये उन्होंने बुनियाद रख दी है । 3 का रास्ता प्रशस्त हो गया है । पहला है N.I.F.T, National Institute for Fashion Technology, N.F.S.U National Forensic Science University और N.I.E.L.I.T. National Institute for Electronics and I.T. इतना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा की छलांग की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से प्रदेश में लगायी है । प्रयास एवं संभावनाएं, भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि और भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में आयें इस दृष्टिकोण से हम जो प्रयास करेंगे । Indian Institute of Science के लिये, S.P.A. के लिये School for Planning and Architect, I.S.A.R. के लिये Indian Institute for Scientific and Education Research के लिये और N.I.P.A.R. के लिये Natioanl Institute for Pharmaceutical Education and Research इसके लिये भी हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई-बहनों की दृष्टि से तैयार किये जायेंगे । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में, उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है । अध्यक्ष महोदय, जो Industrial Growth है, वह इस विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस Industrial Growth को सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के लिए परिकल्पना की और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 2030 तक का निर्माण किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, वह हमारे मूल रूप से फोकस किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए ज्यादा से ज्यादा, अधिकाधिक रोजगार कैसे सृजित हो। सरकारी नौकरियां, निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता के साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 सालों में जितनी सरकारी भर्तियां हुई थीं, निश्चित रूप से इन 5 सालों में उससे ज्यादा सरकारी भर्तियां की जाएंगी। लेकिन कोई भी competition exam कोई बच्चा देता है तो आप यह जानते हैं कि अगर 5 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं तो उसमें 500-1000 बच्चों का ही फाईनल सलेक्शन होता है। एक नीति निर्माता के रूप में, एक शासन के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक समाज के रूप में जो सलेक्ट होता है, उससे ज्यादा हम सब को चिंता जो सलेक्ट नहीं हो पाता है, उसकी भी करनी चाहिए। जो बच्चा सलेक्ट होता है, उसके पास तो मीडिया भी जाती है, उसका इंटरव्यू भी छपता है । हम भी जाकर, फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया में डालते हैं । लेकिन अगर 5 लाख लोगों में 1000 लोग सलेक्ट हो रहे हैं तो उस परीक्षा में हमारे 4 लाख 99 हजार बच्चे रह जा रहे हैं तो उनकी

चिंता करना भी नीति निर्माताओं का काम है। इस दृष्टिकोण से रोजगार सृजन पर आधारित औद्योगिक नीति को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले औद्योगिक नीति का जो तरीका होता था, उसमें सब्सीडी, छूट देने का जो तरीका होता था, वह निवेश आधारित होता था। पहले इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होता था। अगर कोई 1 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो यह छूट दी जायेगी। अगर कोई 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा तो यह छूट दी जायेगी। इस तरह का प्रावधान होता था। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अधिकाधिक जॉब क्रिएशन हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो। इस विजन के साथ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने तैयार करवाया है, जिसके तहत जो सब्सीडी, छूट दी जायेगी उसके लिए रोजगार सृजन को criteria बना दिया गया है। अगर कोई निवेशक आकर 1000 रोजगार सृजित करता है तो उसको यह तो यह छूट मिलेगी। अगर वह 2000 रोजगार सृजित करता है तो यह छूट मिलेगी। इस रणनीति के तहत नई औद्योगिक नीति को तैयार किया गया है। आज के जमाने में कोर्स, पढ़ाई है, वह बहुत प्रोफेशन केन्द्रित, स्कील केन्द्रित हो गई है। अगर हमारे युवा भाई बहन स्कील केन्द्रित पढ़ाई करेंगे तो उससे उनको जॉब क्रिएशन में भविष्य बनाने में ज्यादा आसानी होगी। हम केवल काऊंटिंग या गिनती के लिए पढ़ाई कर लें तो आज के प्रतिपर्धी जमाने में, आज के टेक्नालॉजी बेस्ड वर्ल्ड में, नॉलेज बेस्ड सोसायटी में बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है। हमारा सीखना, स्कील ज्यादा कारगर होता है। इस बात को समझते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हमको रोजगारपरख कोर्सेस को बढ़ावा देना है। इस सोच के साथ पिछले बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, नर्सिंग कॉलेजों और फिजियोथैरेपी कॉलेजों में हमारी सरकार ने किस तरह की छलांग लगायी है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश ने लगायी है मैं उसका विवरण देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश में 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज थे जबकि पिछले साल के बजट में एक साथ 12 नये नर्सिंग कॉलेज दिये गये। (मेजों की थपथपाहट) इसी तरह से फिजियोथैरेपी का एक कॉलेज था, उसमें 6 नये फिजियोथैरेपी कॉलेज एक साथ बजट में लेकर शुरू किया गया। जब हम हमारे छत्तीसगढ़ की इकॉनामी की बात करते हैं तो हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है जो हमारा सेकेण्ड्री सेक्टर है, वह बहुत मजबूत है। क्योंकि हमारे हैवी इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री पर आधारित इकानॉमी है, लेकिन जब हम हैवी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उतने अच्छे तरीके से रोजगार सृजन नहीं हो पाता है, जो रोजगार सृजन होता है जैसे यह माना गया है कि स्टील सेक्टर पर 1 करोड़ के इंवेस्टमेंट पर 0.**37** रोजगार ही क्रियेट हो पाते हैं अर्थात् 1 करोड़ के स्टील सेक्टर के इंवेस्टमेंट पर 1 से भी कम रोजगार पैदा होता है। इसलिए यह प्रयास किया गया है कि हम इसको ऐसे सेक्टर्स को प्रमोट करें, यह जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो सके। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में 1 करोड़ के इंवेस्टमेंट पर 30 नये रोजगार पैदा होते हैं। आई.टी., के.पी.ओ., बी.पी.ओ. सेक्टर में 1 करोड़ के इंवेस्टमेंट पर 50 रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की इकानॉमी में कोर सेक्टर मजबूत है,

लेकिन टरसरी, सर्विस सेक्टर कमजोर है, इसके कारण रोजगार सेक्टर में हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक दिक्कत आती हैं और जॉब क्रियेशन नहीं हो पाता। जहां हजारों करोड़ रूपये के इंवेस्टमेंट से बड़ी मुश्किल से 500-1000 रोजगार ही पैदा होते हैं। इसलिए नयी औद्योगिक नीति में भी और ओव्हरऑल पॉलिसी में भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि हम रोजगारपरक चीजों को ज्यादा बढ़ावा दें । इस दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के सर्विस सेक्टर का राज्य के जी.एस.डी.पी. में जो योगदान है, वह राष्ट्रीय औसत से लगभग 20 प्रतिशत कम है, राष्ट्रीय जी.डी.पी. पर सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 55 प्रतिशत है, वहीं छत्तीसगढ़ के जी.डी.पी. पर सर्विस सेक्टर का योगदान मात्र 35 प्रतिशत है । जब तक हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जॉब क्रिएशन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता । इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म के हब के रूप में भी, नेचरोपैथी के हब के रूप में भी, वेडिंग डेस्टीनेशन के हब के रूप में भी, कांफ्रेंस टूरिजम के हब के रूप में भी हम छत्तीसगढ़ को डेव्हलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । इस दिशा में मेडिकल टूरिजम के लिए बहुत तेजी से प्रयास हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में आपके कार्यकाल में सत्य सांई हॉस्पिटल स्थापित हुआ है, वह देश का अनोखा हॉस्पिटल है, जिसमें कोई बिलिंग काऊंटर ही नहीं है । वहां पर छोटे बच्चों के बड़े-बड़े ऑपरेशन किये जाते हैं, जिसमें लाखों रूपए का खर्च होता है, लेकिन उस पूरे हॉस्पिटल में कोई बिलिंग काउन्टर नहीं है । रहने, खाने-पीने का सब कुछ खर्च वहां पर फ्री में है । उसके कारण से राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग वहां पर ईलाज कराने के लिए आते हैं । इस सत्य सांई हॉस्पिटल के द्वारा 40 हजार से अधिक ऑपरेशन इन वर्षों में पिछले दशक में किया गया है । अध्यक्ष महोदय, उसी तारतम्य में नवा रायपुर में प्रयास करते हुए बाम्बे हॉस्पिटल को भी यहां पर लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है । प्राईवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल स्थापित करना चाहते हैं, उसमें भी नई औद्योगिक नीति सब्सिडी का प्रावधान करती है, ताकि मेडिकल टूरिजम डेव्हपल हो और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 44 प्रतिशत वन संसाधन हैं । हमारे पास धुड़मा रास जैसा बस्तर का गांव है, जिसे यूनाईटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिजम आर्गनाईजेशन ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ टूरिजम विलेज के रूप में चयनित किया है । हमारे बस्तर में कांगेर वैरी नेशनल पार्क है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हैरिटेड साईट के रूप में उसे चिह्नांकित किया है । इन सब जगहों पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं । हमारा 44 प्रतिशत वन्य क्षेत्र, ऐसा जंगल जो देश में बहुत बिरले मिलते हैं, उसके बाद भी नक्सलवाद के कारण, माओवाद के कारण हमारे पास टूरिजम डेव्हपल नहीं हो पाया । हमारे रायगढ़ का आदमी, हमारे कोरबा का आदमी, हमारे राजनांदगांव का आदमी, हमारे कवर्धा का आदमी भी अगर दिल्ली-मुम्बई में खड़ा होता है तो लोग सोचते हैं कि यह भी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र से आया है । इसके कारण से हमारे टूरिजम का सेक्टर डेव्हलप नहीं हो पाया । आज अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी

के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी के प्रयासों से जो माओवाद समाप्त हो रहा है, इससे हमारे पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं खुलेंगी और उसे चरितार्थ करने के लिए होम स्टे पॉलिसी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी से तैयार करके रखे हैं और बस्तर क्षेत्र में पर्यटन बहुत तेजी से विकसित हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, जब तक टूरिजम की बात करते हैं तो आजकल कांफ्रेंस टूरिजम, वेडिंग डेस्टीनेशन जैसी चीजें भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसमें बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं । इस दृष्टिकोण से हमारी नीतियां पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली नीतियां हैं और उस दृष्टिकोण से वहां पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है । जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है । यहां पर वल्लभाचार्य की जन्मभूमि चम्पारण है, यहां पर डोंगरगढ़ जैसा क्षेत्र है । जैनिजम की दृष्टि से, बुद्धिजम की दृष्टि से, हिन्दुजम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है । आचार्य विद्यासागर जी ने भी अपने शरीर को, अपने प्राण को यहीं पर त्याग किया था । इस कारण से हमारे पास हर दृष्टिकोण से टूरिजम की बहुत संभावनाएं हैं । आध्यात्मिक टूरिज्म (स्पिरिचुअल टूरिज्म) की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं । हमारे प्रदेश में शक्तिपीठ हैं, उन सब पर ध्यान केन्द्रित करने की रणनीति पर हमारी सरकार काम कर रही है और करती रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय, जब हम मैन्यूफेक्चरिंग की बात करते हैं तो देश के सबसे समृद्धि संसाधन वाला हमारा छत्तीसगढ़ है । मैं आपके माध्यम से आज कुछ तथ्य यहां पर रखना चाहता हूं । से देश में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल्वे ब्रीज बना है, उस पर छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टील का स्टील उपयोग किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) रक्षा के क्षेत्र में आईएनएस विक्रांत में हमारे छत्तीसगढ़ के स्टील का उपयोग किया गया है । हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित सीमेंट से मुम्बई का बान्द्रा वर्ली see-Link बनाया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिजली से एक हजार किलोमीटर से अधिक तक क्षेत्र देश में रौशन होते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पावर सेक्टर को मजबूती प्रदान करता है। हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित aluminium से मंगलयान में भी इसका प्रयोग हुआ है, चन्द्रयान में भी इसका प्रयोग हुआ है तथा तेजस फाइटर प्लेन में भी छत्तीसगढ़ में निर्मित aluminium का प्रयोग हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इतनी सम्पन्नता से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमारा नया विधान सभा भवन बना है। यहां पर presentation की भी सुविधा हो। मुझे लगता है कि आप नियमों में थोड़ा परिवर्तन करके presentation की सुविधा प्रदान करेंगे। क्योंकि बोलने में चीज स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। यदि वह दिखता तो अच्छा लगता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों में थोड़ा संशोधन करके

यहां पर presentation की भी व्यवस्था करें। यदि हम फोटो और वीडियों के साथ किसी भी चीज को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से present कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारा Infrastructure problematic रहा है। आजादी के बाद 50 सालों तक जिस अनुपात में Infrastructure growth करना था, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ को इस मामले में उतना ध्यान नहीं दिया गया, ignore किया गया है। मैं आपको बिहार और बंगाल के रेल नेटवर्क का एक मैप दिखाता और एक मैप हमारे छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क का दिखाता तो साफ हो जाता कि हमारी छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को आजादी के बाद 50 सालों तक किस तरह से ignore किया गया। लेकिन आज मैं विशेष रूप से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे रावघाट से जगदलपुर तक की रेल लाईन का काम स्वीकृत कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, खरसिया, जैजैपुर, शिवरीनारायण, बलौदाबाजार, मंदिर हसौद होते हुए नवा रायपुर को पार करते हुए राजनांदगांव के परमलकसा तक रेल लाईन है, उसको भी आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने स्वीकृत करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ एक Land Lock state है, जिसके कारण व्यापार-व्यवसाय में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को पुन: धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे Land Lock छत्तीसगढ़ को पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया है। इससे भी हमारे छत्तीसगढ़ की economy को बहुत boost मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम Economic Development की बात करते हैं, जब हम Infrastructure की बात करते हैं तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी economy में बड़ा ग्रोथ सेन्टर हो। हमारा देश भारत, गांवों का देश है। लेकिन गांवों का विकास भी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक economy को रफ्तार न मिले। हम देखते हैं कि न्यूयार्क जैसे एक शहर की economy लगभग 2 ट्रिलियन डालर की बैठती है और पूरे भारत देश की इकानामी, पूरी जी.डी.पी. 4 ट्रिलियन डालर की है। Economic हब का, इकानामिक ग्रोथ सेन्टर का सैकड़ों सालों में वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, हमको उसको मैच करते हुए तेजी से आगे बढ़ना है। हम इसी तरह के ग्रोथ सेन्टर की बात करते हैं तो बिना हैदराबाद के तेलंगाना के अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना बैंगलोर के कर्नाटक के अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारा छत्तीसगढ़ वर्षों नहीं, दशकों तक इग्नोर रहा, पीड़ा में रहा, उस पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी और अटल जी ने समझा और नया छत्तीसगढ़ बनाया। जब हमको छत्तीसगढ़ नये राज्य के रूप में मिला तो उसमें ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ हब नहीं था, जो इकानामी को बड़ा बूस्ट दे, जो इकानामी में बड़ा रेवेन्यु क्रियेट करके दें, जिससे हम दूरस्थ गांवों का, हमारे पिछड़े हुए भाईयों का कल्याण कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इस सोच और इस विजन के साथ आपने नया कैपिटल सिटी बनाने का काम किया था, आज वह एक ग्रोथ सेन्टर के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा

है। यहां पर ए.आई. डेटा सेन्टर आया है, यहां पर सेमी कण्डक्टर आया है, यहां पर श्री श्री रविशंकर जी ने अपना सेन्टर स्थापित करने के लिए एम.ओ.यू. किया है। सत्य सांई सेन्टर को नया जीनोम रिसर्च सेन्टर, हेल्थ स्कील सेन्टर बनाने के लिए काम आगे बढ़ाया है। उनका सीधा टाइअप टाटा मेमोरियल से है। इस कारण हमारे छत्तीसगढ़ की बच्चियां यहां पर हेल्थ स्कील की ट्रेनिंग करके टाटा मेमोरियल में जाकर जॉब कर सकेंगी। इस तरह से कामों को आगे बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस नवा रायपुर में जो क्रिकेट स्टेडियम है, वह आज बी.सी.सी.आई. को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय करके उनके साथ टाइअप किया है। उसी कारण पिछले महीने इण्डिया और साउथ अफ्रीका का इन्टरनेशनल मैच हो पाया। अगले महीने जनवरी में इण्डिया न्यूजीलैण्ड का टी-20 का इन्टरनेशनल मैच होगा। बी.सी.सी.आई. यहां पर एक ट्रेनिंग सेन्टर खोलने जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में रवि शास्त्री जी का क्रिकेट एकेडेमी भी खुले। पुलेला गोपीचंद जी का यहां पर बैडमिंटन एकेडमी भी खुले और फ्लेप्स का यहां पर स्विमिंग एकेडमी भी खुले। इस तरह के प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ग्रोथ हब के रूप में हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बट जब एक ग्रोथ हब की हम कल्पना करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के साथ एक बड़े ग्रोथ हब की भी परिकल्पना को किया गया है और पिछले मानसून सत्र में एस.सी.आर. (स्टेट कैपिटल रीजन) का एक्ट भी सम्माननीय विधान सभा ने पारित किया है, उसके लिए मैं विधान सभा को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, एस.सी.आर. की परिकल्पना में हमारे रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी क्षेत्रों को समावेशित करते हुए एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नीति आयोग की भी मदद ली गई है और इस विजन डॉक्यूमेंट को भी बनाने के लिए भारत सरकार की नीति आयोग ने भी हमारी मदद की है, इसके लिए भी इस सदन में उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जब स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में रायपुर और आसपास का क्षेत्र डेवलप होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ की इकॉनामी को एक ग्रोथ इंजन प्राप्त होगा और आने वाले समय में वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को सफल करने में हमको मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जब विकास की बात होती है तो समावेशी विकास (इंक्लूसिव ग्रोथ) अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की परिकल्पना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, इसलिए किसानों के लिए 3100 रूपये धान 21 क्विंटल में खरीदी करने का काम कर रही है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए धान खरीदी में राज्य का बजट निवेश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, माताओं और बहनों के लिए डी.बी.टी. करते हुए 70 लाख माताओं के लिए महतारी वंदन योजना का संचालन हमारी सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जब हम समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति की बात करते हैं, समाज के हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सामाजिक अधोसंरचना की बात करते

हैं तो जो कच्चे मकान हैं, उसकी चिंता करना उसको पक्का बनाना बहुत जरूरी था और प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना अनुसार 5 सालों तक आवास निर्माण को पूरी तरह से पिछली सरकार ने रोक कर रखा था। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों के छत को छीनने का [xx] किया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहला दस्तखत आवास के लिए किया था। (मेजों की थपथपाहट) लगभग 24 लाख आवास बनेंगे तो इससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी छलांग होगी और 15 प्रतिशत से कम कच्चे मकान रह जाएंगे और उसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने आवास प्लस-प्लस एक तीसरा सर्वे भी कराया है ताकि भविष्य में उनकी चिंता भी की जा सके। इनलैंड लॉजिस्टिक एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा, जिस पर हम काम करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कृषि उन्नति की दृष्टि से भी हमारे छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं जो विशेष रूप से मैं एक फैक्ट का ही बस जिक्र करना चाहूंगा। जब हमारे बस्तर की हम परिकल्पना करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमारे बस्तर में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं, जिसको प्रिमिटिव प्रैक्टिस मानकर जिसको पुरातन पंथी व्यवहार मान कर जिसको पहले इग्नोर किया जाता था केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के उपयोग को ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जितना ज्यादा बढ़ावा दिया गया, अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब जैसे राज्य उसका उसका परिणाम भुगत रहे हैं। हर गली में, हर एक दो घर के गैप में कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ा है, उसके कारण भी इस तरह की दिक्कतें आ रही है और आज पूरी दुनिया समझ रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर की संभावना, हमारे छत्तीसगढ़ की संभावना जहां परंपरागत रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसको हम सर्टिफाई कर लें, उसको हम बढ़ावा दे दें तो कितनी बड़ी संभावना को हम साकार कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसका एक उदाहरण स्वरूप एक फैक्ट बस मैं रखना चाहता हूं। सिक्किम को आज पूरे देश में ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के सात जिलों में से एक जिला दंतेवाड़ा है और दंतेवाड़ा का 70 प्रतिशत एग्रीकल्चरल एरिया को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कराने का काम किया जा रहा है। 70 प्रतिशत केवल दंतेवाड़ा जिले का ऑर्गेनिक अगर हो जाता है तो सिक्किम के पूरे एग्रीकल्चरल एरिया से केवल दंतेवाड़ा एक जिले का 70 प्रतिशत एग्रीकल्चरल एरिया पूरे सिक्किम के एग्रीकल्चरल एरिया से ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी संभावना ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में है। इस दिशा में हमको प्रयास करने की काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जो वन धन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसकी संभावना को साकारित करने के लिए कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने अपने भाषण में विशेष रूप से जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, सिक्किम का व्यक्ति हमारे बस्तर में आकर minor forest produce के Processing का कंपनी चला रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के

Entrepreneurs को, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई-बहनों को भी चाहिए कि हम इस तरह की initiative लें और इतनी बड़ी संभावना को साकार करें। इस दिशा में भी सरकार प्रमोट करने के लिए इस vision document में प्रितबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो तीन Basic enablers की चर्चा की, उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार आने के बाद गुड गवर्नेंस का अलग से डिपार्टमेंट स्थापित किया है। Ease of doing business के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। Auto mutation को रजिस्ट्री के बाद सीधा नामांतरण हो जाये, इसकी प्रक्रिया को Adopt किया गया है, जिससे हजारों-लाखों की संख्या में नामांतरण में लोगों को सुविधांए मिल रही है और उनको चक्कर लगाने से, गलत प्रैक्टिसेस से, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। पिछले मानसून सत्र में D Regulation के लिए जन-विश्वास बिल भी लागा गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस सत्र में भी जन-विश्वास बिल का दूसरा चरण लाया जा रहा है। इस तरह के अलग-अलग प्रयासों से निश्चित रूप से छत्तीगसढ़ की इकॉनामी को, छत्तीसगढ़ के social infrastructure को, छत्तीसगढ़ के सारे सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है और एक vision document के साथ, एक रोडमैप के साथ हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास कर रही है और करती रहेगी। हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ की विकास की दृष्टि से जो सबसे बड़ा मोड़ है, वह माओवाद के, नक्सलवाद की समाप्ति का मोड़ है। आज आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रयासों से जो बस्तर में माओवाद अपनी सांस गिन रहा है, यह छत्तीसगढ़ का टर्निंग प्वाइंट होगा। एक ओर हम एस.सी.आर. जैसी परिकल्पनाओं को साकारित करके इकॉनामी के लिए बड़ी ग्रोथ इंजन भी स्थापित करेंगे, वहीं दूसरी ओर इससे Create होने वाली Revenue से हमारे बस्तर, सरगुजा और मैदानी छत्तीसगढ़ के सुदूर गांवों का भी विकास सुनिश्चित करेंगे। यह विकास Inclusive होगा। इसमें समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति की भी भागीदारी होगी। इस तरह के रोडमैप के साथ, इस तरह के vision के साथ हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में चर्चा हो रही है और विपक्ष यहां से नदारद है। इस तरह की [xx] को, इस तरह के [xx] को छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी के, विपक्ष के इस तरह के [xx] प्रयासों को देश की जनता भी बार-बार सबक सीखा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह डूबती हुई एक नाव है। कांग्रेस और इस डूबती हुई नाव का डूबना तय है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और सत्तापक्ष पूरी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रही है। पूरे देश में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ को एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाने के लिए

हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, आपने इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और माननीय मंत्री जी से ओपन माईंड से कहूँगा, माननीय मंत्री जी ने अभी एक नियम कानून में प्रेजेंटेशन के लिये संशोधन की मांग की है, आप इसे स्पष्ट करेंगे । चूँकि हमारी चर्चा है इसलिये विधि-विधाई प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यह चर्चा किस मोशन में होगी, मैं प्रश्न खड़ा करूँगा और वो उसका उत्तर देंगे कि उन्होंने चर्चा कर दी या गोपनीय सत्र जैसे हुआ, हमने एक अपनी-अपनी बात रख दी कि प्रस्ताव पर, शासकीय संकल्प पर, अशासकीय संकल्प पर, किस तरह की प्रक्रिया में चर्चा होनी है और मैं किस तरह से अपनी बात रखूँ ? यह मेरे अंदर प्रश्न है, चूँकि आपने व्यवस्था दी है, छत्तीसगढ़ विधान सभा में एक नई परम्परा की शुरूआत हो रही है कि कौन सी प्रक्रिया में बहस की शुरूआत कर रहे हैं और कौन सी प्रक्रिया में इसका उत्तर आयेगा और कौन सी प्रक्रिया में चर्चा हो रही है ? इसलिये यह स्पष्ट हो जाना चाहिये था कि आखिरी में मंत्री जी उत्तर देंगे तो मैं उस तरह से बोलूँगा और यदि मुझे अपनी बात रखनी है तो मैं उसे उस तरह से बोलूँगा, यदि सुझाव देना है तो मैं उस तरह से बोलूँगा, इस तरह की चीजें चर्चा शुरू होने के पहले स्पष्ट रहनी चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बात सही कही है कि गलत कही है, आप विधान सभा अध्यक्ष हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक विजन डाकुमेंट्स रखा और निश्चित रूप से एक मार्गदर्शी सिद्धान्त होता है कि हम कैसे किस तरह से कार्य करना चाहते हैं । जितनी बातों का उल्लेख हुआ, जिस तरह से संकल्पों की अभिव्यक्ति हुई, मैं उसमें भी बात करूँगा और छोटे-छोटे विषयों पर भी बात करूँगा । अध्यक्ष महोदय, मैं निराशावादी तो बिल्कुल नहीं हूँ और निराशावादी इसलिये नहीं हूँ कि मेरी जो बात होगी तो हो सकता है कि उसमें लगे कि कोई ऐसी बात नकारात्मक हो गई होगी, वह नकारात्मक बिल्कुल नहीं होगी । हमारी सरकार है, यह अच्छी तरह से चले और यह जो संकल्प की अभिव्यक्ति हुई है, वह संकल्प निर्धारित समय में शुरू हो । संकल्प जो अंजोर विजन है, मैंने उसमें पूरे पृष्ठ पढ़े । मुझे संसदीय कार्य मंत्री जी ने परसों रात को बताया था कि आपको बोलना है, मैंने उनसे भी पूछा था कि यह किस तरह की चर्चा है और हमें किस तरह से बोलना है ? देश-दुनिया के बहुत सारे थिंकर और इंडिकेशन्स की चर्चा हुई । माननीय, आप पढ़ते हैं और मैंने आपके एक इंटरव्यूह में पढ़ा था, यदि आप नौकरी नहीं करते तो हिन्दी साहित्य में शायद कुछ करते, संभवत: हिन्दी साहित्य का उल्लेख किया था । अध्यक्ष महोदय, दुनिया के एक बड़े सुफी कवि थे, रूमी की एक कहावत है और अमेरिका का उल्लेख हुआ, खासकर अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं । रूमी की एक लाईन है- आप एक बूँद में

महासागर हो । हमने महासागर की कल्पना कर दी, लेकिन हम एक बूँद में क्या हैं और कहां पर हैं ? कलाम साहब ने कहा था कि सपने वह नहीं है, जो सोये-सोये देखे जायें, सपने वह है जो सोने न दे । आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, यह बहुत अच्छी है । मैं आपके प्रयत्नों की बधाई देता हूँ, लेकिन हम उसकी बुनियाद कैसे डाल रहे हैं, आपकी ज्ञान गति उसमें क्या बोल रहा है, उसके रिजल्ट क्या हैं, हम दूसरे क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं ? माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस दिन एसआईआर सुधार की चर्चा में स्वीकार किया था, इसमें उत्तर देते हुये उन्होंने कहा कि हम इतिहास को छोड़ नहीं सकते, इसका भी उल्लेख करना है । छत्तीसगढ़ में समग्र परिवर्तन के लिये हमसे गलतियॉ कहॉ पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है और किस तरह से निर्णयन में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिये ? उस आमूलचूल परिवर्तन के लिये इसकी अभिव्यक्ति सबसे जरूरी है । अल्पकालिक तौर पर हमारे जो प्रयत्न है, छत्तीसगढ़ में आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, जैसा कि आपने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिये गवर्नेंस डिपार्टमेंट बना है । जब छत्तीसगढ़ बना तो चारों तरफ क्षेत्रीय असंतुलन था, आपके इस नवा अंजोर के किताब में सामाजिक क्षेत्र के शिक्षा और स्वास्थ्य को स्पर्श किया है, इसमें आपने गरीबी उन्मूलन को स्पर्श नहीं किया है, आपने वूमेन इंपॉवरमेंट को स्पर्श नहीं किया है, आपने लॉ एण्ड आर्डर पुलिस विभाग को स्पर्श नहीं किया है, आपने समाज कल्याण को स्पर्श नहीं किया है । यदि नीतियॉ और कार्यक्रम बनती है तो वह रिफलेक्ट होनी चाहिये कि गरीबी उन्मूलन क्या है ? आपने रोजगार पर रिफलेक्ट किया है, पिछले पांच सालों में और छत्तीसगढ़ बनने के बाद रोजगार क्या है, यह आज तक परिभाषित नहीं हो सका है, आप मुझको बतायेंगे कि रोजगार की परिभाषा किसको मानी जाती है ? सरकार यह बेसिक लेवल पर तय करे कि रोजगार इसको माना जाये, यह छत्तीसगढ़ के लिये जरूरी है । मैं आपके इन बातों से सहमत हूँ कि आप 10 लाख करोड़ से लेकर 2047 तक 75 लाख करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा है, जो कि 14 परशेंट की लगभग बढ़ोतरी है । यह 14 परशेंट की बढ़ोतरी में हो जायेगा, लेकिन सवाल यह है कि एक अनुमान है । दुनिया में अनुमान से महामंदी आई, युद्ध के दौर चल रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अनुमान ध्वस्त हो गये थे । दुनिया अभी नई दिशा में प्रवेश कर रही है कि तीन-तीन साल से युद्ध चल रहे हैं, गाजा का युद्ध और यूक्रेन का युद्ध तीन-तीन साल से चल रहा है । हम उसको कहां तक देखेंगे। मैं तो अपनी बात कहता हूं, मैं 2047 तक जिंदा रहूंगा, 87 साल की उम्र में मरूंगा। मैं बोल रहा हूं उसको आप देखिएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रामविचार जी ने कहा तो रामविचार जी से शुरू करते हैं। मैं छोटी-छोटी बातें बता रहा हूं, हमने सिंचाई में 25 साल में कितना पैसा खर्च किया होगा ? कृषि में जी.डी.पी. का योगदान कितना हो, वह अलग चीज है। उसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण की एक बात बता देता हूं। आपने सिंचाई में अलग से पेज नहीं रखा है, कृषि के साथ ही

उसकी बातचीत की है। आपने सिंचाई को 37 प्रतिशत बताया था, यह वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण है। वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में सिंचाई 3 प्रतिशत घट गई, वह 34 प्रतिशत हो गया। जो अरबों रूपए खर्च हुए, वह कहां पर गए ? छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत कैसे घटा ? यदि सिंचाई का प्रतिशत घट रहा है तो हमारा योगदान कैसे बराबर रहेगा, इस बात को कौन तय करेगा ? इसीलिए मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में गुड गवर्नेंस की जरूरत है, 34 प्रतिशत कैसे हो गया ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका आर्थिक सर्वेक्षण बोल रहा है। आप वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण निकालकर देख लीजिए, इसको जांच करवानी चाहिए कि ये घटा क्यों ? मैं आपको दूसरी बात बोल देता हूं। कृषि पर 16 प्रतिशत का योगदान है, आगे बढ़ेगा। 25 साल में 1 लाख 60 हजार 314 हेक्टेयर कृषि का रकबा कम हुआ है, सिंचाई का रकबा कम हो रहा है, कृषि का रकबा कम हो रहा है और साहब आप कहते हैं कि वह योगदान बढ़ेगा। दूसरी बात, 19 फसलों के उत्पादन में कमी आई है। आप वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लें, 19 फसलों के उत्पादन में लगातार कमी है, 19 फसलों में 16 फसलों का रकबा भी कम हुआ है और उत्पादन में भी कमी आई है। लेकिन जो एलाइड सेक्टर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपने भी कहा कि हम किसानों के इनकम को दुगुना करेंगे। एलाइड सेक्टर में आप न अंडे में आत्मनिर्भर हैं, न मछली में आत्मनिर्भर हैं, न किसी चीज में आत्मनिर्भर हैं, बल्कि आप राष्ट्रीय औसत से कम हैं। एलाइड सेक्टर के लिए किसी भी तरह की नीतियां बने ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं है कि हम एलाइड सेक्टर को मजबूत करके कैसे करेंगे। सिंचाई में जो आपकी लघु सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं हैं, मैंने विधान सभा के भाषण में इस बात को कहा है कि सिंचाई के मामले में एजेंसी की सरकार है कि सरकार की एजेंसी है। 20-20 साल, 15-15 साल से योजनाएं पड़ी हैं और वह बन नहीं रही हैं और बनने के बाद यदि आज सिंचाई में क्षेत्रीय असंतुलन है, अभी कहीं पर जब बस्तर की बात कर रहे थे, उल्लेख नहीं करना चाहिए, दंतेवाड़ा के बस्तर के नारायणपुर से जहां से पूर्व जल संसाधन मंत्री आते हैं, इन जगहों में सिंचाई की व्यवस्था क्या है ? सरफेस वाटर की पॉलिसी क्या है ? सरफेस वाटर जो आज का विषय है, आपने नगर नियोजन में बहुत कम बात की है, उसमें सरफेस वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारी कोई पॉलिसी है या नहीं है, उसमें किसी पॉलिसी का उल्लेख नहीं है। जबकि आज की दुनिया में ये करेंट इश्यू हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एलाइड सेक्टर में अंडों के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में कहा कि हम बिल्कुल पीछे हैं, उसमें काम करने की जरूरत है, उन्होंने आंकड़ों में स्वीकार किया है, आपके विजन दस्तावेज में है। अब मैं आपको बता देता हूं जो आंकड़ें आपने दिये नहीं हैं। क्या हम बीज के मामले में आत्मनिर्भर हैं ? क्या छत्तीसगढ़ बीज के मामले में आत्मनिर्भर है ? कौन से बीज में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है और कौन सा बीज हम आज भी मध्यप्रदेश बीज महासंघ से खरीदते हैं ? आज भी हिन्दुस्तान के बीज विकास निगम से बीज खरीदते हैं, उन बीजों को खरीदते हैं जो छत्तीसगढ़ में लगाए जाते हैं, उन फसलों के भी बीज खरीदते हैं। हमने 25 साल बाद आत्मनिर्भरता में

क्या कदम उठाए ? मेरे कहने का मतलब यह है कि नीतियों में ये छोटी-छोटी बातें छत्तीसगढ़ को बड़ा करेंगी। मैं सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये वस्तुस्थिति है, किसी सरकार की है या नहीं है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। पशुपालन, जब मैंने एलाइड सेक्टर का उल्लेख किया तो आपको बता देता हूं, दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान मात्र दशमलव 88 प्रतिशत है। ठीक है साहब।

समय :

12.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में खपत कितनी है? मतलब यदि हम शुरूआत के 5 राज्यों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात व छत्तीसगढ़ को ले लें तो खपत 192 ग्राम है। पंजाब के लोग प्रति व्यक्ति सवा लीटर दूध पीते हैं। नस्ल सुधार में आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। जो हाईब्रिड नस्ल है, दुग्ध उत्पादन में वही 33 प्रतिशत का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर देती है और छत्तीसगढ़ में उसका प्रतिशत कितना है? मैं आपको बता देता हूं कि नस्ल सुधार में हाईब्रिड नस्ल का योगदान 33 प्रतिशत है और हमारा योगदान 6.3 प्रितशत के आसपास है। आपके पास नस्ल सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है। आई.वी.एफ. तकनीकी इतनी महंगी है कि किसान उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। माननीय डॉ. साहब ने इसके लिए अपने समय में कामधेनु विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला बनवाई थी। आज वह किस स्थिति में काम कर रही है, यह मैं नहीं जानता हूं। आपने चारा की बात की है तो हम चारा की बातचीत करेंगे। आपके जो पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय हैं, वह टीकाकरण और इलाज के मामले में मरणासन्न स्थिति में हैं। मैं आपको यह बात बता देता हूं कि आपको दुग्ध उत्पादन या एलाइड सेक्टर को मजबूत करने के लिए सोचने और ग्राउंड लेवल में काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में इन्हीं छोटे-छोटे निर्णय की जरूरत है। मैंने आपको इसीलिए रूमी की कविता बोली कि बूंद-बूंद से महासागर बनेगा। आपके पास चारा के लिए कोई खास प्रोग्राम नहीं है। एक भी प्रोग्राम नहीं है। आपने ऑर्गेनिक खेती का उल्लेख किया। आपने पंजाब का उदाहरण तो बताया कि पंजाब से राजस्थान के बीच कैंसर वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। आपने देश-दुनिया की बात की, लेकिन यूरोपीय यूनियन और अनेक देशों ने भारत के ऑर्गेनिक खेती के कई उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया कि आप फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड का उपयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं तो आपके उत्पाद प्रतिबंधित हैं। अब मैं यह बात कहता हूं कि यदि हमारी यह स्थिति है तथा एलाइड सेक्टर में हमारी स्थिति कमजोर है तो एलाइड सेक्टर के लिए हमारी नीति क्या है? आप उसको उद्योग का दर्जा दे रहे हैं तो हमारी नीति क्या है? दूसरी बात, चारागाह के लिए आपकी नीति क्या है? कुछ नहीं है। नर पशु का क्या उपयोग होगा? मशीनीकरण करने के बाद नर पशु का कोई उपयोग नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान में आजकल सिर्फ और सिर्फ मादा नस्ल से भी मादा नस्ल पैदा किए जा सकते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ में उसका कोई उपयोग नहीं है और उसकी कोई नीति नहीं है तो ये छोटे काम हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। आपने

एन.डी.डी.बी. से समझौता किया है। अब वह समझौता किस स्टेज में है, उसका क्या क्रियान्वयन हुआ है, उसको आप पूछ लीजिए। यदि मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि दूध के उपयोग व उत्पादन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मछलीपालन, पशुपालन, मधुमक्खीपालन जैसे जितने तरह के एलाइड सेक्टर हैं, उसके लिए नीति की जरूरत है और तब आप माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करेंगे। गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है। गुजरात मॉडल और आपके गवर्नेंस के बारे में हम धीरे-धीरे बात करेंगे। आपने स्वास्थ्य विभाग में चर्चा की। आप सेज बनाएंगे। सेज की अवधारणा क्या है? स्वास्थ्य के पहले उद्योग का विषय थोड़ा ज्यादा था। आपने उद्योग नीति बनाई। अच्छा है। आप उसमें रोजगार देंगे। अच्छा है। मैं आपको रोजगार के बारे में बता देता हूं, जिसका उल्लेख आपने भी किया। छत्तीसगढ़ में 97 प्रतिशत लोग अनस्किल्ड हैं और 3 प्रतिशत आबादी स्किल्ड हैं। आप जितनी शैक्षणिक संस्थाएं ला रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ काम करते हुए हमने ढेरों संस्थाएं बनाईं और जिन संस्थाओं का आपने उल्लेख किया, उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत है, लेकिन आपको इस पर सोचना है। जब हम शिक्षा में बात करेंगे तो इस विषय में आएंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रवेश कैसे हो? आपने औद्योगिक नीति बनाई, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि आपने उसे लागू करने के लिए बनाई या संशोधन करने के लिए बनाई? मैं हर 15-20 दिन में पढ़ता हूं कि उसमें एक संशोधन हुआ है। अब कहीं पर यह झलक नहीं मिलती कि मेक इन इंडिया। मेड इन छत्तीसगढ़ या मेक इन छत्तीसगढ़ कहां पर है ? जब माननीय थे, मैं छत्तीसगढ़ का मेक इन छत्तीसगढ़ और मेड इन छत्तीसगढ़ के छोटे-छोटे उदाहरण दे देता हूं। हम सायकल खरीदते हैं। चलिये आपने देश दुनिया की बात की। चीन ने जब एप्पल को बुलाया तो उन्होंने कहा कि आपको कामगारों को यहीं प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब वहां के कामगार प्रशिक्षित हुए तो वहां से कितनी सारी कंपनियां निकली ? MI वहीं से निकली, Vivo वहीं से निकली और Oppo भी वहीं से निकली। आज ऐसी कौन-सी कंपनी है, ऐसी कौन सी चीजें और ऐसे कौन से सेक्टर हैं, जिन्हें हम चिन्हित करके छत्तीसगढ़ में मेक इन छत्तीसगढ़ और मेड इन छत्तीसगढ़ कर सकते हैं ? आपकी उद्योग नीति इसमें क्या बोलती है ? अब मैंने कहा कि हम सायकल बांटते हैं। उसमें क्या प्रतिस्पर्धा है ? उसको चाहे एटलस बनाये या एवन बनाये। छत्तीसगढ़ में कारखाना डालिये। हम 20 साल तक सायकल देंगे और उसके सहायक उद्योग यहीं खुलेंगे, यहीं बनायेंगे और आप सायकल बांटिये। उसमें क्या प्रतिस्पर्धा है ? जो छत्तीसगढ़ में आकर बनायेगा, उसको हम देंगे। जो हमारे अनुकूल बात करेगा जो हमारे मैन पॉवर को Trained करेगा, Skill करेगा, उसको हम देंगे और उसके बाद हम बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गये। यदि आप मशीन नहीं बनवा सकते हैं, बाकी चीजें नहीं बनवा सकते तो पूनी को यही बनवा लीजिये, पट्टी को यही बनवा लीजिये, रीएजेन्ट्स

को यहीं बनवा लीजिये। आपको किसने मना किया ? अब आप सेज की बात करते हैं। हिन्दुस्तान में जब सेज की बात करते हैं तो आज कल सेज बंद हो चुका है। हमने अपैरल पार्क बनाया था, चलिये घूमने चलते हैं और अपैरल पार्क की क्या हालत है देखते हैं ? वह एक तरह का सेज ही है। आपने कुटीर उद्योग के लिये इसमें क्या पॉलिसी रखी है ? एक बेल मेटल का आदमी, एक स्व सहायता समूह का आदमी, एक और भी लघु कुटीर उद्योग के लोग हैं, आप उनको कौन सी नीति के तहत फाइनेंस करते हैं, कौन सी नीति के तहत कच्चा माल देते हैं, उसको कौन सी नीति के तहत ट्रेनिंग देते हैं ? यदि 10 हजार दुर्गा पंडाल बनते होंगे तो रायपुर के सारे दुर्गा पंडाल बंगाल के लोग आकर बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के बांसवारों को बांस की ट्रेनिंग देकर वेल्यू एडिशन कर दिया जाये। इससे उसको फाइनेंस मिलेगा, उसको बैंक गारण्टी मिलेगी। यहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं, आज आर. सेठी जिनको ट्रेनिंग देते हैं, वही उनको फाइनेंस नहीं करते हैं। जब उनको अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं है तो यह जो छोटे निर्णय है, मेक इन इंडिया और मेक इन छत्तीसगढ़ और मेड इन छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि आप मेक इन छत्तीसगढ़ भी खरीद सकते हैं, आप मेक इन इंडिया भी खरीद सकते हैं यदि मेड इन नही है तो। छत्तीसगढ़ में इस नई अवधारणा के लिये इतना potential है और आपने जिस आर्थिक क्षेत्र की परिकल्पना की है, यदि उसमें इतना potential है तो फिर यह चीजें हम क्यों नहीं ला सकते ? उन कंपनियों से यह बात क्यों नहीं कर सकते ? समय में हिन्दुस्तान में अपने उद्योग नीति, अपने कार्य में।

समय:

12.09 बजे

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष विधान सभा के अध्यक्षीय दीर्घा में आसीन है। सदन की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) कृपया जारी रखें।

छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक कहीं पर भी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिये कोई नीति नहीं बनी। आज इतने लाख के बी.पी.ओ. में, इतने लाख के इस्पात में, हमारे चन्द्रमा में यह पहुंच गया, हमारा लोहा पहुंच गया, टाइटन पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, दुर्घटना वाला तेजस हमारा नहीं था। आप बता दीजियेगा कि दुर्घटना वाले तेजस में हमारा लोहा नहीं लगा था। लेकिन जो सबसे

ज्यादा रोजगार देता है, वह थ्रस्ट सेक्टर है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग वहीं उद्योगपति बनेंगे । खाद्य मंत्री जी बतायें कि राईस मिल की क्या हालत है या तो आज उसमें स्वतंत्र बहस कर लीजिये कि उसकी क्या स्थिति है ? मरेंगे या जियेंगे या बचेंगे ? मैं धान खरीदी पर भी थोड़ी देर बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है। जो थ्रस्ट सेक्टर है, उसको हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम समाप्त होने की कगार पर है, उसको ठीक करने की जरूरत है और वह कैसे ठीक होगा, यदि आप चर्चा करेंगे तो उसके सुझाव हैं। आप वह फोरम बताईये। मैंने विजन-2047 बताते समय आपसे कहा था कि आप किसी दिन चर्चा के लिये आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर आकर सुझाव दूंगा। लेकिन आपने वह अवसर नहीं दिया। कोई बात नहीं। पर्याप्त है, आपने अच्छा बनाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त की बात हुई, अच्छी है। मैंने सहमति दी। मान लीजिए छत्तीसगढ़ 3 ट्रिलियन डालर इकानामी में पहुंच जायेगा या 2 ट्रिलियन डालर मान लेते हैं, 2047 तक न्यूयार्क बन जायेंगे। मैं दिल्ली में था, लेकिन उससे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी के कान में भी गुनगुनाया था। हम खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं तो बजट किसलिये? हम राशि का क्या करेंगे ? freebies के लिये, राजस्व व्यय जिसमें अकल नहीं लगती, उसमें यदि हम खर्च करते हैं तो उसमें गवर्नेश कहां पर है? जहां पर खर्च करना है, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बेसिक सेक्टर में खर्च कितना हो रहा है और क्यों नहीं हो पा रहा है। यहां पर गवर्नेश की जरूरत है। वह कैसे ठीक होगा, आप पूछेंगे तो हम वह भी बतायेंगे। हम पहली बार सुनें कि बजट व्यय बढ़ाने के लिये सी.एस. की बैठक हो रही है। पेपर में पढ़ा । क्या सच है, यह अन्य विषय हो सकते हैं, लेकिन हमने इस बात को पढ़ा। आप मुझको यह बताईये कि skill development की जब बात हुई, कितने विभाग skill development करते हैं ? इसको देखने की जरूरत है कि क्या skill development करते हैं ? उसकी डिमांड छत्तीसगढ़ में, दुनिया में है या नहीं है ? यदि आपने जो नीति बनाई है, उसको आपने skill development का सर्विस एजेंट दिया है, वह कितने दिन नियोजन करता है ? उसके बाद वह नौजवान कहां गये जिनका skill development हुआ है ? जो 3 प्रतिशत लोग हमारे पास स्किल्ड हैं, जो आपने नौजवान छत्तीसगढ़ कहा, 97 प्रतिशत लोगों के लिये रोडमैप की तत्काल जरूरत है जो आपको करना चाहिए। यही छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको वित्त पर क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में बोलना है। बाकी सब उनकी परिकल्पनायें अच्छी हैं। चलिये मैं एक उदाहरण रायगढ़ का ही ले लेता हूं या और कोई नारायणपुर ले लेता हूं। अब आपको नारायणपुर में परियोजना के, नक्सल क्षेत्र के, आदिवासी प्राधिकरण के, डी.एम.एफ. के पैसे मिलेंगे। सारे पैसे मिलेंगे। रायगढ़ और कोरबा में डी.एम.एफ. के इतने सारे पैसे हैं कि दूसरे बजट की जरूरत नहीं है। पर जशपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, मुंगेली में डी.एम.एफ. का कितना पैसा है और कौन-कौन सी स्कीम लागू है और उस असंतुलन को दूर करने के

लिए हम क्या कर रहे हैं ? यदि सारी योजनाओं के पैसे सब जिले में बराबर बंट रहे हैं तो अतिरिक्त जो पैसे हैं, उनके सम्यक और संतुलित विकास के लिये असंतुलन कैसे दूर होगा, यह तो हम निर्णय करेंगे। एक तरफ ये असमानता है। अभी 1 लाख 30 हजार करोड़ के लिये मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करवाई, एक बार मैं चाहता हूं कि सदस्यों के लिये, मुख्यमंत्री जी के लिये, अध्यक्ष जी के लिये, जो भी मंत्री शामिल हैं, उन सबके लिये मेज थपथपाकर इसके लिये बिल्कुल स्वागत करें। (मेजों की थपथपाहट) अब एक लाईन आपको समर्पित कर देता हूं, फिर मैं वित्त की चर्चा बंद करूंगा। फिर दूसरे विभाग को स्पर्श करते हुए चलूंगा। Milton Friedman नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री हैं। आप उनकी लाइन पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी गलतियों में एक यह है कि नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन उसकी नीयत से नहीं, उसका मूल्यांकन उसकी नीयत से नहीं, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, उनके परिणामों से होना चाहिए। आप यह देखिये कि अभी दो साल, तीन साल में आगे के लिये परिणाम क्या बात रहे हैं। और हम अक्सर उसका उल्टा करते हैं। हम नीयत को देखते हैं परिणाम को नहीं देखते। यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं कि परिणाम को हम देखें। नीयत में कहीं कोई संदेह नहीं है। भगवान विष्णु के पालनहार हैं, उनकी नीयत में कैसे संदेह होगा। संदेह पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कहूंगा, आपको कहूं या न कहूं, आप बता दीजियेगा। liberalisation या liberal के सबसे बड़े अनुयायी हमारे विष्णु भगवान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं तो नहीं सोचता कि बाकी मंत्रियों के पास ये है या नहीं है, मैं नहीं जानता, आप हैं या नहीं हैं, मैं नहीं जानता। क्योंकि [XX][1] कभी-कभार आपसे बात होती है । कभी-कभार आपसे मुलाकात होती है [XX] जब आप लिबरल नहीं रहेंगे तो, हम लोग मदद करेंगे न ।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह नहीं लगता है कि व्यक्तिगत विषयों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए । हो सकता है कि मैं...।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आरोप लगाउंगा तब तो आप व्यक्तिगत कहेंगे, आप सदन की परम्परा सिखा रहे हैं । इसमें क्या मैंने कोई आरोप लगाया, क्या मैं अनुमति लेकर लगाऊंगा ? मैंने यह कहा कि आप लिबरल हैं या नहीं हैं ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने बात रखी ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपको पूछ देता हूं कि आप लिबरल हैं या नहीं हैं ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- देखिये, मैं भी दूसरी बार का विधायक हूं । ऐसा नहीं है और मुझे भी नियम-परम्परा मालूम है ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो चलिये, बुरा है तो डिलीट कर दीजिये साहब । यदि अन्यथा है तो मैं क्षमा मांगता हूं ।

---

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- हां, इसको डिलीट करने के लिये मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- जायसवाल जी, ऐसा है कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है । मैंने पूछा है और मैंने उनसे अनुमति ली और यदि बोलें तो मैं चर्चा भी बंद कर देता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.एम.आर., स्वास्थ्य विभाग में एम.एम.आर. यह निरंतर घटेगा लेकिन राष्ट्रीय औसत के लिये हम एक्स्ट्रा एफर्टस कैसे कर रहे हैं। मैं ऐसे ही बोल देता हूं । सेज बनायेंगे, मेडिकल सेज । क्या है भई मेडिकल सेज ?

क्या हम छत्तीसगढ़ में कोई कार्यक्रम स्वीकार कर सकते हैं ? हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं लेकिन फैकल्टी कैसी है, पढ़ाई का स्तर कैसे हो रहा है ? एक भी मेडिकल कॉलेज में कोई फैकल्टी नहीं है । प्राईवेटाईजेशन की बात है, आपके समय में हम लोगों ने जो कदम उठाये थे, मैं इतिहास के तौर पर कुछ का उल्लेख कर देता हूं । हमने मेडिकल कैडर अलग बनाने की बात कही कि सारे मेडिकल डॉक्टर जो हैं, वह अपना काम करें । प्रशासन करना उनका काम नहीं है, सेवा भर्ती नियम में हम करेंगे । मेडिकल साईंस और मेडिकल मैनेजमेंट में एम.बी.ए. पास लोग हैं, ऐसे लोगों का कैडर बनायेंगे, उनको पदौन्नति देंगे, उसको हम वेतनमान में पदौन्नति देंगे करके। आपको याद होगा कि उन डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल आपसे मिले, बोले साहब हम लोगों को मेडिकल, आपने कहा कि अभी रहने दीजिये । एक क्रांतिकारी पहल थी। हमने एक-एक डिप्टी कलेक्टर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ करने की बात कही थी इसलिये कही थी कि यह खरीदी-बिक्री करना डॉक्टरों का काम नहीं है । यह दूसरे लोग करें । वह सुधार क्यों रूका ? जो पी.पी.पी. मॉडल की आप कहीं भारत सरकार की संस्था से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में कौन-कौन सी सेवाओं को इधर के तत्कालीन सचिव थे, मैं यहां नाम तो नहीं लूंगा । उनसे पूछ लीजियेगा, पूरे प्रोक्योरमेंट हो गये फिर वह रूक गया कि सरकार इतना पैसा देगी और इतनी सेवाओं को हम देंगे क्योंकि हम उसको कर नहीं पा रहे हैं तो भारत सरकार की यह संस्था मौजूद है कि कौन-कौन से संस्थाओं में, किस तरह की सेवाओं में पी.पी.पी. मॉडल ला सकते हैं यह मौजूद है, यह निर्णय पहले हो चुका था फिर रूका क्यों ? यह तो तत्काल होना चाहिए । मैं इसमें यह कहना चाह रहा हूं । उसके बाद एनीमिया, हम एक कार्यक्रम के तौर पर क्यों स्वीकार नहीं कर सकते ? सारे प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम हैं । एग्रीकल्चर में भी, स्वास्थ्य में भी, छत्तीसगढ़ एक प्रोग्राम स्वीकार कर सकता है कि एनीमिया के खिलाफ युद्ध और एनीमिया उस तौर पर जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा कंसनट्रेशन है बस्तर । हम जीवन की प्रत्याशा की बात करते हैं कि 76 वर्ष है । मैं कुरूद में आदिवासी मोहल्ले में रहता हूं, मेरा वॉर्ड सुरक्षित था । आप एक अलग से सर्वेक्षण करवाईये कि छत्तीसगढ़ में ट्राईबल में कितना एवरेज एज है ? आपको स्वास्थ्य की स्थिति पता लग जायेगी । आदरणीय चौधरी जी, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, 50-55 साल होगी तो बहुत है । मैं हजारों बार उनकी बैठकें ले चुका

कि आपको यह-यह चीजें नहीं करनी हैं करके । नहीं मानते, आप अलग से सर्वेक्षण करवाईये । आज की तारीख में हम मानव विकास सूचकांक, मिलेनियम गोल हब्स इसकी यदि चर्चा करें । हमने पहले आपके डिपार्टमेंट में एक प्रकोष्ठ बनाये थे, रूरल डव्हलपमेंट में मिलेनियम गोल हब्स करके । इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कौन से ईलाके में सबसे कम है ? उसको बढ़ाने के लिये हम क्या कर रहे हैं ? कौन से ईलाके में प्रति हजार बेड की संख्या कम है ? हम उसको बढ़ाने के लिये क्या कर रहे हैं ? ठीक है कि मेडिकल कॉलेज खोल दिये लेकिन उससे जिला अस्पताल और बाकी जगह बेड में तो वृद्धि नहीं हो रही ? उसके लिये हम क्या करें ? उस नजर से बस्तर के लिए हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी जो स्वास्थ्य का प्रोग्राम बनेगा उसमें वह शामिल हो। मैं तो नहीं जानता, पर जो आज की स्थिति है। मैंने गवर्नेस की बात की। मैं गवर्नेस (governess) की बात इसलिए कर रहा हूँ । तात्कालीन मुख्यमंत्री जी आज अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान हैं उस समय पैट स्कैन मशीन और गामा मशीन खरीदी गयी। मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर बनता, यदि उसमें किसी तरह का करप्शन है तो उसका भुगतान भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। यदि मेरे दस्तखत फंसे हैं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक उदाहरण दिया।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद उस समय माननीय सदस्य महोदय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके बाद तुरंत हट गया था।

श्री केदार कश्यप :- आप उसमें वह करिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ।

आप सारी चीजों में कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैट स्केन, गामा मशीन जो गरीब लोगों को सबसे बड़ी सुविधा देगी। मैंने 5 बार भूपेश बघेल जी को हाऊस में कहा होगा कि उसको जांच करवाकर, खोल दीजिए, सजा देकर खोल दीजिए। लेकिन वह कब खुलेगा या खुल गया, यह नहीं मालूम। लेकिन यह बड़ी चीज है। आज तो मैंने पढ़ा है कि जितनी लागत है कितना सच है, उसका उत्तर आएगा तो मैं देखूंगा, सुनूंगा कि उसको फिर से चालू करने में हमर लैब कहां चल रहा है, उसको मैं नहीं जानता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सिकल सेल संस्थान बनाया था। यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने यह कहा कि हम कुछ चीजों को स्थानीय प्रोग्राम के तौर पर स्वीकार कर लें। जिसमें एक सिकल सेल संस्थान की स्थापना हो। ओ.बी.सी. और आदिवासी लोगों में यह बीमारी बहुत कॉमन है। मैं चाहता हूँ वित्त मंत्री जी उसका निरीक्षण जरूर करें, उसके लिए आवश्यक बजट, संसाधन की व्यवस्था जरूर करें। फाईलेरिया, छत्तीसगढ़ की ही बीमारी है इसके लिए हम अभियान के तौर पर क्यों स्वीकार नहीं कर सकते कि छत्तीसगढ़ को इससे मुक्त करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश टी.व्ही. की बीमारी सबसे ज्यादा है। संचारी रोग में पूरे भारत में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ प्रदेश में टी.व्ही. की बीमारी होती है। हम

क्यों बड़ा संकल्प नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी मांग हो रही है, इतने बड़े आर्थिक परिदृश्य से हमको दिखाया जा रहा है, इतने रोजगार के परिदृश्य दिखाये जा रहे हैं तो बेसिक चीजों में छत्तीसगढ़ लड़ाई लड़ेगा। यह इस शासन का संकल्प है। यह संकल्प, मैंने कहा कि छोटे-छोटे संकल्पों से यह छत्तीसगढ़ महान बन जायेगा। यह संकल्प का ही जनादेश हमारे पास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा विभाग में पढ़ा कि हम गुजरात का मॉडल लागू करेंगे । मैं बहुत सारे मंत्रीगणों का सुनता हूँ तो वह कहते हैं कि हम गुजरात का मॉडल लागू करेंगे। हमने बहुत सारे असंतुलन को दूर किया । जिस दिन छत्तीसगढ़ बना, आपने यह पूछा था कि जी.आर. कितना है ? तो ब्यूरोक्रेसी को यह मालूम नहीं था कि जी.आर. कितना है ? जब गणना करवायी गयी तो वह पौने 2 प्रतिशत निकला। कांग्रेस की 50 सालों की यात्रा में छत्तीसगढ़ की यह भयावह स्थिति थी। लेकिन आपने एक दिन में 3 विश्विवद्यालय बनायें, निजी विश्विवद्यालय विधेयक बनाये। हमने प्राईवेट कॉलेजों के लिए विधान सभा में कानून बनाया और पारित किया। आज सब में 19 प्रतिशत में हैं। पर हम राष्ट्रीय औसत से कितना पीछे हैं ? जब इतनी सारी संस्थाएं खुल रही हैं तो बेसिक हम कहां पर पीछे हैं ? और क्यों पीछे हैं ? मैं curriculum पर कहना चाहूंगा कि जितने विश्वविद्यालय हैं कोई गणेश का "ग" पढ़ा रही है या गधा का "ग" पढ़ा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक विषय के कितने curriculum है। राष्ट्रीय प्रतियोगी परिक्षाओं के लायक वह curriculum है या नहीं है ? विद्या परिषद् की बैठकें कितनी होती हैं? यहां कब-कब curriculum को ठीक किये गये। यहां कितनी प्लेसमेंट की एजेंसियां हैं जो छत्तीसगढ़ में आती हैं, कितनी बड़ी कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट के लिए आती हैं क्यों छत्तीसगढ़ के बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता ? उसको सोचने की जरूरत है। मैंने उसका अध्ययन करवाया था, हम बोल नहीं सकते, हमारी अंग्रेजी कमजोर है, हमारी कम्प्यूटर की शिक्षा कमजोर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में राजकीय विश्वविद्यालय में 1100 पद हैं और 806 पद के आसपास यू.टी.डी. में रिक्त है। 6 शोध पीठ हैं और शोध पीठ का अध्ययन् करने के लिए एक पीठ बनाना चाहिए कि शोध पीठ में क्या हो रहा है ? अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने एक बैठक ली थी, आपको याद होगा कि शोध पीठ या तो बंद कर देनी चाहिए और या नहीं तो ठीक से काम करे, इसकी चिन्ता करनी चाहिए । नाम के लिए उसको नहीं चलाना चाहिए । आपने छत्तीसगढ़ की पहली अकादमी हिन्दी ग्रंथ अकादमी बनाई । संस्कृति में बात होती है, शिक्षा में बात होती है । मैं अभी मेक इन छत्तीसगढ़, मेड इन छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था । आप पुस्तक छापते हैं, पुस्तक बनाते हैं । छत्तीसगढ़ के रचनाकार, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के संदर्भ ग्रंथ कौन प्रकाशक छापेगा ? वह आपने बनाई थी, वह भूपेश बघेल जी का विषय नहीं था, वह हमारा विषय था । उसमें ताला लगा हुआ है ।

श्री राजेश मूणत :- उनका कौन सा विषय था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब ये बताएंगे कि कौन सा विषय था ।

श्री राजेश मूणत :- फिर उस विषय पर आ जाईए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ में किताबें कौन-कौन बनाता है ? एन.सी.ई.आर.टी. की भी किताब चलती है, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भी किताब बनाता है, एस.सी.ई.आर.टी. भी किताब बनाता है । अब यह निर्णय करने की जरूरत है कि ब्यूरोक्रेट एस.सी.ई.आर.टी. में बैठेगा या कोई वैचारिक आदमी बैठेगा या कोई शिक्षाविद बैठेगा ? यह निर्णय होते हैं कि साहब, इसमें कोई शिक्षाविद् बैठेगा और केरिकुलम कैसे बनेंगे, कौन सा केरिकुलम पढ़ाया जाएगा । समन्वय समिति की बैठक होती है या नहीं होती है, यह मुझे नहीं मालूम, उसे शिक्षा मंत्री जी जानेंगे, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री थे तो समन्वय समिति की नियमित बैठक होती थी और एक फोरम था कि सारे कुलपति, रजिस्ट्रार कम्प्लायंस देते थे कि यह-यह निर्णय हुए हैं और हमने इन तीन महीनों में इतने काम कर लिये । जब मैं पहली बार माननीय राज्यपाल जी से मिला था तो मैंने एक बात कही थी कि कुछ हो या न हो, पर समन्वय समिति की बैठक होनी चाहिए । राज्य के सामने आता है कि उच्च शिक्षा का परिदृश्य क्या है ? अब छत्तीसगढ़ ने नई शिक्षा नीति स्वीकार कर ली । कितना पैसा लगेगा, कितनी किताबों में परिवर्तन होगा, कितनी कक्षाओं में परिवर्तन होगा, कितने भवन में परिवर्तन होगा, कितने कॉलखण्ड में परिवर्तन होगा, कितनी भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषाओं में हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रीय बोलियों में हम क्या कर रहे हैं ? यह जो छोटे-छोटे निर्णय हैं, वे छत्तीसगढ़ को गरिमा देंगे, स्थान देंगे । मैंने स्मार्ट क्लास के संबंध में पूछा था कि स्कूल का नया नक्शा एस.सी.ई.आर.टी. बनाती है या पीडब्ल्यूडी बनाती है, 11वीं, 12वीं के छात्राओं के लिए कोई चेंजिंग रूम है क्या, को-एजुकेशन है क्या, को-एजुकेशन के लिए अलग-अलग रूम हैं या एक रूम हैं ? रैम्प बनते हैं या नहीं बनते हैं, बिजली लगती है या नहीं लगती है, एक नया नक्शा, स्मार्ट क्लास रूम हम शुरू से बना सकते हैं क्या, बिजली शुरू से लगा सकते हैं क्या? तो उन्होंने मुझे जानकारी देने की बात कही, पर अभी तक मुझे वह जानकारी नहीं मिली है । मैं तो कहता हूं कि भवनविहीन स्कूल और भवनविहीन कॉलेजों के लिए सबसे ज्यादा पैसे देने चाहिए । क्षेत्रीय असंतुलन में भी मैंने यही बात कही कि कॉलेज की सीटें एक अध्ययन की जरूरत है कि 19 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक ले जाने का जो एक महती लक्ष्य है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन विभाग या पीडब्ल्यूडी विभाग में बोल देता हूं कि क्योंकि आपने परिवहन और पीडब्ल्यूडी विभाग में विज़न 2047 में बहुत कम लाईनें दी हैं । लॉजिस्टिक की नीति भी इसी में है । विशाखापट्टम सड़क आपने बनाई, वह बन रहा है । केन्द्र सरकार की परियोजना है, बहुत अच्छी है । डबल इंजन की सरकार है । धनबाद, हैदराबाद के लिए भी सड़क बनने वाली है । नागपुर रोड़ भी आरंग के पास, अभनपुर के पास विशाखापट्टम में जुड़ रही है, फिर वह आगे जाकर उड़ीसा वाले हाईवे में, सराईपाली वाली हाईवे में वह सड़क जाकर जुड़ रही है, लेकिन यह आंकड़ा है

कि सड़क में हैवी वाहन में 1 हजार प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि 25 साल में हुई है । लाईट व्हीकल में 3 हजार प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है । हम अभी कितनी सड़कें बना रहे हैं । भार क्षमता में 55 से 60 टन वाली वाहन छत्तीसगढ़ की सड़कों पर अब चल रहे हैं । मैं नहीं जानता कि कौन-कौन बोलेंगे, पर यदि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बोलेंगे तो इस बात को जरूर बोलें कि हमारी जो पीडब्ल्यूडी की स्टेट हाईवे हैं, वे कितनी भार क्षमता की बन रही हैं ? क्या हम इतना पैसा होने के बाद भी इसीलिए सड़कें बना रहे हैं ताकि वे दो साल में उखड़ जायें। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, माननीय श्याम बिहारी जी, आप इसको आलोचना के तौर पर मत लें, मेरा लक्ष्य किसी की आलोचना नहीं है। मैं सहज, सरल संवाद हो इसीलिए धोखे से उदाहरण दे दिया और मैंने शब्द वापस ले लिया। मैं किसी को एलीगेट नहीं करता, आप लोगों के मंगल भविष्य की कामना करता हूं। आप आगे चलकर नाम कमायें, देश का नाम रौशन करें, प्रदेश का नाम रौशन करें।

अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. ने एस.ओ.आर. बनाया। गवर्नेंस की क्या जरूरत है, मैं उसको बता देता हूं। फिर कौन सा एस.ओ. आर. लागू होगा ? नहीं इसमें पुराना वाला एस.ओ.आर. लागू होगा, उसको वापस करो। ठीक है, वापस हो गया। अब इसमें नया एस.ओ.आर. लागू होगा, फिर से नया बनकर आयेगा, ठीक है। उसके बाद भू-अर्जन में ज्यादा पैसा लग रहा है। अब यदि आप नई सड़क बनाओगे, 55 टन, 30 टन के लायक नई सड़क बनाओगे तो सड़क चौड़ी करनी पड़ेगी, भू-अर्जन तो करना पड़ेगा। फिर यह सब स्वीकृत हो गया तो अब फिर नहीं, इसको वापस करो। फर्नीचर का अलग टेण्डर होगा और सड़क का अलग टेण्डर होगा। बजट में वित्तीय उपलब्धता साल भर के लिए होती है। मैं बिलकुल नहीं कहता हूं कि आप तुरन्त प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दें, लेकिन आप प्रशासकीय स्वीकृति जारी करे, क्योंकि यदि गवर्नेस है तो एक चैक लिस्ट बन गई कि साहब, ये-ये ऐसी बनेगी, इतने टन का लागू होगा, इसको बनाकर दीजिये। एक कैलेण्डर बन गया। विभागों में बजट आने के 30 दिनों, 40 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें और 15 दिनों के भीतर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करें। वित्तीय स्थिति के बाद आपको टेण्डर लगाने की स्वीकृति दी जायेगी, यह गवर्नेंस होता है। किसने कहा कि साल भर के बजट को एक महीने में व्यय कर दें। लेकिन आज दिसम्बर महीना चल रहा है, अब तक वर्ष 2023-24 बजट की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है। वर्ष 2025-26 की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं होगी तो वर्ष 2026-27 और 2027-28 के बजट को चुनाव में नहीं देखेंगे। यह तीन साल का बजट है, जिसको हम लोग चुनाव में देखेंगे। ऐसा क्यों होता है ?

अध्यक्ष महोदय, एरीगेशन वर्किंग डिपार्टमेंट में तो पिछले एक साल तो टेण्डर ही नहीं खुला, नीचे का पूरा अमला खाली है। काम करने वाले लोग ही नहीं हैं। मैं एरीगेशन का उल्लेख कर दिया तो मैं सोचा था कि इसको कर लेंगे, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। यदि आप चाहे तो

छत्तीसगढ़ में जोरानाला, महानदी जल विवाद को उड़ीसा की सरकार के साथ मिलकर सुलझा सकते हैं। केन्द्र में हमारी सरकार है, आप इसको हल कर सकते हैं और इससे छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हित होगा।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ चार कछारों में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नर्मदा कछार में आपका इलाका आता है। पण्डरिया, जहां से भावना जी बैठी हैं, गृह मंत्री जी हैं, नर्मदा कछार में आता है। राम विचार जी बैठे हैं, वह गंगा कछार इलाके के हैं। अभी तो हमने नर्मदा कछार और गंगा कछार के बारे में सोचा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में जितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, अंग्रेजों के समय की थीं, सर्वे समाप्त हो गया, छत्तीसगढ़ में नया सर्वे नहीं हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में उस सर्वे की जरूरत है, जिसमें कन्जर्वेशन एक्ट मत आये, भूमि मत आये। लघु मध्यम सिंचाई योजनाएं, जो कंजरवेशन के लिए भी काम आयेगी, जल सरंक्षण के लिए भी काम आयेंगी, पेयजल के लिए भी काम आयेगी और सिंचाई के लिए भी काम आयेंगी। ऐसी योजनाओं को नये ढंग से लघु-मध्यम सिंचाई संभाग और उस तरह के काम अब छत्तीसगढ़ में बंद है, जबकि इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय :- करीब 50 मिनट हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कौन से स्वरूप में है, कैसा है, क्या बोलना है। मैं बंद कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप आखिरी 5 मिनट विजन में बोल लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5 मिनट में तो नहीं साहब, थोड़ी और देर बोल देता हूं। कुछ विषय को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्यटन में रोजगार की संभावनाओं का उल्लेख काफी किया। मैंने गवर्नेंस की बात कही। मुख्य सचिव साहब दीर्घा में मौजूद हैं। वरिष्ठ सचिव भी मौजूद हैं। किसी को एलीगेट करना मेरा बिलकुल भी विषय नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, श्याम बिहारी जायसवाल जी ने मेरे कान खड़े कर दिए, उन्होंने मजाक को भी सीरियस कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एक अधिकारी है, वह मेरा डी.एफ.ओ. रहा है। एम.डी. पर्यटन, एम.डी. संस्कृति, आई.एच.एम. का भी डायरेक्टर रहा है, पुरातत्व के भी डायरेक्टर हैं। कौन सा out standing perfromnaces है ? मैं आलोचना के लिए नहीं बोल रहा हूं। सिरपुर में 142 किले हैं, 5 साल में उसमें 52 से 53 नहीं हो पाये हैं। दो साल में पुरातत्व का एक लायसेंस लिया है। रीवा की खुदाई चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अश्वनी लोहानी जी दो बार छत्तीसगढ़ के एम.डी. पर्यटन रहे। उन्हें रेलवे बोर्ड का एम.डी. बनाया गया, जो रेलवे बोर्ड का सबसे बड़ा पद है। वे इंडियन एयरलाइंस के प्रबंध संचालक भी बने। अब उनका उल्लेख अचानक क्यों आ गया, यह भी बता देता हूं - उनका ससुराल जगदलपुर में है। आई.टी.सी. में एक दिन उन्होंने बुलाया था, उस समय मैं थोड़े दिनों के लिए पर्यटन मंत्री था। मैंने आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि मैं इस विभाग को नहीं करना चाहता, जबकि यह मेरा पसंदीदा विभाग है, फिर भी नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना

चाहता था, वह इतिहास की बात है। आज भी अगर मुझसे काम करने के लिए सबसे अच्छा विभाग चुनने को कहा जाए, तो वह सिर्फ पर्यटन और संस्कृति होगा। अब पर्यटन में आप स्थान बनाना चाहते हैं, तो क्या उसे पॉलिटिकल रखना चाहते हैं या प्रोफेशनल रखना चाहते हैं, यह एक नीतिगत निर्णय है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से है। संस्कृति पर बहुत भाषण दे चुका हूं, इन दस सालों में बहुत बोल चुका हूं। अब भाषण देने का मूड इसलिए नहीं होता कि आप करमा के क्षेत्र से आते हैं, मंत्री जी, करमा के क्षेत्र से ही आती हैं। एक आदमी को करमा सीखना हो तो कैसे सीखेगा? कितने स्टेप होते हैं, कैसी वेशभूषा होती है, कौन-कौन से वाद्य का इस्तेमाल होता है? शैला सीखना है तो कैसे सीखेगा? अभी गुरु घासीदास जी के लिए जो पंथी नृत्य होता है, वह सीखना हो तो कैसे सीखेगा? मैंने कहा एक अकादमी बनाइए। छोटा राज्य है, लोककला, फोक आर्ट, नाटक, नाचा - सबको एक साथ देखिए। आज इसकी कोई शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है। हम बड़ी-बड़ी अकादमियों की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की असली चीजों के लिए, जितनी विविधता छत्तीसगढ़ की संस्कृति में है, आप कहीं भी चले जाइए, वैसी कहीं और नहीं मिलेगी। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के खान-पान को एक अवधिया फैमिली को दिया था - बस्तर से लांदा, रामविचार जी के गांव तक की बीडिया, फेनी, पपची, ठेठरी, कुर्मी, जितने प्रकार की चीजें हैं, सबको और आई.टी.सी. ग्रुप से हमने बातचीत की थी कि इसकी कितनी कैलोरी है, क्या मान्यता है, कैसे बनता है - इस सबको भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणित करवाना है । अभी फरा सीजन चल रहा है। फरा कितने प्रकार से बनता है, बताइए तो सही। कहां हैं श्याम बिहारी जी? अभी लाखड़ीदार मिलाके बनही, चना भाजी मिलाके बनही, लाखड़ी बनाके भाजी मिलाके बनही - फरा। क्या आप एक इडली को दुनिया के मापदंड में ला सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा विजन में आइए । इडली, दोसा अब छोड़िए।

श्री अजय चन्द्राकर :- इडली दुनिया के मापदंड में आ सकती है। टुंडा कबाब दुनिया के मापदंड में आ सकता है, लखनऊ की एक गली में एक आदमी बनाता है। तो छत्तीसगढ़ के विविध व्यंजनों का मानकीकरण हम क्यों नहीं कर सकते? छत्तीसगढ़ का जो आई.एच.एम. बना है, वह इसमें काम क्यों नहीं कर सकता? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एकमात्र जगह है, एक चीफ सेक्रेटरी थे, आप सामने में मौजूद थे। आज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम छत्तीसगढ़ में 25 साल में आर्काइव नहीं बना पाए। जगह तय हो गई कि साहब, मुझे कहा गया यह नीर भवन आपको देंगे इस तारीख को ले लीजिएगा। आज छत्तीसगढ़ के बारे में किसी को शोध करना है, जानना है, आपने इतने अच्छे-अच्छे काम किए हैं, उसको कौन बताएगा? मध्य प्रदेश से हम ला नहीं सके। सी.पी. बरार से वह कागजात नहीं ला सके। छत्तीसगढ़ एकमात्र जगह है, जहां संग्रहालय में डायरेक्ट्रेट लगता है हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगता। यह उसी चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा था कि हम डायरेक्ट्रेट के लिए आपको जगह देते हैं, आज तक जगह नहीं मिली यह निर्णय हमको करना है। छत्तीसगढ़ में अभी तो डबल इंजन की

सरकार है। हम राष्ट्रीय संग्रहालय क्यों नहीं बना सकते। गुरु घासीदास का संग्रहालय देश का पांचवां सबसे पुराना संग्रहालय है। संभवत: क्षेत्रीय दो संग्रहालय बने जगदलपुर और अंबिकापुर है। बिलासपुर में हमारा कोई स्थान नहीं है, एक नई चीजें नहीं हुईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरपुर में आपने बनवाया। आज तक संग्रहालय उसका बन नहीं पाया। हमने पी.डब्ल्यू.डी. को 15 लाख रुपया दिये। भाई साहब, वापस। अब तक नहीं बना। क्या उसको वर्ल्ड हेरिटेज बनाएंगे। अभी दिवाली को विश्व विरासत की दर्जा मिला। शेखावत जी से बात करके बस्तर दशहरा के लिए दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। सिरपुर के लिए वह प्रयास कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि एक बार एक टीला को हटायेंगे, एक बार टीला को हटायेंगे, लेकिन 142 टीलों को खोद कर दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास लायेंगे। वह नालंदा के, वह तक्षशिला के, वह विक्रमशिला के समकालीन जगह है, लेकिन इतिहास के उस पुनर्लेखन की जरूरत है। उस काम को कौन करेगा? आपने राजभाषा परिषद बनायी। राजभाषा परिषद में आपने क्या काम किया है? 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी से पुराना 1890 का हमारा व्याकरण है। यह एशियाटिक सोसायटी में छपा और मुझे इस बात का गर्व है कि हीरालाल काव्योपाध्याय कुरूक्षेत्र के रहने वाले थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का व्याकरण लिखा। यह भूपेश बघेल जी का उल्लेख कर रहे थे, मैं उल्लेख कर रहा था कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया और उसके कोख से निकले एक विभाजनकारी बात करने वाला आदमी और वह हजार रूपये कढ़ाही का बासी खाना मतलब छत्तीसगढ़िया, जाकर सांकर लेना मतलब छत्तीसगढ़ी हो गया, यह इतना ही छत्तीसगढ़ है। आज छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाम पर सिर्फ गोबर ढो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, साहित्य परिषद बना दिया गया। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भूपेश बघेल जी ने संस्कृति परिषद निर्णय लिया। उस परिषद की पांच सालों में एक भी बैठक नहीं हुई।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह फ्लो में बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक शब्द के लिए क्षमा चाहूंगा, जिसको निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी गोबर ढो रहे हैं, इसको रिकॉर्ड से निकाल देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके निर्देशों का पालन करते हुए मैं थोड़ी अपनी बात को समेटता हूं। पर्यटन, संस्कृति, भाषा, लोक-व्यवहार आदि छत्तीसगढ़ में जितनी विविधताएं हैं, मैं किसी भी विद्वान से बहस के लिए तैयार हूं। आज हम आपके कक्ष में कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास का हर समकालीन दौर में जो योगदान है, उसको सोचने, समझने के लिए साहित्य में हो। अभी विनोद कुमार शुक्ला जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरस्कार मिला। उसमें क्या प्रयास है? सिर्फ भूपेश बघेल जी की तरह नारा है कि सांकर लेना है और बासी खाना है। फिर तो छत्तीसगढ़िया हो गया और पुन्नी नहाने के लिए जाना है। जैसे भूपेश बघेल जी 4 बजे नहाने जायेंगे, तभी हम लोग

पुन्नी नहाये हैं, नहीं तो हम लोग पुन्नी नहीं नहाये हैं। वह रहते तो और मजा आता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नये विषय जलवायु परिवर्तन पर बोलना चाहूंगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन में केदार जी हैं। केदार जी, आपने स्टेट प्लान बनाया है। जलवायु परिवत्रन के विषय में तुक है, उस स्टेट प्लान में छत्तीसगढ़ में कोई एक्जीक्युशन नहीं हो रहा है। आप नोट कर लीजिए, पता लगा लीजिए। हमेशा एक चर्चा होती है। आज माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में भी विषय आया कि 44 प्रतिशत जंगल है। हमको इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए कि यहां 44 प्रतिशत जंगल है। हमने जितनी जमीन खनन के लिए, दूसरे विषय में लीज दी है, जो उजड़े वन है, वह सब हमारे खाते में अभी भी वन भूमि है और हम 44 प्रतिशत जंगल बोलते हैं। उसको घटा दीजिए और बताईए कि क्या छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत जंगल है? हम लोगों को शासकीय भाषा छोड़ देनी चाहिए। जब तक हम लोग रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे, तब तक हम छत्तीसगढ़ का कल्याण नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी, आप पर्यावरण प्रदूषण देखते हैं। आज आप रायपुर को देखेंगे, आप ज्यादा दूर मत जाईये। रायपुर में खारून नदी से पानी सप्लाई होती है। खारून नदी का पानी पीने लायक है या नहीं है, आप उसको दिखवा लीजिये। अरपा नदी की क्या स्थिति है, आप उसको देख लीजिये। वायु प्रदूषण में राजस्थान में जहां से आंदोलन निकला, सारे आंदोलनकारी राजस्थान में एक दिन एकत्र हुए, वे बैठे कि इसी स्थान में हम स्वच्छ हवा के लिए मांग करेंगे कि स्वच्छ हवा हमारा मौलिक अधिकार है। आज संसद में संभवत: उसमें बहस होगी या सोमवार को बहस होगी। राहुल गांधी जी के प्रस्ताव को सरकार ने खुले दिल से स्वीकार कर लिया है कि हम प्रदूषण पर चर्चा करेंगे, यह देश के लिए current issues है। हम कितने गंभीर हैं? मेरे पास यह पूरा पेपर रखा है। समय की मर्यादा है। अब मैं शहरी निवेश में दो-चार लाईन बोल देता हूं, जिसको आपने स्पर्श नहीं किया या आपने किया होगा तो हो सकता है कि मैंने नहीं पढ़ा होगा। मैं राजस्व में बोल देता हूं। कुल 53 हजार प्रकरण लंबित हैं। राजस्व मण्डल में 20-25 साल के लगभग 3500 प्रकरण लंबित होंगे। मैंने एक बार और सुझाव दिया था कि एक पखवाड़ा सरकार मंत्रिगण विदेश चल दें, विधायक विदेश चल दें, माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रालय में बैठकर सारी पेंडिंग मामले को निपटा दें। मैं सोचता हूं पेंडिंग नहीं होगा, लेकिन यह पूरा पखवाड़ा राजस्व मामलों को निपटाने का है। छत्तीसगढ़ का आम आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित है और उसका कैम्प विशेष न्यायालय आज पेपर में है कि लोक अदालत का इतने अरब का समझौता हुआ, इतने सारे मामले निपटे, उसको एक एक्शन मोड में करे, सारे लोग जुटें और मैंने तो एक और सुझाव दिया था कि आप प्रोटोकॉल अफसर दूसरा रखते हैं, जिस दिन राजस्व न्यायालय लगेगा, कोई भी आदमी नायब तहसीलदार से लेकर संभाग आयुक्त तक कोई भी दौरे में नहीं जायेगा । छत्तीसगढ़ का आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वहीं होता है । आप कर सकते हैं तो एक सुझाव है, यह अच्छी बात है । मैंने इसीलिए कहा कि गवर्नेंस की जरूरत है । शहरों में अनियंत्रित बढ़ाव, अनियंत्रित कॉलोनी, जमीन की बढ़ती कीमत, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनकी पहुंच

से बाहर है, क्योंकि किफायती आवास की योजनायें, गृह निर्माण मंडल की जमीन, आज बिक नहीं रहे हैं । यह कितना परशेंट बिका है, मैं विधान सभा का उत्तर दिखा देता हूँ, उसके बाद योजनायें बन रही है । फायनेंस हो नहीं रहे हैं, लक्ष्य पूरे हो नहीं रहे हैं । पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 24 घण्टे पानी, अमृत मिशन फेल हो चुका है । स्मार्ट सिटी में रायपुर का अध्ययन करना चाहिये कि पांच सालों में करप्शन का क्या मॉडल होगा और हमको तो जॉच करवानी चाहिये ? आज भी पेपर में छपा है कि बूढ़ा तालाब दो संस्थानों पर्यटन मंडल और निगम के बीच में झूल रहा है । हम लोगों ने राजेश जी के साथ जॉच की है, इसमें कितने खर्च डबल-डबल हुये हैं, लेकिन चढ़ा एक है, देखते हैं । गुजरात मॉडल की बात होती है, रिवर फ्रंट सबसे पहले साबरमती रिवर फ्रंट के रूप में गुजरात में बना है । दुनिया की सबसे ऊँची 182 फीट की सबसे ऊँची मूर्ति, वहां मैं जब गया था तो 3000 करोड़ में से 1200-1400 करोड़ रूपये वसूल हो गये थे । मैं पिछले विधान सभा चुनाव में 3 दिनों के लिये केवड़िया विधान सभा में था । हमारे यहॉ राम भगवान की मूर्ति को बदलने की घोषणा है, पर्यटन में इसका उल्लेख नहीं कर पाया । चंदखुरी राम भगवान जैसे दिखता भी नहीं है । वह दो साल में बदल ही नहीं पा रहे हैं, यह विधान सभा की घोषणा है ।

श्री राजेश अग्रवाल :- वह मूर्ति इस सप्ताह आ जायेगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उदाहरण दिया कि एअरपोर्ट से रेल्वे स्टेशन जाओगे, आप उतनी लागत में नागपुर पहुंच जाओगे । पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिये तत्कालीन नगरीय विकास के विशेष सचिव थे, यहां से वह दिल्ली गये । अध्यक्ष महोदय, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की योजना बनवाई थी और कैबिनेट में रूट तय हुये । भूपेश बघेल जी ने क्या किया, यह हिन्दुस्तान का एक उदाहरण है कि उसमें चिकित्सालय को भी जोड़ दिया तथा जेनेरिक मेडिसिन की दुकान को भी जोड़ दिया । न पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, न हमर अस्पतपाल चला, न जेनेरिक मेडिकल स्टोर चला और न हमने उसको रद्द किया । ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहीं है तो वह छत्तीसगढ़ में है । आज इंडिगो की दुर्घटना के बाद लोग वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान में आज बुलेट ट्रेन होती तो स्थिति दूसरी होती । अध्यक्ष महोदय, हमने उर्जा पर बातचीत की है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, यह बहुत अच्छा है । सूर्य घर की बात हो रही है, यह बढ़िया है इसमें तेजी लायें । लेकिन एक लाईन लिखा है कि हम 10 शहरों में केबल वगैरह डालेंगे तो मैं इसमें एक छोटा सा लाईन बोल देता हूँ कि रायपुर शहर की राजधानी उसी से शुरूआत कर दें कि कब डालेंगे ? रायपुर से ही शुरूआत कर दें कि हम इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत ले रहे हैं । गुजरात में एक गांव को, जहॉ पर सूर्य भगवान का मंदिर है मांढ़ेरा, गुजरात ने इसे सौर उर्जा से संचालित गांव बना दिया । आप कहीं की एक गांव ले लें, माननीय डिप्टी सी.एम. आप कौन से गांव से आते हैं ...।

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- कवर्धा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कवर्धा को मॉडल बना दीजिए कि इसे सौर उर्जा से पूरी तरह संचालित किया जायेगा । टंकराम जी के बलौदाबाजार को बना दीजिए कि यह माढ़ेरा की तरह एक सिटी बनेगा । यदि पैसा नहीं है तो एक छोटा सा पायलेट प्रोजेक्ट लीजिए, लेकिन यह दिखे कि उसमें छत्तीसगढ़ बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है । आपका सिवरेज ट्रीटमेंट प्लॉण्ट कितनी जगह स्वीकृत है और कितनी जगह बने हैं, कितनी जगह शुरू हुये हैं । मुझे यहां इसलिये खड़ा होना पड़ रहा है कि आपकी व्यवस्था बड़ी जोरदार है ? यह पहला दिन है, अब धीरे-धीरे इसको सुधारेंगे । यहॉ पैर सीधा रखने की जगह नहीं है ।

(सभागृह की बैठक व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया गया)

अध्यक्ष महोदय, अब अमृत मिशन फेल, स्मार्ट सिटी की कोई उपलब्धि नहीं है, तत्कालीन महापौर जो दो थे, वह उसकी पॉकेट मनी थी । एक नये तरीके से नगर विन्यास को सोचने की जरूरत है । आपने पंचायत को छोड़ दिया, आपने समाज कल्याण को छोड़ दिया, महिला बाल विकास को छोड़ दिया। गरीबी उन्मूलन से सारी विचारधाराएं पैदा होती हैं। माननीय मोदी जी कह रहे हैं, SJSY की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट और एक उत्पाद हम ले लेते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए आप कांकेर से आते हैं, कांकेर में ग्रेनाईट बहुत है, वहां के स्व सहायता समूह को ग्रेनाईट के लिए दे दीजिए, बस्तर में सेल्फी का वेल्यू एडीशन करवा दें, किसी को पैकेजिंग के लिए दे दें, साहब, आईए स्वसहायता समूह को ट्रेनिंग दीजिए। जांजगीर जिला है, लखन लाल जी का क्षेत्र है, वहां टेक्सटाइल के लिए बात कर दीजिए, 5 मंदिर हैं, जिसको आप कारीडोर बनाना चाह रहे हैं, साहब, आप लोग रतनपुर, बिलाईगढ़ से आते हैं, वहां की चुनरी, वहां का माला, वहां की फूल, फूल के उत्पादन फ्लोरीकल्चर को हम देंगे तो बढ़िया है, स्वसहायता समूह के लिए एक दृष्टि से करिए। पेसा पर आपका दृष्टिकोण छपा है, पेसा पर आप लागू करेंगे तो 6वीं अनुसूची का क्या होगा ? उसको अध्ययन करने की जरूरत है, किस स्वरूप में कैसे पेसा लागू हो, क्योंकि बस्तर आंदोलित 6वीं अनुसूची पर भी होता है और उसी मुद्दे पर महेन्द्र कर्मा जी चुनाव जीत चुके हैं। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। इसलिए उसमें एक संवेदनशील विषय है। उसमें बड़ा अध्ययन और लागू करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस विजन में लॉ एंड आर्डर में बातचीत नहीं हुई। आप देखिए, जो भागीरथ संकल्प हुआ, 31 मार्च, 2026 को नक्सलमुक्त कर देंगे, उस संकल्प के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी सबको बधाई। लेकिन दूसरी ओर साइबर ठगी नये तरीके का अपराध है, डिजिटल अरेस्ट नये तरीके का अपराध है। नशे का कार्टेल नये तरीके का अपराध है। रोड एक्सीडेंट, मैं बोलता हूं ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हम ब्लैक स्पॉट को पूरा ठीक कर देंगे, दो साल में ब्लैक स्पाट पूरे ठीक नहीं हुए, एक दिन ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर में दो मरे, तीन मरे, समाचार नहीं होता, माननीय गडकरी

जी का पिछले हफ्ते ससंद में बयान था, हिन्दुस्तान में प्रतिदिन 485 आदमी रोड एक्सीडेंट से मरते हैं और छत्तीसगढ़ टॉप स्थान में है। नशा करने में छत्तीसगढ़ टॉप स्थान में है, इन नई चीजों में पुलिस का प्रशिक्षण, हम हर बात के लिए पुलिस को दोष नहीं दे सकते, गृह मंत्री को दोष नहीं दे सकते, पूरी दुनिया इससे पीड़ित है। नये तरीके के आतंकवाद, अब NIA की तरह SIA बनाना है, आपने SIA को क्या दिया है ? ये थोड़ा सा बता दीजिए। हमने SIA को कुछ अधिकार पॉवर नहीं दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ जो लोग हुए, मैं एक पेपर भर देख रहा हूं, फिर मैं बंद कर देता हूं। मुझे बोलना तो बहुत कुछ था। क्योंकि मैंने लगभग सभी पेज को टैग लगाया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए समाप्त करिए, 5-5 मिनट हो गया।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बस, एक कागज मिल जाए तो देख लेता हूं। लोक प्रशासन, (Hota Committee), माननीय वित्त मंत्री जी, आपने तो प्रशिक्षण में पढ़ा होगा, बहुत उच्च शिक्षित हैं, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण है। परफार्मेंस बेसिस नियुक्ति, परफार्मेंस बेसिस नियुक्ति नहीं है तो लोक प्रशासन असफल होगा। क्या हम छत्तीसगढ़ में इस तरह का कर रहे हैं ? सिंगापुर में मेरिट आधार पर नियुक्ति होती है और एक विषय पर विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है। उत्तरी यूरोप के जो नॉर्डिक देश हैं, नॉर्डिक देशों में एक-एक निर्णय की समीक्षा होती है, फाईल रहता है, साहब कौन निर्णय कितने दिन तक किस टेबल में लंबित थे और क्यों लंबित थे ? जानबूझकर लोकहित में देरी की गई तो उसमें कार्रवाई होती है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि लोक प्रशासन की दृष्टि से, हमारा प्रशासन आज आटोमोड में है, यदि कोई विधायक, यदि कोई सांसद फोन न करे तो फाईल आज स्वत: नहीं चलती। यदि हम फोन करते हैं, फॉलोअप करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी उसको बुरा मानती है कि साहब हम काम नहीं कर रहे हैं। आप बार-बार वही प्रश्न पूछते हैं। मेरे पत्रों के उत्तर देने की परंपरा समाप्त हो गई और ऑटो मोड में चलने लगी। जनहित के विषय में यह फाइल स्वत: चलकर आएगी, बिना अप्रोच के भी जनता का काम होता है, यह हम साबित नहीं कर पाये। जब देश-दुनिया में रिफॉर्म हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ कम से कम वह केन्द्र बने। कल मैं छत्तीसगढ़ के एक लड़के से मिला था। वह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का ही लड़का था। उसने मेरे चरण छुए। मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो तो वह बोला कि साहब, मेरा बैंगलोर में स्टार्टअप है। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है तो उसने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप के लिए उतना मुझे कोई ध्यान से सुना नहीं। वह बोला कि मेरा स्टार्टअप एशिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है। लखनलाल जी, यदि आप मिलेंगे तो मैं आपको उस लड़के से मिलवा दूंगा। नये विषय में ई-व्हिकल आया। आप 12 लाख में सब्सिडी दे रहे हैं। 12 लाख में कोई भी ई-व्हिकल नहीं आता है। अभी 100 करोड़ रूपये से ऊपर की सब्सिडी देना बाकी है। जो नये क्षेत्र हैं, प्रशासन के नये विषय हैं, उस पर हम लंबे-लंबे विषय सोच रहे हैं, वह बहुत स्वागतयोग्य है। लेकिन हमें छोटे-छोटे प्रयास करने होंगे। मैंने कहा कि आप बूंद में महासागर हैं। ऑर्गेनिक खेती जैसी सब चीजों में यदि किसी तरह

का बजट का अभाव है तो उसको पायलेट प्रोजेक्ट में शामिल कीजिए। यह तेजी से चलने वाली, निर्णय लेने वाली सरकार है। आपने सोचा, क्रियान्वित किया, जिससे भी सलाह ली, जिस तरह से सलाह ली तो छत्तीसगढ़ के लिए एक दृष्टिकोण दस्तावेज बना। माननीय विष्णुदेव साय जी के इस प्रयत्न का, वित्त मंत्री जी के इस प्रयत्न का, मंत्रिपरिषद के इस प्रयत्न का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी चर्चा में एक बात दु:खद हुई, जिसको अन्यथा लिया गया। मैंने ऐसे ही मजाक से कहा कि [xx][2] जैसे हैं, हम लोग निरंतर मिला करें, आप लिब्रल आदमी हैं। इसमें व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह का आक्षेप नहीं था। विधान सभा में यदि उसके लिए आपको बुरा लगा हो तो मैं विनम्रता से क्षमा चाहता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में निजी आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है। मैं उसको जानता हूं। मैं अपनी सरकार, अपने विधायक के ऊपर निजी आरोप नहीं लगाऊंगा। मेरे पास व्यक्तिगत जगह है और ओ.पी. चौधरी जी से मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं उनसे कोई बात न कर सकूं। मैं इतना अधिकार भी रखता हूं कि उनसे मजाक भी कर सकता हूं। उसको दूसरे ढंग से जो ट्विस्ट देने की कोशिश हुई, वह खेदजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, जो मैंने आपसे कही और जिस पर चर्चा की, यह उदाहरण बनेगा या नहीं बनेगा, किस तरह से होगा, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसका उत्तर आएगा कि यह मेरा एक वाणी विलास है या इस पर कोई कार्रवाई होगी या कोई उत्तर आएगा। इस दस्तावेज को सरकार ने स्वीकार किया है तो क्या इसके क्रियान्वयन का कोई रोड मैप है? क्योंकि टेबल तो बहुत सारी चीजें होती हैं, टेबल होने से सब टेबल के दस्तावेज में चर्चा हो, यह जरूरी नहीं है। यदि आपने चर्चा करवाई है तो यह बात माननीय वित्तमंत्री जी की तरफ से नहीं कही गई है कि इसको किसी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार कर लिया है। पहले बजट में हम बनाएंगे, यह शब्द आया था। एक उदाहरण बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि पिछली सरकार में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक लाइन छप गई कि यह घोषणा पत्र हम स्वीकार करते हैं और इसका अक्षरश: पालन करेंगे। शब्द ऊंचे-नीचे हो सकते हैं। हमने उसको 5 साल के लिए पकड़ लिया। आप उस विधान सभा में थे। आपने इसको स्वीकार कर लिया और यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आ गया, मतलब यह एक शासकीय दस्तावेज हो गया। इससे संबंधित उत्तर आपको देने पड़ेंगे। आप आजू-बाजू नहीं कर सकते हैं। आपने शराबबंदी कही है, बेरोजगारी भत्ता कही है, 14 साल की आयु तक की फ्री शिक्षा कही है तो इसके लिए क्या बजट है? वह इस बात से परेशान होते थे। इसलिए वह हमको ऐसे परेशान मत कर सके। यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि इसको हमने स्वीकार किया है और इसके लिए अल्पकालिक योजनाएं ये हैं और दीर्घकालिक योजनाएं ये हैं। आशा है कि यह गतिशील सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में और एक उच्च शिक्षित, उच्च प्रशिक्षित वित्त मंत्री, जिसके पास अपना विजन और दृष्टिकोण है, इसको रखेंगे। कभी और भी विषय चर्चा के आएंगे तो बाकी विषयों पर

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

हम बातचीत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी।

समय :

12.59 बजे **(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेंडी) पीठासीन हुई)**

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण व मार्गदर्शन में वित्तमंत्री जी के द्वारा विस्तृत रूप से इसमें चर्चा कराने के पश्चात जो विजन 2047 छत्तीसगढ़ अंजोर डॉक्यूमेंट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

समय :

1.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य के जो सपने हैं और वर्ष 2047 में हम कैसा छत्तीसगढ़ चाहते हैं, छत्तीसगढ़ अभी कहां पर खड़ा हुआ है, उसको लेकर स्कूलों में, कॉलेजों में अनेक संस्थाओं में और उसके साथ ही विस्तृत रूप से उसमें चर्चा कराने के पश्चात आज विधान सभा में इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तावना में विस्तार से बातें रखी गयी हैं और सभी विषयों पर इसको प्रस्तावित किया गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ 2047 कैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विस्तार से जानकारी तो नहीं है लेकिन जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 का विजन पार्लियामेंट में रखा गया और उसके बाद यदि किसी प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए यह सोचा है कि हम छत्तीगसढ़ को 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ बनायेंगे तो मुझे लगता है कि यदि दो-तीन प्रदेशों की बात करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ भी उस एक प्रदेश में शामिल है जो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 का समर्थन करते हुए इस विकसित छत्तीसगढ़ की रूप रेखा रखने का प्रयास इस छत्तीसगढ़ के विधान सभा के माध्यम से यहां पर प्रस्तावित किया गया है। अभी हमारे वित्तमंत्री जी के बाद अजय चन्द्राकर जी, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके द्वारा इस पर विस्तार से चर्चा की गयी है और हमारे विभागों के जो मंत्री हैं, वह भी अपनी बात रखेंगे, हमारे विधायक साथी भी अपनी बात रखेंगे इसलिये मुझे बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी एक पृष्ठभूमि आ गयी है कि वर्ष 2047 में जब हमारा भारत, विकसित भारत बनेगा तो हमारे छत्तीसगढ़ का दृष्टिकोण क्या होगा और किस-किस दिशा में हम वर्ष 2047 में इसको ले जाकर रख पायेंगे। यहां पर एक संपूर्ण दस्तावेज रखने का काम किया गया है। मैं सबसे पहले हमारे कृषि विभाग के विषय पर जाना चाहता हूं। मैं आज भी

कह सकता हूं कि हमारा जो कृषि है, उसमें हम चाहे भारत की बात करें या हम छत्तीसगढ़ की बात करें, सबसे ज्यादा जीवकोपार्जन..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदया, मैंने अपनी बातचीज में एक लाइन कही थी और मेरा आग्रह है कि उसको विलोपित कर दिया जाये। वह यह है कि मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के लिये एक शब्द उपयोग किया था कि [XX][3] ऐसा शब्द आया था। उसमें माननीय जायसवाल जी ने आपत्ति भी ली और मैं भी इस बात से सहमत हूं और मेरा आग्रह है कि उस वाक्यांश को विलोपित किया जाये।

श्री धरमलाल कौशिक :- वैसे यह असंसदीय नहीं है।

सभापति महोदया :- माननीय सदस्य के अनुरोध को मानकर विलोपित किया जाता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, हमारे देश में लोगों की सबसे ज्यादा निर्भरता कृषि में है। हमारे लगभग 60 प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मूल जीवकोपार्जन का साधन भी कृषि है। कृषि को लेकर जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है कि आने वाले समय में उन्नत कृषि कैसे हो, हमारा उत्पादन कैसे बढ़े और उसकी लागत क्षमता कैसे कम आये जिससे हमारी कृषि एक आमदनी का जरिया बन सके और उसके लिये सरकार के द्वारा लगातार उस दिशा में काम किया जा रहा है। उसमें खासकर जो हमारे लगातार रिसर्च हो रहे हैं, उन्नत बीज की बात आ रही है, ज्यादा यील्ड लेने की बात आ रही है। उसके साथ ही साथ में कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण, हम केवल अनाज के उत्पादन की बात करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अनाज के उत्पादन में जो हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है, खाने के लिये ही नहीं बल्कि हम दूसरी जगह भी अनाज की सप्लाई करते हैं। लेकिन जब दलहन और तिलहन की बात आती है, आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में हम दलहन और तिलहन में दूसरे के ऊपर आश्रित हैं और उस दिशा में लगातार प्रयास करने के बाद भी उसमें हमारी आत्मनिर्भरता में कमी है, हम दूसरे के ऊपर में अभी भी निर्भर बने हुए हैं। इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इतने प्रयास होने के बाद में आखिर क्या कारण है कि हम उस दिशा में अभी भी आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। इसमें इस विजन डॉक्यूमेंट में दिया गया है कि हमारी जो जलवायु की स्थिति है, हमारे सरगुजा की उत्तर की पहाडियों की हम बात करते हैं जिसकी जलवायु अलग है। बस्तर छोड़ करके हमारा जो पूरा मध्य क्षेत्र है, उसकी हमारी जलवायु अलग है। हमारे बस्तर की जलवायु अलग है। इसलिये आप देखेंगे कि अनाज के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ाने वाला क्षेत्र मध्य क्षेत्र है। लेकिन क्या हम सरगुजा के लिये अलग विचार कर सकते हैं कि सरगुजा में हमारी कौन सी क्राप होगी ? क्या हम बस्तर के लिये अलग से विचार कर सकते हैं? बस्तर के लिये अलग से विचार करके

[XX][3] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

हम उस दृष्टिकोण से वहां के किसानों को हम उस दिशा में ले जाने का प्रयास करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आज भी हम सिंचाई की बात करेंगे तो हमारी 40 प्रतिशत से कम सिंचाई की क्षमता है जिसके ऊपर हम निर्भर हैं। ये बात अलग है कि अन्य प्रदेशों से लगभग 6 प्रतिशत वर्षा हमारे यहां ज्यादा होती है। इसलिए हम उस प्रकार से फसल ले सकते हैं। लेकिन लगातार इस दिशा में जो काम करने की आवश्यकता है, मैं जल सरंक्षण की बात करना चाहता हूं। मैंने पिछली बार अनुभव किया है कि हमारी जो महानदी है जिससे हम शहरों में पीने का पानी ले जाते हैं और पिछली बार हमारी महानदी सूख गई। महानदी का सूख जाना अपने आप में ये बडी बात है कि प्रदेश का वाटर लेवल क्या है? जल सरंक्षण के क्षेत्र में वाटर लेवल बढ़ाने के लिये हमको क्या करने की आवश्यकता है। हमारा वर्षा जल आ रहा है और आने के बाद में वर्षा जल निकल जा रहा है। हम उसको कितने प्रतिशत संरक्षित कर पा रहे हैं? हम उसको कितना रोक पा रहे हैं और उसको रोकने के लिये हमारा उस दिशा में क्या प्रयास है? शहरों में भी जो पानी की समस्या है, हमारी बड़ी-बड़ी कालोनियां बन रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी कालोनियां बनने के बाद हम वाटर रिचार्ज का कितना काम करा पा रहे हैं। हम एन.ओ.सी. जारी करते समय, लाइसेंस देते समय हम ये बता तो रहे हैं कि वाटर रिचार्ज करने के लिये हमारे ये उपाय होने चाहिए, लेकिन उसकी मानीटरिंग कितनी हो रही है? इसके कारण में हम देख रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है और वाटर लेवल नीचे जाने के कारण में खेती की सिंचाई की बात तो अलग है, पीने के पानी की दिक्कत गर्मी में आ रही है। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा है और इस समय भी हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हमको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में हमको और आगे बढ़ने की आवश्यकता है और आगे बढ़कर के हमको उस पर काम करने की आवश्यकता है। यदि उसमें और बजट बढ़ाने की आवश्यकता हो तो हमारा बजट बढ़ना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि यहां पर हम जो उद्योग लगा रहे हैं, चाहे हम उद्योग के लिये पानी की बात करें, जहां नदी की व्यवस्था है, नदी से पानी तो लेकर आ रहे रहे हैं, लेकिन हमार जो अंडरग्राउण्ड वाटर है । यह हम उद्योग में उपयोग कर रहे हैं और उद्योग में उपयोग करने के बाद अभी हमारी जो लगातार स्थिति बन रही है और हमको वॉटर लेवल में इसका जो फर्क दिखायी दे रहा है, हम उसके लिये क्या करना चाहते हैं ? इस दिशा में हमको विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी । इसके साथ ही साथ हम लोग कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी, यदि हम सकल घरेलू उत्पाद में बात करें कि हमारी क्षमता क्या है तो 20 प्रतिशत से ज्यादा योगदान नहीं है इसका मतलब यह है कि अभी हमारे पास संभावना बहुत है और उस संभावना के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र में हम और मजबूत होने की स्थिति में हैं, हम और मजबूत होकर काम करने की स्थिति में हैं ।

माननीय सभापति महोदय, आज हम उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो हमारा जो योगदान सबसे ज्यादा यदि किसी सेक्टर में है तो हमारा उद्योग के क्षेत्र में है और उद्योग के क्षेत्र में है तो आज भी उसमें हमारी जो संभावना बनी हुई है लेकिन मैं उस दिशा में बात करना चाहता हूं कि आखिर गांव में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो किसान उसका विरोध क्यों करना चाहते हैं ? वह क्यों चाहते हैं कि हमारे यहां उद्योग न लगे ? अभी मेरे पास हमारे कुछ किसान लोग खैरागढ़ से चलकर आये थे, कोई उद्योग लगने वाले हैं । उसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां पर उद्योग लगे हैं और लोग उसका जो पॉलुशन देख रहे हैं और पॉलुशन देखने के बाद लोगों को लगता है कि हमारे यहां उद्योग नहीं चाहिए जबकि खेती के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने की स्थिति यदि किसी सेक्टर में है तो उद्योग के सेक्टर में है । जहां हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं और रोजगार देकर हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको हम काम दे सकते हैं लेकिन उसके बाद भी उसका जो विरोध होता है इस दिशा में कहां पर हमारी कमी है, इन कमियों को हम कैसे ठीक करेंगे ? लोग उसका विरोध करना बंद कैसे करेंगे ? लोग उसकी तरफ कब आकर्षित होंगे ? हमें इन सारी बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है और न केवल चर्चा करने की बल्कि उसका रास्ता निकालने की आवश्यकता है कि लोग आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस क्षेत्र में जिस प्रकार से काम करने की जरूरत है, निश्चित रूप से उस दिशा में कहीं न कहीं हम पीछे हैं और इसके कारण हमको जो सुविधाएं जनता को देनी चाहिए । उद्योगों से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, हम उन अपेक्षाओं को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? इसमें मुख्य रूप से एक बात आती है कि फैक्ट्री लग जाती है, लगने के बाद में अक्सर बाहर के लोग आकर काम करते हैं और स्थानीय लोगों को यह लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है तो क्या हम केवल प्रदूषण झेलने के लिये हैं ? इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी आती है और इसलिये मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम जब उद्योग की बात करते हैं, हम जब कौशल उन्नयन की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में जिस सेक्टर में कौन-कौन से उद्योग आ रहे हैं । क्या उस उद्योग के लिये, कौशल उन्नयन के लिये हमारे पास, क्या हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तो अधिकाधिक हम संस्थाएं खोलकर कि उनके यहां जो टेक्निकल आवश्यकता है । उसके अनुरूप उनका कौशल उन्नयन हो सके, उसी दृष्टिकोण से उनका एजुकेशन हो सके और उसी दृष्टिकोण से हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर सकें ताकि वहां के जो हमारे प्रदेश के लोग हैं और स्थानीय लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उस उद्योग में हम उनको काम दे सकें और काम देकर के हम उनको आगे बढ़ा सकें तो मुझे लगता है कि हमारे कौशल उन्नयन और शिक्षा के क्षेत्र में यह मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है और मूलभूत परिवर्तन करके उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है कि जहां पर जाकर हम इन कामों को व्यवस्थित तरीके से कर सकें । इसमें जो आया है कि हमको जो आगे बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिये कुछ दृष्टिकोण से हम जब उद्योग की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के ऊपर भगवान की

जो कृपा है कि पानी की कमी नहीं है । सबसे सस्ता श्रम संपदा छत्तीसगढ़ में है, वन संपदा हमारे खनिज का अथाह भंडार, हमारे यहां पर बिजली और इस प्रकार से एक जो उद्योग लगाने के लिए आवश्यकताएं हैं, छत्तीसगढ़ में वह सारी चीजें बहुतायत में हैं उसके बाद भी हमें उस सेक्टर में जहां पहुंचना चाहिए, उसका जो उपयोग होना चाहिए, इसे निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, आप जानती हैं। पूरे देश में कोल के सेक्टर में हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे । पूरे देश में कोल के सेक्टर में हमारे सामने छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा योगदान है । हमारे यहां हम स्टील क्षेत्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम बाकी प्रदेशों से तुलना करेंगे तो स्टील के क्षेत्र में हम भारत को एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। अभी यहां पर जो चर्चा आयी थी कि हमारे यहां की क्वालिटी अच्छी है जो विमान में लग रहे हैं जो सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज है वहां पर लगा हुआ है। उसके साथ में देश में जो अनेक निर्माण कार्य हैं उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के खासकर भिलाई के स्टील की बात करें, हम नगरनार की बात करें, हम Allance sectors की बात करें, हम स्पंज आयरन की बात करें, हम रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर की बात करते हैं। जिस सेक्टर में हमारा औद्योगिकरण हुआ है हम उस सेक्टर में उद्योगों के माध्यम से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ में हमको जो एक बड़ी आवश्यकता है, वह मूल्य संवर्धन और क्षमताओं में बढ़ोत्तरी हो। हम अपने प्रतिशत को देखेंगे कि देश की उत्पादन क्षमता में स्टील क्षेत्र 14 प्रतिशत का योगदान देता है, लेकिन जब हम finished स्टील की बात करते हैं तो उसमें हमारी कितनी हिस्सेदारी है? हमारे छत्तीसगढ़ की 2.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यदि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं तो हमें उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। कच्चे काम के बजाए हम उनको यहां से बनाकर, भेजेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विस्तार भी होगा, हमारी आय भी बढ़ेगी, यहां के लोगों को काम भी मिलेगा। हमको उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। दूसरा, जो हमारी निर्यात क्षमता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ औद्योगिक संरचना का विस्तार हो। यहां हमारे औद्यौगिक पार्क कितने बने हुए हैं? हमें आगे कितने औद्यौगिक पार्क बनाने की आवश्यकता है। उसके साथ में हमारे प्लग एण्ड प्लेन सुविधाओं का विस्तार हो। इसके साथ ही निवेश के लिए हमारी एक आकर्षक योजना हो। दूसरे प्रदेश के लोग या देश के बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में उद्योग के क्षेत्र में इंवेस्टमेंट करने के लिए आयें। हमारी जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं को पूरा करने के लिए जो प्रयास किये हैं, यह लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है कि यहां पर लोग निवेश करने के लिए तैयार हुए हैं। यहां पर उन्होंने न केवल हस्ताक्षर किया है, बल्कि यहां पर काम करना भी शुरू कर दिया है। यह छत्तीसगढ़ के आने वाले समय के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है कि हम उद्योगों के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं कनेक्टिविटी में सुधार पर कहना चाहूंगा। यदि हम यहां उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो। चाहे हम रेल की बात करें, हम सड़क यातायात की बात करें जो हमें सस्ते में उपलब्ध हो। हम आसानी के साथ दूसरे प्रदेशों में भेज सकें और वहां हम सप्लाई कर सकें। जहां पर भी कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से वहां पर व्यापार बढ़ेगा। वहां लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो यहां लोग निवेश करने आएंगे। उसका रेट भी कम होगा और हम कम रेट में ज्यादा earning कैसे कर सकते हैं ? साथ ही मैंने जो प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन की बात की, यहां पर पर्यावरण और तकनीकी पहल हो। आखिर हमारे यहां पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो प्रभावित हो रहे हैं, उसको हम कैसे बचा सकें। उसके लिए भी जो हरित ऊर्जा की बात आयी है, नवीनीकरण ऊर्जा के निर्माण की जो बात आयी है निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। यहां के हमारे जो उद्योग हैं, वह फलेंगे, फूलेंगे और जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हम आज जिस स्थिति में खड़े हुए हैं। जब हम छत्तीसगढ़ विजन 2047 की बात करते हैं। इस क्षेत्र में 2047 में हमारी क्या स्थिति बनेगी ? हमें 2047 में जाने के लिए, उस क्षेत्र में क्या-क्या काम करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इस पर हम जो देख रहे हैं कि बिना प्रदूषण के किस-किस सेक्टर में अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है । हम छत्तीसगढ़ राज्य आटोमोटिव इलेक्ट्रानिक्स की बात करते हैं । सेमी कंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जो उद्योग में न केवल स्पंज आयरन, कोयले के सेक्टर हैं, उसके अलावा भी नये सेक्टर में हमें जाकर काम करने की आवश्यकता है । हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे हुए हैं, उस सेक्टर में हम जाएंगे तो लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेंगे । एक अच्छी बात यह है कि 2024 की नई उद्योग नीति में आप कितना पैसा लगाएंगे, वह सेकेण्डरी है, पर उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, यह हमारी प्रायरिटी है और उसके अनुसार से हमारी सब्सिडी और उसके अनुसार से हम बाकी सुविधाएं देंगे तो निश्चित रूप से लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा क्योंकि जो उद्योग लगाने के लिए आएंगे, वह यह सोचकर आएंगे कि उस दिशा में मैं काम करूंगा तो सरकार की जो फैसिलिटी है, वह ज्यादा से ज्यादा उस उद्योग को प्राप्त होगी । इसके साथ ही साथ जो हमारी नई संभावनाएं हैं, आजकल हम टेक्सटाईल्स की बात करते हैं, हम नया रायपुर में टेक्सटाईल्स की बात कर रहे हैं । वास्तव में यदि छत्तीसगढ़ में देखा जाये तो मुझे लगता है कि पुराने समय में जो हमारे स्पिनिंग मिल थे, हम चाहें राजनांदगांव की बात करें या हम बिलासपुर की बात करें, उसके बाद में टेक्सटाईल्स के काम लगभग बंद हो गए । उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अभी जो अवसर दिखाई दे रहे हैं और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है । केवल सामान्य कपड़े की बात नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में जो जैकेट बनाने का काम है, वर्दी बनाने का काम है, जो चमड़े उद्योग के काम हैं, उसके साथ में रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पादन में एक नई संभावना हमारे सामने में है, जो अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं । यदि उस सेक्टर में हम जाएंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में

उद्योग के क्षेत्र में एक नए कान्सेप्ट के साथ हम लोग बढ़ेंगे और उस क्षेत्र में हमको आने वाले समय में जो हमारी संभावनाएं दिख रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार दिला सकते हैं और 2047 के दृष्टिकोण से हम लोगों ने बात रखी है । जो लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक राज्य के सकल मूल्य वर्धिक जीवीए 25 से 28 लाख करोड़ रूपए तक हम विस्तार कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 2024 से 10 गुना अधिक होगी और इस प्रकार से उस दिशा में हम अपने उत्पादन क्षमता में वृद्धि और साथ ही हमारे नीतियों के माध्यम से इस उद्योगीकरण की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं । इसमें डिजीटल रूपांतकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, एलओटी, आईओटी और उसके साथ में हमारे डिजीटल पीस का हम उपयोग करके हम उस दिशा में कितना आगे बढ़ सकते हैं । इसके साथ में आपूर्ति चैन, हमारी आपूर्ति की जो श्रृंखला है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है । इसी के साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हम नये विजन के साथ में इस प्रदेश को औद्योगीकरण की दृष्टि से आगे ले जाकर एक अच्छा कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का हम प्रयास कर सकते हैं ।

सभापति जी, हम अभी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित है, हमारे यहां के पर्वत, पहाड़, वृक्ष, लुभाने वाले धार्मिक स्थल, अध्यात्म के स्थल, झरना, ऐसे स्त्रोत हैं, हम कुटुमसर गुफा की बात करें, हम चित्रकोट फाल की बात करें और इसके साथ में हमारे जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ की बात करें, हम अंबिकापुर के मैनपाट की बात करें, ऐसे हमारे यहां पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, जहां पर काम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च, 2026 तक नक्सल मुक्त करने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने के बाद यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र बस्तर है, जहां पर बड़े-बड़े इण्डस्ट्री से लेकर वहां बड़े-बड़े अनेक स्थान हैं, जिसे हमें पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षण वैसे भी बना हुआ है, हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। चाहे वह देश में हो या देश के बाहर हो, हमारा छत्तसीगढ़ पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ को पर्यटन का क्षेत्र बनाने के लिए लोगों को सुविधाएं चाहिए। सुविधाओं में हमारी सड़कें कैसी हैं, हमारी एयर कनेक्टिविटी कैसी है, रेल की सुविधाएं कैसी हैं, यदि हम किसी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं तो वहां रूकने की क्या व्यवस्था है, हम पर्यटकों को कितनी सुविधाएं दे सकते हैं, हम वहां थोड़ा काम करके कैसे उस क्षेत्र को सुन्दर बना सकते हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता है। बस्तर वैसे भी प्राकृतिक रूप से बहुत सुन्दर है, जो लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। यदि हम उस दिशा में थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ायेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा एक बहुत ही बड़ा सेक्टर इस छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्यटन का क्षेत्र होगा, टूरिज्म का क्षेत्र होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारा मैनपाट का क्षेत्र बहुत सुन्दर है। वहां उल्टा पानी है। अभी दिल्ली से मंत्री लोग आये थे। जब हमने उन्हें बताया कि वहां पानी उल्टा बह रहा है तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। हम उनको दिखाने के लिए वहां ले गये। वहां केवल पानी ही नहीं गाड़ी को भी उल्टा चलता हुए देखे, गाड़ी उल्टी दिशा में चल रही है। इस पर उन लोगों ने कहा कि इस पर शोध कराना चाहिए कि इसका कारण क्या है, इसका बहाव उल्टी दिशा में कैसे हो रहा है ? यह शोध का विषय है। यह हमारे आकर्षण का केन्द्र है। ऐसे बहुत सारे स्थान, जो हमारे धर्म, अध्यात्म और पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। अभी सर्किल बनाने की बात आई है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से लेकर रतनपुर, बस्तर के दंतेश्वरी से लेकर जांजगीर का चन्द्रपुर है, चन्द्रपुर से लेकर अम्बिकापुर है, यहां 5 माआतों का केन्द्र है, सर्किल बनाने की बात आई है। यदि हम इसको बनायेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, वहां लोगों को सुविधाएं मिलेंगी।

माननीय सभापति महोदय, यदि आज हम पर्यटन की दृष्टिकोण से बात करेंगे और सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का प्रतिशत निकालेंगे तो वर्ष 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत है। आप देखें कि हम कहां पर खड़े हुए हैं ? इसीलिए मैंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में यहां अपार संभावनाएं हैं। हम पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। यदि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसी हिन्दुस्तान में कई ऐसे प्रदेश हैं या हिन्दुस्तान के बाहर देश हैं, जिनका 50 प्रतिशत आय का साधन वहां का पर्यटन है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में पर्यटन 1.7 प्रतिशत है। हम उस प्रतिशत को बढ़ायें। अभी हमारे राज्य में अच्छा पर्यटन का क्षेत्र होते हुए भी हम सीमित क्षेत्र में हैं, हमारे पास उसको बढ़ाने की गुंजाइश है, उस दिशा में काम करने की जरूरत है, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, जिसके कारण यहां छत्तीसगढ़ में हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे यहां कई पर्यटन क्षेत्रों में आनलाईन बुकिंग हो रही है। हम इसे केवल अपने देश तक सीमित ना रखें, बल्कि हम इसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक कैसे स्थापित कर सकते हैं, हम पर्यटकों को इसके बारे में विस्तार से कैसे जानकारी दे सकते हैं, इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार आनलाईन के माध्यम से कर सकते हैं। हम दिशा में जितना अधिक काम करेंगे, निश्चित रूप से इसका लाभ पर्यटन के क्षेत्र में मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जब हम बात करते हैं, जिस बात को अजय चन्द्राकर जी ने रखा है, उस दिशा में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

समय :
1.30 बजे

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझती हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

छत्तीसगढ़ विजन 2027 पर चर्चा (क्रमश:)

श्री धरमलाल कौशिक :- गुड गवर्नेंस, छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के द्वारा और हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि हमारी जो शासन प्रणाली है, उसमें पारदर्शिता कितनी आए, काम पारदर्शिता के साथ में कैसे हो। उस दिशा में उनके विभाग में भी उनके कार्यालय में भी यह जो प्रयास शुरू हुए हैं, आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। बहुत सारी बातों का उल्लेख हुआ, हम बजट तो ला रहे हैं, लेकिन बजट के बाद में उसका परिणाम क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। बजट के बाद में उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं न कहीं हमारी वहां पर लीकेज है। उस लीकेज को यदि हमको रोकना है तो प्रशासन में पारदर्शिता आवश्यक है, सरकार में आवश्यक है। हमारी जितनी पारदर्शिता आएगी, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए न केवल मैं सरकार की बात करूं, न केवल मैं विभाग की बात करूं, बल्कि हमारे गुड गवर्नेंस की मैं बात करता हूं। हमको सबको जवाबदारी मिली है। मैं विधायक हूं, मेरे को भी अपने क्षेत्र में काम करने की जवाबदारी है । मंत्री हैं, उनको अपने विभाग में काम करने की जवाबदारी है। मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में काम करने की उनकी जवाबदारी है। हमारे एक कलेक्टर बैठे हुए हैं तो कलेक्टर को भी अपने जिला में वहां का प्रशासन कैसे चल रहा है, नीचे की इकाई कैसे काम कर रही है, यदि हमारे विभाग में सचिव बैठे हुए हैं तो उनके विभाग के अंदर में कैसे कार्यवाही हो रही है। आजकल हम देखते हैं कि लगातार हम लोग विधान सभा में जो प्रश्न उठाते हैं और प्रश्न उठा कर जब बात करते हैं कि यह जो पारित हुए हैं, पास होने के बाद में आखिर इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? हमारे यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुए। पूर्णता कब हो जानी चाहिए थी, पूर्णता क्यों नहीं हो पा रही है? तो कहीं न कहीं जो उसकी कमी और खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि यहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना बनी कि हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचनी चाहिए और उनके यहां पानी उनको मिलनी

चाहिए। योजना बन गई, योजना बनने के बाद में शुरुआत में क्या हुआ, आपकी जानकारी में है । उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। आज भी वह हमारी योजना पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? आपने तो उसमें बजट रखने के बाद में उसको टेंडर भी दिये होंगे । टेंडर के बाद में आपने काम भी दिया और काम देने के बाद में खुदाई भी हो गयी। आपका टोटी भी लग गयी और टोटी लगने के बाद में जब पानी पहुंचनी चाहिए तो आज पानी नहीं पहुंच है पा रही है, इसलिए ये सारी पारदर्शिता की मैंने बात कही है।

श्री राजेश मूणत :- आप पानी तक क्यों सीमित हो? उसमें तो कुछ नहीं पहुंचा। वह टंकी बनी ही नहीं है। लाइन बिछ गई है और जब लाइन बिछ गई है तो पानी नहीं है और यह किया किसने? कोई राजनेताओं ने नहीं किया, वह सब अधिकारी मजे में हैं, जो करके गए हैं। उनका विजन ठीक करो।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त करना। हम जहां पर खड़े हुए हैं, उससे आगे बढ़ना और अभी तक जो हुए हैं, मैं बहुत दोहराना नहीं चाहता।

श्री राजेश मूणत :- माननीय राम विचार जी बोल रहे हैं, वह कमी ऐसी है कि वह दूर हो ही नहीं सकती नहीं। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, उसको दूर तो करना पड़ेगा। यदि आप दूर नहीं करेंगे तो 2047 विजन डॉक्यूमेंट हमारा कोई काम का नहीं है। यदि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा और हमको अडॉप्ट करके आगे चलना पड़ेगा। इसी लाइन में हमको काम करना पड़ेगा, ठीक करने की लाइन में काम करना पड़ेगा। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी का ध्येय तो अलग था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिनके हाथ में बागडोर थी, उन्होंने उसको गलत दिशा में ले गया और अपने जवाबदारी से बचने के लिए उसका विकेन्द्रीकरण कर दिया। विकेन्द्रीकरण करने के बाद में उन्होंने जिले को सौंप दिया कि जिला वाले जाने और जिले के हाथ में आया तो उसका हश्र आज पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है। इसलिए इसको इस दिशा में आगे काम करने की आवश्यकता है। यह बजट का विषय तो नहीं है। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं फिर इस बात को बोलना चाहता हूं कि आपने सड़क के लिए एक सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद में आपने उसका बजट तय किया। बजट तय करने के बाद में आपने उसका प्रशासकीय स्वीकृति दिया। प्रशासकीय स्वीकृति के बाद में आपने उसका टेण्डर लगाया और टेण्डर लगाने के बाद में पता लगा कि वह 15 प्रतिशत बिलों में गया। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि उस सड़क की क्वालिटी क्या है? आपने उसकी जो प्रशासकीय स्वीकृति दी और जो टेण्डर दिया, उस बीच में सड़क की गुणवत्ता कहां पर है? हम लोग सड़क बनाते हैं, उसके बाद में फिर पत्र लिखना शुरू करते हैं कि साहब उसको Renewal करा दो। पांच साल में उसका मरम्मत और बाकी सब कुछ करना चाहिए। मेरा कहने का आशय केवल यह है कि जब हम वर्ष 2047 की बात करते

हैं तो हमको उस दिशा में आने वाले समय में हमारी काम ऐसी होनी चाहिए कि हम जो एक काम किए हैं तो वह दिखनी चाहिए।

सभापति महोदया :- कौशिक जी, 40 मिनट हो गये हैं। आप थोड़ा जल्दी खतम करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, मैं कुछ बातों को रखकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्योंकि एक्चुअल में इधर सामने में कोई नहीं है। हमारे सभी सदस्यों को बोलना है।

श्री राजेश मूणत :- उनका कोई विज़न ही नहीं है तो यहां रहकर क्या करेंगे? उनका सिर्फ एक ही चीज में विज़न रहता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री जी को पुन: धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां बहुत अच्छा प्रारूप रखा है और उसी के ऊपर में चर्चा है। उसके बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, जिस बात को हम लोग रख रहे हैं और वर्तमान में जो कमियां है, उसके साथ में एड करके आगे चलने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे बहुत सारे विभागों में चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि माननीय अजय चन्द्राकर जी ने चर्चा की है। लेकिन खासकर जिन-जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को अभी आगे काम करने की जरूरत है, मैंने उन क्षेत्रों की बात प्रारंभ की है। आपने कहा कि 40 मिनट हो गये। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह कहना है कि कुल मिलाकर जब हम 2047 की बात करते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ 2047 में कैसे हो? उस दिशा में हम सभी लोग बात कर रहे हैं तो हमारी जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना, नये सिरे से उस दिशा में जाना, नई सोच के साथ हमको आगे बढ़ना और उसके साथ-साथ हम उस दिशा में अपना काम सुनिश्चित करें। जहां तक हमारे फारेस्ट की बात है, पंचायत की बात है, हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जिसमें बातचीत करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन को लेकर जो बात है, हमारे होम डिपार्टमेंट की बात है, इन बहुत सारे सेक्टरों में बात करने की आवश्यकता है कि अभी भी हम उसको और कैसे ठीक कर सकते हैं? हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कुल मिलाकर लोगों का विश्वास जीतना। हमने वर्ष 2023 के विधान सभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास जीता, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में हमने लोगों को जो विश्वास दिलाया है, उस विश्वास के साथ में हम अपना काम करें, सरकार काम करें और विश्वास के साथ में काम करते हुए हम आगे बढ़ें। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमने काम नहीं किया है, हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर काम किया है। हमने धान खरीदी में बहुत अच्छा काम किया। मैं सोसायटी में गया था। मुझे सरकार की इस बात की प्रसंशा करनी पड़ी कि हम पहले भी धान बेचते थे। हम सबसे पहले बोरा के लिए रोना रोते थे, लेकिन आज एडवांस में बोरा रखा हुआ है। सेम डे किसान धान बेचकर गया है और वह घर पहुंचा नहीं है, उसके अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। इसके लिए मैं सरकर को बधाई देना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सेम डे में उनका धान खरीदी का पैसा पहुंच जाना, यह निश्चित रूप से बड़ी बात है। हमने चार

किश्त को सपोर्ट प्राइस और वन स्टालमेंट में देना शुरू कर दिया। हम लगातार महतारी वंदन योजना का पैसा दे रहे हैं, लोग आलोचना कर रहे थे कि हम महतारी वंदन का पैसा लोक सभा तक देंगे, लेकिन हमने महतारी वंदन का पैसा जारी रखा है । हम उनकी लगातार किश्तें दे रहे हैं । हमारे जो खेतिहर मजदूर किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनके खातों पर हम पैसा भेज रहे हैं, तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में 5500 रूपये भेजा गया है । हमने ऐसे अनेक क्षेत्रों में जो वादा किया था, वहां पर विश्वास जीता है । हमें केवल इतने पर ही नहीं रूकना है, बल्कि छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें उसी स्थिति में काम करना पड़ेगा । इसमें केवल एक ही के कहने पर काम नहीं होगा, केवल हमारा मंत्री काम करेगा तो नहीं होगा, केवल मुख्यमंत्री काम करेंगे तो नहीं होगा, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हमारे मंत्री हों, हमारे विधायक हों, हमारे अधिकारी हों और मैं तो यहॉ तक कहता हूँ कि हमारी जो जनता है, जब हम सभी साथ चलेंगे, जो जवाबदारी है उसे साथ मिलकर पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ जो आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में बढ़ रहा है, वह सपना साकार होगा । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ विजन 2047 का जो विजन डाकुमेंट्स प्रस्तुत किया गया है, यह हमारे लिये उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा । हम अन्य क्षेत्रों में भी आगे इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे । आज इस अवसर पर जो आपने समय दिया, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ । एक बार पुन: इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को, हमारे वित्त मंत्री चौधरी जी को, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को, विधान सभा के अध्यक्ष जी को और आपको भी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने के लिये धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ और विशेष रूप से रामविचार जी को धन्यवाद देता हूँ, वह हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और उनके पास ट्राईवल का महत्वपूर्ण विभाग भी है । हमने अभी यहां पर संस्कृति के बारे में बात किया है, प्रकृति के बारे में बातें की है, यहां का हमारा लंबा इतिहास जो कि आजादी की भूमिका का निर्वाह करने वाले ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे रामविचार नेताम जी यहां पर बैठे हुये हैं । आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वह जीते हैं । आप समझ रहे हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा में जाकिट सिलवाये थे, उसे पहने थे आपने देखा है ?

सभापति महोदय :- माननीय श्री राजेश मूणत जी ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विजन 2047 पर बोलने का अवसर दिया है, वास्तव में यह छत्तीसगढ़ के भविष्य की परिकल्पना है । जब सोच नहीं होगी तो विजन कहॉ होगा और कल्पना नहीं होगी तो यह साकार कैसे होगा । छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं । नये विधान सभा के सत्र का यह पहला दिन है और एक विजन डाकुमेंट्स बनाने की कल्पना हाऊस के अंदर माननीय वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी जी ने रखी है और इस चर्चा में भाग लेते हुये माननीय अजय चन्द्राकर जी ने बहुत सारे सकारात्मक सुझाव

रखे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या-क्या होना चाहिये, यह कैसे होने चाहिये ? माननीय धरमलाल कौशिक जी ने भी अपनी बात को रखा और बहुत से विषयों को उठाया है, इसके पीछे सार्थक चर्चा और सार्थक सोच कि यह मेरा छत्तीसगढ़, यह मेरा विजन, इस परिकल्पना के लिये हम सब की भागेदारी से हमारी जिम्मेदारी बनती है । हमारे 90 विधान सभा के सदस्यों से बने लोकतंत्र के सबसे बड़े इस मंदिर में चर्चा के लिये पक्ष और विपक्ष को होना चाहिये । इसके पहले भी कई चीजों पर चर्चायें हुई है । सभी के सकारात्मक सुझाव आते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि यह छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, उस राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिये हम विजन डाकुमेंट्स लेकर आयें, यदि यहां विपक्ष का भी मत आता कि उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, छत्तीसगढ़ कैसे होना चाहिये तो सकारात्मक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने के लिये प्रेरणा मिलती । इस महत्वपूर्ण चर्चा में विपक्ष का भाग न लेना दुर्भाग्यपूर्ण है । इनका विजन छत्तीसगढ़ नहीं है, विजन इसलिये नहीं है कि दूरदृष्टि से काम करना, आने वाले बच्चों के भविष्य को संवारना, आने वाला छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, चाहे किसान के बारे में हो, बेरोजगार नौजवान के बारे में हो, चाहे उद्योग के बारे में हो, चाहे कृषि के बारे में हो, जब इस संपूर्ण विषय के उपर यहां बातचीत रख रहे हैं और विजन डॉक्यूमेंट रख रहे हैं तो अपनी-अपनी बातों को अपने हिसाब से यहां रखने का एक अवसर मिला है लेकिन उस अवसर का लाभ न उठा करके उन्होंने आज यहां से बहिष्कार करके चले गए। उसके पीछे उनकी सोच समझ में आती है, वे दूरदृष्टि नहीं रखते हैं, वे तात्कालिक लाभ लेने की योजना पर काम करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आज माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज यहां विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की एक कल्पना साकार है, तरक्की की ओर बढ़ता हुआ प्रदेश का विजन है, अगर एक बात कहें, आज नक्सेलिज्म खत्म करना है, अगर यह विजन नहीं होता तो हम सालों से नक्सली से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दूरदृष्टि थी, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री, अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, (गृह) माननीय विजय शर्मा जी और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से एक लक्ष्य लेकर चलें, हमारा बस्तर नक्सल की वजह से जो विकास की गति नहीं पकड़ पाया था, वहां के रहने वाले ऐसे कई लोग जो अपने प्राणों की आहूति दिए थे जिसके अंदर उनका कोई लेनदेन नहीं था, उनका किसी प्रकार का वाईलेंस से मौका नहीं पड़ा, उन लोगों से मुक्ति दिलाया, तरक्की और प्रगति के मार्ग को ले करके केन्द्रीय गृह मंत्री जी ये बात बोलते हैं कि बस्तर 2030 में सबसे बढ़ता हुआ संभाग दिखेगा तो एक विजन है, एक सोच है, एक कल्पना है, उसको साकार करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी आगे बढ़े हैं। (मेजों की थपथपाहट) हम भी चल रहे थे, देश चल रहा था, आप भी चल रहे हैं, लेकिन देश को 21वीं सदी की ओर ले करके जाना है। ये नया रायपुर है, ये नई विधान सभा है, एक विजन था, एक सोच थी,

एक कल्पना थी, जिसको आप और हम यहां बैठ करके साकार कर रहे हैं। इस प्रदेश की दो करोड़ 20 लाख जनता का आज निर्णय कर रहे हैं, ये हमारा मंदिर है, इसके अंदर हम चर्चा करते हैं तो आने वाले भविष्य बनाने की बात करते हैं। अगर किसी प्रदेश की पहचान बनती है तो कई चीजों में बनती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से फैला है, यहां जिस प्रकार से वनांचल क्षेत्र और पहाड़ियां हैं, यहां जिस प्रकार से नदियां हैं, जल, जंगल, जमीन है, तीनों भरपूर होने के बाद हम आने वाले भविष्य में क्या-क्या कर सकते हैं, यह अलग-अलग विभाग की अपनी-अपनी सोच है। कृषि के सेक्टर में बहुत कुछ करने की गुंजाईश है, सुझाव दिया, कृषि मंत्री जी कर रहे हैं, इसके पहले भी लोगों ने किया, आने वाले भविष्य में और क्या होना चाहिए, क्योंकि धान छत्तीसगढ़ के उपार्जन का और हमारे आर्थिक व्यय का सबसे बड़ा स्थान है। इसीलिए हम इसको लेकर क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ इंडस्ट्री विभाग आता है, जब यहां धान की पैदावार होती है, धान का छिल्का जब राईस मिल में उतरता है तो उसका वेल्यू एडीशन क्या-क्या हो सकता है ? उसके लिए दूरदृष्टि से विचार करना चाहिए। सरकार 3100 रूपये में 21 क्विंटल धान खरीद रही है, 1 लाख 47 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा धान यहां पैदा हो रहा है। उस धान से निकलने वाले रॉ मटेरियल का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हम उस सेक्टर में क्या-क्या कर सकते हैं, उसके उपर एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएं तो कृषि विभाग हो गया, इंडस्ट्री विभाग हो गया, दोनों मिलकर ज्वाईंट एफर्ट के साथ हम इसका उपयोग कैसे करें, आने वाली पीढ़ी जो इस सेक्टर में है, वह आगे क्या कर सकती है, इस पर विचार होना चाहिए। हम स्टील सेक्टर में बहुत आगे हैं, छत्तीसगढ़ की मेन इॅकानामी के अंदर आयरन इंडस्ट्री का भी उतना ही योगदान है। आयरन ओर यहां पैदा होता है। हमारी स्टील इंडस्ट्री है। कभी-कभी ये चर्चा का विषय बनता है कि वल्लभ स्टील कभी स्टील का भाव खोलता था, आज छत्तीसगढ़ 24 प्रतिशत से ज्यादा स्टील का उत्पादन करके देश की खपत को पूर्ति करता है। स्टील सेक्टर में क्या-क्या होना चाहिए, वैल्यू एडीशन में क्या-क्या कर सकते हैं, आज हमको मजदूर की आवश्यकता है, हमारे यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, क्या आई.टी.आई. के अंदर हमें ऐसे कोर्स प्रारंभ करना चाहिए कि भविष्य में वहां पर स्टील सेक्टर में लगने वाले बड़े-बड़े कारखानों में ऑपरेटर का काम सीखकर यहां के लोग काम कर सके और उनको रोजगार मिल सके, इसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर को इसमें जोड़ना होगा। माननीय, इस बात को कहा गया है कि वेल्यू एडिशन के साथ-साथ जोड़कर रोजगार उन्मूलक, जिन्हें रोजगार कैसे मिलेगा तो इंडस्ट्रीज की पॉलिसी में आपने कुछ चीजें की हैं। आपकी पॉलिसी में आपने इतनी सारी चीजें कर दी हैं कि वह इंडस्ट्री लगाएगा और आपने कहा है कि हम यहां के बेरोजगार नवजवानों को रोजगार देने की दृष्टि से एक इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कौन देगा, उतना प्रतिशत उसकी सब्सिडी बढ़ेगी। लेकिन इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लैण्ड की व्यवस्था कहां है? मेरा इस विषय पर कहना बहुत दुर्भाग्य के साथ विजन नहीं था और जिनका विजन नहीं था, उन्होंने कभी निर्णय नहीं किया। मैं इस

बात का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आप भी बस्तर से हैं और बस्तर के साथी बैठे हैं। बस्तर में टाटा आ रहा था। लैण्ड इक्वीजेशन हो चुका था। सी.एस.आई.डी.सी. ने लैण्ड इक्वीजेशन की, मुआवजा बंट गया। सी.एस.आई.डी.सी. के खाते में लैण्ड चढ़ गई। लेकिन वहां इंडस्ट्रीज नहीं लगी। वह वहां की कई चीजों से परेशान हो गये। टाटा पलायन कर गया। लैण्ड सी.एस.आई.डी.सी. के पास थी, लेकिन पूर्व सरकार ने फैसला कर दिया और लैण्ड वापस किसानों को लौटा दी। अब हम बात करते हैं कि बस्तर में इंडस्ट्रीज न आये तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति वहां पर इंडस्ट्रीज लगाये तो उसके पास जगह कहां है? अगर आदिवासी समाज के व्यक्ति की जमीन नहीं ले सकता। वह इतना बड़ा रिस्क लेकर आदिवासी समाज इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता। वहां एक भी बड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया नहीं है। जब वहां पर इंडस्ट्रीयल एरिया नहीं है तो वहां पर हम कितनी भी छूट दे दे, लेकिन बेनिफिट क्या है? जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, बताने के लिए भी अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए सरकार पॉलिसी बना सकती है, सरकार दूरदृष्टि के साथ योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्न कर सकती है, लेकिन फील्ड में जो लोग काम करते हैं, उनकी दूरदृष्टि कहां तक है, इस बात को आज सोचने की आवश्यकता है। यही नहीं आज इन्फ्रा के अंदर बातचीत कर रहे हैं। आप एन.सी.आर. की तर्ज पर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव तक पूरा मास्टर प्लान बनाकर आने वाले भविष्य में इसका विकास कैसे होना चाहिए, उस तर्ज पर एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। जब शहर के पुराने डॉक्यूमेंट्स बने, जो हमारे पूरे मास्टर प्लान बने, उन मास्टर प्लान्स का क्रियान्वयन लोकल प्रशासनिक अधिकारी नहीं करा पाये। जो बेतरतीब से पूरा शहर बसता जा रहा है, वह अपनी रिसपॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप विजन डॉक्यूमेंट बनाये तो विजन डॉक्यूमेंट में इसको भी सुनिश्चित करें कि अगर इसका कोई वायलेशन होता है तो रिसपॉन्सिबिलिटी टू। जब तक यह स्योरिटी नहीं होगी, तब तक हम किसी के बारे में कितनी बातचीत करते रहे। आज हम दिल्ली जाते हैं। आप नई दिल्ली की कल्पना करिये कि कितने साल पहले उसका मास्टर प्लान बना होगा? सालों-साल पहले 100 साल से ज्यादा हो गये, लेकिन वहां अतिक्रमण तो नहीं कर पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वह निर्णय करने की क्षमता रखी है। आज हमने नया रायपुर बसाया है। यह नया रायपुर 21वीं सदी का नया शहर है। अब यहां पर भी हम कभी-कभी समाचार पढ़ते हैं कि अतिक्रमण हटाना पड़ता है तो पुराने रायपुर का हाल क्या बताया? अजय जी ने स्मार्ट सिटी के बारे में बता दिया। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट बनाये तो क्रियान्वित करने वाले लोगों को भी उतनी ही गंभीरता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। जिस प्रकार से हम बस्तर की बात करें और पांचों संभाग की बात करें। रोड की कनेक्टिविटी कल क्या थी, आज क्या है और कल क्या होगी ? यह फ्यूचर प्लान है, यह एक दिन में नहीं बनता। माननीय धरम भैया अभी कह रहे थे। माननीय वित्त मंत्री जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने विजन डॉक्यूमेंट रखा था। मैं उनके सामने एक उदाहरण दे देता हूं।

यदि आपको कोई एक रोड बनानी है तो पहले सर्वे होता है, सर्वे के बाद डी.पी.आर. बनती है, उसके बाद विभाग उसका अनुमोदन करके वित्त विभाग को भेजता है, वित्त विभाग उसके बाद उसका A.A. देता है, A.A. देने के बाद टेण्डर लगता है, टेण्डर लगने के समय जब उसका टी.एस. होता है तो उस समय उनका आइटम कुछ और रहता है और उसके बाद जब साइट में फील्ड में काम होता है तो आइटम भी चेंज हो जाता है। मैंने उस विभाग में काम किया है इसलिए बोल रहा हूं। अजय जी ने बहुत कहा है । तब से लेकर आज तक जो पी.डब्ल्यू.डी. विभाग बना है, ब्रिज का ऐसा कौन-सा एक काम है जिसमें रिवाईज नहीं हुआ है ? मैंने पूछा है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। राजिम में पुल बन रहा है, उसका टेण्डर हो गया, सब कुछ हो गया, काम चालू हो गया, उसके लिये लैण्ड एक्विजिशन का प्रावधान हो गया, उसमें पैसा भी था। हम वहां गये तो साइट इन्सपेक्शन में पता चला कि 50 साल पहले उस केस में एच.एफ.एल. लेना है कि कितना पानी आया था तो 50 साल पहले एकाध बार बाढ़ आ गई होगी तो उसमें 1 मीटर हाईट बढ़ा दी। अब 1 मीटर हाईट बढ़ा दी तो उसकी लंबाई भी बढ़ गई। अब उसके नॉर्म्स में, अब वह पुल तो बनकर खड़ा है, अब उसने कहा कि पैसा खत्म हो गया। मैंने कहा कि यह तो स्वीकृत हो चुका है, सब कुछ हो चुका तो प्रॉब्लम क्या है ? हम जाकर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सर यहां पर एक बाढ़ आयी थी, जिसके कारण हमको वहां जाकर देखना पड़ा और वह 50 साल पहले आयी था तो उसके हिसाब से एच.एफ.एल. लेकर इसकी हाईट बढ़ गई तो लंबाई बढ़ गई, जिसके कारण लैण्ड एक्विजिशन नहीं कर पाये। फील्ड में ऐसे कई केस मिलते हैं । विजन डाक्यूमेंट में यह छोटी-छोटी चीज कही न तो फील्ड में ऐसी कई चीजें मिलेंगी, मैंने उसका एक उदाहरण आपको दे दिया। इसलिए आपने दूरदृष्टि के साथ छत्तीसगढ़ का विजन, छत्तीसगढ़ की सोच, छत्तीसगढ़ की कल्पना को रखा है। आने वाले भविष्य में क्या-क्या करना चाहिए, यह हर एक के बस की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, माननीय विष्णु देव साय सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस देश के अंदर ऐसे कई कड़े फैसले किये जो भारत के हित में है, आने वाले भविष्य के हित में है, आने वाली पीढ़ी के लिये हैं और जब ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं तो कई प्रकार की बातें निकलकर आती है। इसलिए कई चीजें वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है। अब इसके ऊपर कौन करेगा ? संबंधित डिपार्टमेंट की क्या सोच है ? मेरा एक सुझाव है कि आपको विभाग के मंत्रियों से भी एक सुझाव ले लेना चाहिए कि उनका विजन कहां तक है ? आपको डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी का भी सुझाव ले लेना चाहिए। वह योजना बनाते जरूर है लेकिन Implement करने में कहीं न कहीं देरी होती है। वह भी छत्तीसगढ़ के हैं, हम भी छत्तीसगढ़ के हैं, उधर बैठे हैं वह भी छत्तीसगढ़ के हैं, यहां विधान सभा में बैठे हैं, वह भी छत्तीसगढ़ के हैं। मेरा एक आग्रह है कि आपने जब सबसे ऑनलाईन सुझाव लिया तो थोड़ा बहुत सुझाव उनका भी ले लीजिए। चूंकि सब लोगों ने रिपीट कर लिया है तो मुझे भाषण लंबा नहीं करना है और मैं लंबा इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि अजय जी ने इतने सुझाव दे

दिये हैं और मैं उनके सुझाव का वाकई में समर्थन करता हूं। उनका प्रस्तुतीकरण थोड़ा अलग स्टाईल का रहता है। अध्ययन करने में उनके सानी में कोई नहीं है। इसलिए दूरदृष्टि के साथ में उन्होंने जो कुछ चीजें रखी हैं, उसका दूरगामी परिणाम न आये, अच्छा रिजल्ट आये और भविष्य की दृष्टि से हमें उन बातों पर जरूर विचार करना चाहिए। आज जैसे कई चीजों के ऊपर बातचीत करते-करते अच्छे सुझाव भी मिले। माननीय धरमलाल कौशिक जी भी बोलकर चले गये, लेकिन शायद एक-दो चीजें रह गईं। छत्तीसगढ़ में वनोपज और इसकी वेल्यू एडीशन पर आज तक ..।

समय

2.00 बजे

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदया, कैसा वेल्यू एडीशन हुआ था, उसको मैं बता रहा हूं। केन्द्र सरकार से 100, 150 करोड़ रुपये पैसा मिला, हम लोगों की सरकार चली गई। भूपेश बघेल जी के खास मंत्री ने उस वेल्यू एडीशन के प्लांट को बस्तर, कोंडागांव में बन रहा था, उसको वहां से हटाकर पाटन में लगाया। वेल्यू एडीशन की कास्ट कैसे बढ़ेगी? कच्चा माल सरगुजा, जशपुर या बस्तर से पाटन आयेगा और पाटन से फिर कहीं जायेगा। ऐसी-ऐसी योजना यहां बनी है तो इन लोगों के कारण से वेल्यू एडीशन तो सपना हो गया है। चलिये, आप बोलिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय आपने जो वेल्यू एडीशन की बात कही है, मैं उसी पर बात कह रहा हूं। हमने एक फूड पार्क आपके यहां भी स्थापित किया। छत्तीसगढ़ में सबसे यदा एक कोशिश की टमाटर की खेती बहुत होती है। बाबा रामदेव से आग्रह करके पकड़ करके लेकर आये। पूरा घूमने के बाद में यह निकल करके आया कि उसको जितनी रा मटेरियल की आवश्यकता है, वह उसके अनुकूल एक महीने के लायक भी नहीं है। तो रा मटेरियल जिन चीजों का निकल रहा है, उसके वेल्यू एडीशन पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और फूड पार्क जैसी जगह पर जिस सेक्टर के लिये पहले अजय चन्द्राकर जी ने उल्लेख किया, साहब आपके यहां 2003 में सायकल पार्क बना है और सायकल पार्क की स्थापना हुई, लेकिन हमने सायकल का वितरण चालू किया। वहां सायकल पार्क में सायकल नहीं बनती, बाकी बचा हुआ सब बनता है। यानि आप जिन चीजों के लिये पार्क की स्थापना कर रहे हैं, वहां सिर्फ स्कोप बनती थी। मैं उस विभाग का मंत्री होते हुए खुद साईट को देखने के लिये गया कि सायकल पार्क बनाया है, वहां क्या बना रहे हैं, उसको देख करके आते हैं। कोई चिमटा, कोई कैरियर, कोई डंडा, कोई सीट, कोई चेचिस बना रहा होगा। मेरे को पूरा इंडस्ट्रियल एरिया घूमने के बाद में खाली बस एक स्कोप बनाने वाला मिला। पार्क तो बना दिया लेकिन वाकई में उसको implement करते हुए उसके ऊपर क्या-क्या होना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब वनोपज में बस्तर में, कोंडागांव में, नारायणपुर में हम कुछ कर सकते हैं तो वनोपज संबंधित हमारी पालिसी ऐसी बननी चाहिए कि वहां के लोगों को उसका

बेनीफिट भी मिले और रोजगार भी मिले। यह बहुत बड़ी एक सोच है। मैं सोच के अंदर कहता हूं न तो कई लोग नहीं सोच सकते।

समय
2.03 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेन्डी) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, केदार कश्यप जी वहीं से हैं। कभी किसी ने कल्पना की थी कि प्रयास जैसी संस्था प्रारंभ हो सकती है। वह कैसे प्रारंभ हो गई? एक नौजवान कलेक्टर पहुंच गया। उन्होंने लोगों के साथ में उठा, बैठा है और वहां की स्थिति को देखा है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं का हाल देखा है। वह देखने के बाद में प्रयास जैसी संस्था प्रारंभ की तो विजन तो यही है न। दूरदृष्टि सोच, कल्पना, विजन और उसको implement करने की क्षमता, वह धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में लागू हो गई। और यही चीजें हैं कि जब लाभ देना चाहते हैं तो किसको लाभ देना चाहते हैं। साहब, यह हम लोग जो कहते हैं न कि आई.टी. वाले आयेंगे। जब जबरदस्ती व्यर्थ में अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं खुद गया था, खोज-खोजकर ले आया, पहली इनवेस्टर समिट छत्तीसगढ़ में मैं ही कराया। मैं राहुल बजाज के जी के साथ में ढ़ाई घंटा, दिनेश श्रीवास्तव जी मेरे सेक्रेटरी थे । मैं उनके पास ढ़ाई घंटे बैठा । सब बात की, मैं यह कोशिश में था कि एक ऑटोमोबाईल की इंडस्ट्री आ जाये तो उसके साथ में 200 उद्योग आते हैं । पूरी कोशिश कर ली, आदमी आखिरी में हाथ जोड़कर बोला कि साहब वहां आपके यहां नक्सल बहुत है तो मैं उससे बोला कि नक्सल यहां नहीं है साहब, साऊथ बस्तर के उस तरफ का है । नहीं-नहीं, डर लगता है कि मेरे दो बेटे हैं। मेरा एक बेटा इंश्योरेंस का काम देखता है और मेरा एक बेटा ऑटोमोबाईल का देखता है । साहब, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं सुरक्षित हूं। हमने सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से 22,000 स्क्वेयर फीट की एक बिल्डिंग बनाकर रखी थी । वह इसीलिये बनाकर रखी थी कि चलो, आई.टी. वाले आ जायें, तुम्हारे कम्प्यूटर के आगे खाली प्लग लगाना है । सब सर्वे करके चले गये तो उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला । रॉ मटेरियल मतलब लोग नहीं मिले, स्टूडेंट नहीं मिले । कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, खोलकर के, सब करके देख लिये और उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारे लायक नहीं है । साहब, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और मैंने अभी परसों, अभी एकाध हफ्ते पहले ही माननीय केदार कश्यप जी ने परिवहन विभाग के अंदर आपने जो एक छूट दी है, यदि वह छूट, वाकई में इम्प्लीमेंट कर देंगे कि 10 सीट और 12 सीट की जो गाड़ियां हैं, जिनके टेस्ट के अंदर थोड़ी छूट मिल जायेगी तो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, क्या है कि आजकल सामान्यत: किसी को एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी, 3 गाड़ी लेकर जाना पड़ता है और इस पर्यटन के बढ़ावे के लिये कुछ-कुछ सेक्टर में हमें प्राईवेट सेक्टर का इंवाल्वमेंट करके बहुत बड़ी, अतुल्य संभावनाएं हैं । आप सोचिए कि बस्तर के अंदर कैलाश गुफा से लेकर कहां तक लोग जाते थे । आज जब बस्तर शांत हो रहा है तो जब

विजन है तो विजन डॉक्यूमेंट में, बस्तर को भी हमें उतनी ही महत्ता देनी चाहिए ताकि बस्तर क्षेत्र विकसित कैसे हो, फ्यूचर प्लान कैसे हो ? राजेश जी, आप तो वहां के पर्यटन मंत्री हैं । हम लोग गये हैं, अभी धरम जी बता रहे थे कि वहां उल्टी दिशा से पानी बह रहा था । हम सब लोग गये थे न, मैनपाट । उल्टा पानी तो उसका डवलपमेंट विजन बनना चाहिए । वहां तिब्बती परिवार रहते हैं उनका कल्चर जीवित रहना चाहिए और वहां दिनभर आदमी वहां रहकर टाईमपास कर ले ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बनना चाहिए कि वहां 1 घंटे के लिये ऊपर जायें और वापस नीचे आ जायें तो फिर फ्यूचर नहीं बनेगा तो जब इन बहुत सारी चीजों पर विजन डॉक्यूमेंट बना है तो कुछ लोगों का अभिमत पर्यटन वाले भी लेना चाहिए । दूसरे से जो पर्यटन सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनसे जब अभिमत लेंगे तो उनकी तकलीफ क्या है ? वह अभी हमें बतायेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, सभी लोगों ने बहुत सारे विभागों पर चर्चा कर ली। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि यह फ्यूचर प्लान है, ओपन डिस्कस है । ओपन विचार का एक मंच है, छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी संस्था है और इस संस्था के माध्यम से आने वाले 2047 तक छत्तीसगढ़ का कितना विजन होना चाहिए उसके ऊपर आज यह परिचर्चा है और माननीय अध्यक्ष जी ने समय देकर इस परिचर्चा के ऊपर सब जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था लेकिन विपक्ष के साथी लोगों ने, उनके कोई सुझाव नहीं हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कोई बात नहीं, उनसे लिखित में ले लेना, उनको चिट्ठी लिख देना । क्या है कि उनके कार्यकाल में उनका डवलपमेंट विजन नहीं था । इस पर कभी भी एक डिस्कस कर लें। उनका विजन डवलपमेंट था ही नहीं । उनका विजन एक ही चीज का था कि माल कहां से आयेगा और कैसे आयेगा, केवल उसको छोड़कर कोई काम नहीं । मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं, मैं राजधानी रायपुर की बात करूं । यहां 5 साल में एक ईंट नहीं जुड़ी है। यहां पर 3 बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करके चले गये। न उसका टेण्डर लगा, न उसका डी.पी.आर. बना। भईया, न आपने टेण्डर किया तो भूमि पूजन किसका किया? जब भूमि पूजन कर दिया जिसमें शारदा चौक का चौड़ीकरण का कार्य होगा, जिसकी 150 करोड़ रूपये की लागत होगी, महादेव घाट के ऊपर घाट का निर्माण, जिसकी लागत 100 करोड़ रूपये होगी। मैंने पहले ही शारदा चौक के चौड़ीकरण के बारे में बता दिया। यहां वाई फ्लाईओव्हर का निर्माण, जिसकी लागत 150 करोड़ रूपये होगी। चुनाव के बाद साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये का भूमिपूजन सम्पन्न। आज तक रायपुर वाले देख रहे हैं आज 7 साल हो गये। इन्होंने वही तो काम किया है अभी अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हो रही है जिस दिन अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो साहब, आपने भी कई घोषणाएं की हैं। आपने उन घोषणाओं पर बताना चाहूंगा कि नगरीय प्रशासन विभाग की घोषणा कर दी। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने स्मार्ट सिटी के बारे में बताया। भगवान कसम "अंधा बांटे रेवड़ी चिन्ह-चिन्ह के दे" । रायपुर शहर में 1000 करोड़ रूपये खर्च हुआ। रायपुर शहर में 1000 करोड़ रूपये केवल स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुआ। साहब, सिंगल

प्रोजेक्ट नहीं। वहां पर कोई जाकर एक प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकता कि यह प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का बनाया हुआ है इसके अंदर यह देखिये। साहब, आज विजन डाक्यूमेंट में ऐसा भी ध्यान रखियेगा कि जो फर्जी तरीके से जो कुछ करके चले जाते हैं उनके लिए सजा का भी प्रावधान डाल दीजिएगा क्योंकि बिना विजन कुछ नहीं होना है। इसीलिए इस विजन डॉक्यूमेंट में एक सोच के साथ, आप लेकर आये हैं। मैं आपके प्रति आभार, माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कम से कम उनकी दूरदृष्टि एक सोच और कल्पना को मूर्त रूप देने का काम, हमारे युवा मंत्री हमारे ओ.पी. चौधरी जी को दिया है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें। यहां डबल इंजन की सरकार है। यह एक छोटा राज्य, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, हम इसकी परिकल्पना को साकार करने का जो बीड़ा उठाकर चल रहे हैं, उसके लिए पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद्। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपके प्रति आभार।

समय
2.14 बजे

कार्यमंत्रणा समिति का सप्तम् प्रतिवेदन

सभापति महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रविवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2025 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय का निर्धारण करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

1.	**वित्तीय कार्य**	निर्धारित समय
	वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन विचार एवं पारण	3 घंटे
2.	**शासकीय विधि विषयक कार्य**	
(1)	छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025	1 घण्टा

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विधान सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को भी होगी। इस दिन "वन्देमातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्रित विषय पर चर्चा होगी।

सभापति महोदय :- अब इसके संबंध में श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा (क्रमशः)

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के बहुत ही विद्वान वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के छत्तीसगढ़ विजन 2047 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, हर इंसान को अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े सपने देखने का अधिकार होता है और उसे देखना भी चाहिए । जिसका विजन ही कमजोर हो, जिसका विजन बहुत ज्यादा दूर तक न जाये तो वह जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता और यह राजनीतिक रूप से इसको विवाद में उलझाने का भी विषय नहीं है । प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर के पहले दिन अगर छत्तीसगढ़ के विकास की बात करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आया है तो अच्छा होता कि इसमें विपक्ष भी रहता । वह आलोचनात्मक सुझाव देते और उसे सरकार स्वीकार करती । लेकिन जहां विष्णु देव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में हम यह कदम उठा रही है, वहीं विपक्षी दल के लोग अपने नेता के विकास के लिए दिल्ली जाकर वहां पर संघर्ष कर रहे हैं । यही सोच है और इसी सोच से जनता निर्णय करती है । हम रेल्वे की बात कर रहे हैं, हम देश के किसानों की, हवाई सेवा की बात कर रहे हैं और वे अपने नेता की बात कर रहे हैं । सभापति महोदय, दुनिया में दो प्रकार के नेता होते हैं । एक जबरदस्त नेता होता है और एक जबरदस्ती का नेता होता है । (मेजों की थपथपाहट) तो जबरदस्त नेता हमारे पास हैं । श्री नरेन्द्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस देश के अंग्रेजों के सैंकड़ों ऐसे कानून को बदल दिया, जो अनावश्यक रूप से सिर्फ पेशी के ऊपर पेशी, पेशी के ऊपर पेशी देते थे । यही क्रांतिकारी रिफार्म है । यह थोड़ी हो रहा है कि 2047 में यहां कोई समस्या ही नहीं रहेगी । विकास भी होगा, समस्या भी होगी, लेकिन यह अंग्रेजों के कानून के ऊपर चलने वाला कानून नहीं रहेगा, हमारे गांव के किसानों को तहसीलदार और कोर्ट में पेशी के ऊपर, पेशी के ऊपर पेशी सन्नी देओल का डॉयलाग

नहीं बोलना पड़ेगा । सन्नी देओल जी का कोई डॉयलाग है न तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख । तारीख पर तारीख नहीं चलेगा, उन्होंने सरल कर दिया । अगर प्रधानमंत्री जी ने यह सोचा कि देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है । इसमें क्या बुराई है ? अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चलेगा और यह फूल स्टाफ नहीं हुआ है तो इसमें क्या बुराई है ? जब भारत के ऊपर पहलगाम में पाकिस्तान का हमला होता है, उनके आतंकवादी हमला करके मारकर चले जाते हैं, अगर उनके देश के 10-10 आतंकवादी अड्डे उड़ा दिए जाएं और 11-11 एयरबेश त्राहिमाम करने के लिए उनको साथ कर दिया जाये तो उसमें किसी को क्या तकलीफ होना चाहिए ? पर प्रश्न वहां पर भी उठता है । माननीय वित्त मंत्री जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन राजनीतिक चश्में से देखने वालों को यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस प्रदेश की 2 करोड़ जनता को यह दिखाई दे रहा है । यहां की जनता महसूस कर रही है । मोदी की गारंटी के ऊपर जनता ने विश्वास किया और इसलिए प्रचंड वोट देकर यहां पर पूर्व सरकार का तख्ता पलट हुआ और यह नई सरकार बनी और इस नई सरकार के बनने के साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसानों के कल्याण के लिए 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल धान की राशि देकर उनकी भलाई का काम किया । यही रिफार्म है, यही क्रांतिकारी परिवर्तन है, यही विजन है, जो हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने वहां पर देखा और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सरकार के वित्त मंत्री जी ने उसको पूरा किया। सभापति महोदय, हमने अपनी माताओं और बहनों से वादा किया था कि आपको एक हजार रूपया प्रति माह महतारी वंदन का देंगे। सरकार की वित्तीय स्थिति क्या रहती है, पूरे प्रदेश को जो चला रहा है, उसको मालूम होता है। हमने हर महिलाओं को एक-एक हजार रूपये देने का काम किया है। हम बोनस नहीं दिए थे, इस सरकार ने उसको देने का काम किया है। यह विजन है। मैं तो डॉ. रमन सिंह जी को याद करना चाहूंगा कि जब हम लोग सन् 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस राज्य के टैंट के विधान सभा में बैठे थे। तब इस रायपुर का आलीशान ईमारत में बैठे हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शायद यहां आने के लिए कोई सड़क भी नहीं था। यह जमीन भी हमारी नहीं थी, इस विधान सभा भवन की परिकल्पना भी नहीं थी। डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां सड़क बनवाई, लोग यहां की सड़क को देखने आते थे। महानदी और इन्द्रावती भवन, जैसे विशाल भवन बनाकर मंत्रालय को स्थानान्तरित करके इस नवा रायपुर को जिंदा किया। यहां लोगों का आकर्षण बढ़ाया, यह विजन होता है। अगर 22 साल पहले डॉ. रमन सिंह यह नहीं बनवाये होते तो कहां का नवा रायपुर, कहां का विधान सभा भवन और कहां का मंत्रालय होता। हम वहीं डी.के.एस. अस्पताल में, मुर्गी के दड़बे में जाते रहते। यह होती है सरकार की सोच। मैं वित्त मंत्री जी की दो बजट को देखा हूं। उन्होंने प्रापरली हर क्षेत्र को अपने बजट में स्थान दिया है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे वह छात्र हो, उन्होंने सबको मौका दिया। वह आज ही अपने भाषण में बोल रहे थे कि स्कील डेवलपमेंट करना है।

पहले फिजियोथैरेपी के कुछ ही कॉलेज थे, आज 12 नये-नये कालेज खोल दिए। सभापति महोदय, यही तो विकास का काम है। कई बच्चे और बच्चियां वहां ट्रेनिंग लेकर लोगों की सेवा करेंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी के इस प्रस्ताव का बहुत दिल से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश में कोई लक्ष्य निर्धारित करने की परम्परा आज से नहीं बल्कि वर्षों पुरानी है। हमारे पूर्वज आज से सौ-दो सौ साल पहले भी, जो गांव के गौटिया और मुखिया होते थे, (खड़े होने में दिक्कत महसूस करने पर) सभापति जी, खड़े होते नहीं बन रहा है। आपकी अनुमति से थोड़ा एंगल बदल रहा हूं, माफ करियेगा। आज पहला दिन है, पहला प्यार है, अच्छा है, चलेगा। सभापति महोदय, हमारे पूर्वज लोग, गांव के जो मुखिया होते थे, वह तालाब खुदवाते थे, उस जमाने में जल सरंक्षण करने का ऐसा फैशन नहीं चलता था। परन्तु उन्होंने तालाब खुदवाया, उन्होंने आम के वृक्ष लगाये, वह फल तो नहीं खाये, उसको आने वाला पीढ़ी खाया। यह विजन भी आने वाली पीढ़ी के लिए है कि हम अपने प्रदेश के उन करोड़ों नवजवानों को आने वाली पीढ़ियों को अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधा, अच्छा अवसर दें, ताकि वह इस प्रदेश का नागरिक होने का गौरव से नाम ले सकें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विजन है और उसे क्रियान्वित करने के लिए वित्त मंत्री जी आगे बढे हैं। वित्त मंत्री जी, आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्जुन बनना पड़ेगा। जब मछली को घुमाया जा रहा था, कई महापुरूष मछली का निशाना लगा रहे थे, उसमें मछली की आंख पर ही निशाना लगाना था। किसी से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है तो बोले मछली की पूंछ दिख रही है। किसी से पूछा गया तो कहा कि मछली का सिर दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है तो बोले कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन ने तीर मारा और जाकर आंख में तीर लगा।

श्री राम विचार नेताम :- अगर यह प्रश्न मोहले जी पूछा जाता तो क्या बोलते?

श्री धर्मजीत सिंह :- मोहले जी तो बोलते कि आंख के अंदर का रेटीना दिख रहा है। (हंसी) आंख के अंदर का रेटीना भी दिख जायेगा। मोहले जी यहां पर सबसे बड़े धनुरधर और निशानेबाज हैं।

एक माननीय सदस्य :- धुरंधर हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- धुरंधर हैं। अभी धुरंधर पिक्चर भी हिट हुआ है।

श्री राम विचार नेताम :- मोहले जी एक तीर से कई निशाना साधे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- और जब तक हम कोई लक्ष्य नहीं लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए लक्ष्य लेना हमारे लिए गौरव की बात है और लक्ष्य को ईमानदारी से क्रियान्वित करना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है और उसका पालन वित्त मंत्री जी करेंगे, क्योंकि बिना मुद्रा के कुछ काम हो नहीं सकता और मुद्रा ही सब कुछ है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो मुद्रा का अपने आप में

महत्व है। आपने सब सेक्टर में काम किया। सोशल सेक्टर में काम किया। किसानों के लिए काम किया। छात्रों और महिलाओं के लिए भी आपने काम किया है। हमारी सरकार की उपलब्धि बहुत है, दो वर्ष हुए हैं, बहुत सी उपलब्धि है। सभापति जी, मैं बहुत ही संतोष के साथ गर्व के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में श्री विष्णु देव साय की सरकार में 40-45 साल से जो नक्सल समस्या से हम जूझ रहे थे, नक्सलियों के कारण हमारा सब विकास रूका हुआ था, उन नक्सली लोगों के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कई नक्सली सरेंडर हुए। कई गिरफ्तार हुए और कई नक्सली हमारे फौज से मुकाबला होने पर हताहत भी हुए और मौत के घाट भी उतारे गए। उसमें एक हिडमा नाम का नक्सली था। एक-डेढ़ करोड़ का इनामी बसवराजू और हिड़मा। सभापति महोदय, इस देश में ऐसे लोग भी हैं, जो विकास को रोकते हैं। उनको यह नहीं मालूम कि हमारे 200 से ज्यादा जवानों को मारने वाला हिड़मा जो आतंक का नाम था, उसकी मौत पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया, उसके सपोर्ट में खड़े हो गए, हिड़मा तेरे, कई जिंदा होंगे हिड़मा प्रकार के नारे लगाए गए। सभापति महोदय, उनको बुलाइए, उनको निमंत्रण दीजिए और दिखाइए कि बस्तर में कैसा खूनी नरसंहार हुआ है। नहीं तो उनके खिलाफ एक भर्त्सना का प्रस्ताव इस विधान सभा से पास होकर जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मतलब यह नहीं है कि वह कुछ भी देशद्रोही और आतंक करने वाले लोगों को समर्थन दे। ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद करके अस्पताल बना देना चाहिए जो हिड़मा जैसे लोगों का समर्थन करते हैं और ऐसे लोगों को जो सफेद पोश लोग सपोर्ट करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा बनते हैं, उनके खिलाफ भी पूरे लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी, रशियन कोलाबोरेशन में एस-400 बनाए। वह एस-400 पाकिस्तान के हमले में यहीं से बैठे-बैठे उनको उड़ा दिया गया। क्या गलत किया। सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में किसान कल्याण निधि देकर गरीबों को मदद करने का प्रधानमंत्री ने काम किया, हमारी सरकार ने उसको लागू किया। हमने किसानों के बारे में सोचा। सभापति महोदय, चंद्रयान भेजने के लिए निर्णय लिया। चंद्रमा में यान भेजे। दुनिया के दो तीन देशों में हमारा नाम हुआ। यही तो विजन है, यही तो तरक्की है, यही तो हमारी छलांग है, यही तो हमारी इच्छा है, यही हमारी आकांक्षा है। लेकिन सभापति महोदय, यह काम भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। माननीय वित्त मंत्री जी कहां हैं? हैं नहीं, उनको रहना था। बुलवाओ भाई। मेरे विधान सभा में दो व्यक्ति हैं, मैं उनको मुख्यमंत्री जी से मिलवाना चाहूंगा। मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था, एक 80 साल का है, एक 85 साल का है। वे लोग कई साल से वृक्ष लगा रहे हैं और सिर्फ लगाते हैं दो प्रकार का वृक्ष–एक वट का और एक पीपल का। मैंने उनको सम्मानित किया है। ऐसे लोगों से ही प्रेरणा लेने का काम हमको करना पड़ेगा। सभापति महोदय, जब हम कई विकास के काम करते हैं, कई विजन आगे बढ़ाते हैं तो हमें सामाजिक रूप से भी लोगों को जागृत करने का काम करना चाहिए। समाज कल्याण मंत्री भी नहीं हैं, पता नहीं कहां है। सब मंत्री लोग भाई।

श्री केदार कश्यप :- भोजन करने गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम भी तो भोजन नहीं किए हैं, उनको रहना था न। सभापति जी, समाज कल्याण की दिशा में बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि समझाने के बाद भी जो नये-नये छात्र हैं, वह अपना जन्मदिन बीच चौराहे में मनाते हैं और तलवार से केक काटते हैं। वे ओपन रूफ वाला गाड़ी में बैठकर वीडियो रील बनाते हैं। यह सब विकृति को रोकने के लिए सिर्फ सरकार एवं पुलिस का कानून नहीं है, उसमें हमको जनजागृति पैदा करना होगा। हम सदन में बैठे हुए लोगों को, ग्राम पंचातय में चुने हुए लोगों को, ग्राम पंचायत के प्रमुख लोगों को समाज कल्याण विभाग के कोई कार्यक्रमों के माध्यम से आप जागरूक करिये। एक अच्छे प्रदेश के रूप में, एक अनुशासित प्रदेश के रूप में सुशभ्य और सुसंस्कृत प्रदेश के रूप में इसको हमको बनाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, विज़न 2047 के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह चाहते हैं कि इस देश में हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करें। बहुत अच्छी बात है। हवाई यात्रा करना है, जब छत्तीसगढ़ का विज़न 2047 है तो सिवाय रायपुर एयरपोर्ट के कहां से हवाई सेवा है? ए.टी.आर. जगदलपुर में छोटे एयरपोर्ट में कुछ दिन हवाई सेवा शुरू हुआ तो दो दिन चलता है, चार-छः दिन बंद रहता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ए.टी.आर. हवाई हड्डे की बात कर रहे हैं तो मुंगेली में भी हवाई अड्डे की मांग कर दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- हाँ, करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब चीज बन गया है, लेकिन मुंगेली में हवाई अड्डा नहीं बना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, पहले वह मेडिकल कॉलेज खोलवायेंगे, फिर हवाई अड्डा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसकी मांग कर दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- हाँ, मैं मांग कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर एक बहुत प्रमुख केन्द्र है। वहां हाई कोर्ट है, एन.टी.पी.सी. है, कोल इंडिया का हेड ऑफिस है, रेल्वे का जोन है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहां से प्लेन सर्विस बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछली बार विधान सभा में एक अशासकीय संकल्प रखा था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने अशासकीय संकल्प में बिलासपुर के हवाई अड्डे के लिए 26 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति की थी, लेकिन अभ हम बहुत परेशान हैं। बिलासपुर में हवाई अड्डे से लगा हुआ 1100 एकड़ जमीन रक्षा मंत्रालय के पास है। उसमें से हम 300 एकड़ जमीन मांगना चाह रहे हैं, ताकि हमारे यहां बोइंग 4सी एयरपोर्ट का दर्जा मिले और वहां बोइंग प्लेन उतर सकें। अब वह 300 एकड़ जमीन के लिए सिर्फ 50 करोड़ रूपये देना है। अगर हमारी सरकार 50 करोड़ दे दें, डिफेंस मिनिस्ट्री तैयार है तो हमको 2500 मीटर रनवे बनाने के लिए वह जगह मिल जाएगी। वह जगह मिलेगी तब उसको रनवे बनायेंगे, रनवे बनेगा तो अपने आप प्लेन सर्विस शुरू हो जाएगी क्योंकि इंडिगो की दादागिरी के कारण ही प्लेन सर्विस शुरू नहीं हो पा रही थी। इंडिगो ने एक

दिन में पूरा सिस्टम को कोलेप्स किया। एक दिन में ट्रैफिक रोक कर पूरे देश में हाहाकार मचवाया। अब दूसरे एयरलाइन्स को भी परमिट मिलेगा, पर एयरपोर्ट होना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री जी ने परमिशन दिया है, मुख्यमंत्री जी मिल लिए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री तैयार है कि उसको 50 करोड़ रूपये दो, 300 एकड़ जमीन ले लो। इसलिए इसको लेना चाहिए और बिलासपुर के हित के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अजय चन्द्राकर जी ने क्षेत्रीय असंतुलन की बात की थी और मैं भी यह कह रहा हूं कि क्षेत्रीय विकास में अगर क्षेत्रीय असंतुलन होगा तो 2047 पाना बहुत कठिन होगा। इसलिए बिलासपुर को भी पैरलल दिया जाये। जो प्रोजेक्ट सुनते हैं कि रायपुर में यह संस्थान खुलेगा, अच्छी बात है। यह कहां खुलेगा तो रायपुर में खुलेगा, अच्छी बात है। रायपुर के अलावा भी दूसरे शहर है। बिलासपुर है, रायगढ़ है, कोरबा है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, धमतरी है, उसका भी तो ख्याल करिये। फैलाकर रखेंगे तो चारों तरफ आना-जाना होगा, फैलाकर रखेंगे तो वहां का विकास होगा, फैलाकर रखेंगे तो सब एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे। सिर्फ रायपुर-रायपुर कर देने से, एक राजधानी को दिखाने के लिए रायपुर को बढ़ा देंगे और बाकी जगह का विकास रोक देंगे। अध्यक्ष महोदय, आदमी को एक फूल बाही का शर्ट पहनाया जाये और उसमें एक तरफ पूरा काट दो तो वह कैसे दिखेगा? इसलिए जब आप लोग बैठते हैं तो दूसरे क्षेत्र का नहीं तो कम से कम बिलासपुर के लिए, अंबिकापुर के लिए काम करिये। मंत्री जी, आप लड़िये न। हमारे नेता तो आप हैं। आप उधर के नेता हो तो आपको लड़ना चाहिये । वह बस्तर के लिये लड़ रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है, उनको लड़ना चाहिये । आदमी क्यों 6 घण्टे मोटर में जायेगा, वह प्लेन में जायेगा। आपको तो चलाना नहीं है, हवाई अड्डा बनाकर दे दो, हवाई जहाज वाले चलायेंगे, आदमी किराया देगा और बैठकर जायेगा । बिलासपुर एअरपोर्ट में 800 एकड़ जमीन फिर भी बचेगा । अध्यक्ष जी, आपके लिये भी बोल रहा हूँ । बिलासपुर में 800 एकड़ डिफेंस का जमीन है । 1100 एकड़ में 300 एकड़ 50 करोड़ रूपये का देकर मुक्ति पाओ । डिफेंस का 800 एकड़ जमीन बचेगा । 800 एकड़ जमीन में डिफेंस प्रोडक्शन का काम क्यों नहीं हो सकता है । ब्रम्होस लखनऊ में बन सकता है तो बिलासपुर में क्यों नहीं बन सकता । जबलपुर में गन कैरिज फैक्ट्री और दुनिया भर का है, वह यहां क्यों नहीं खुल सकता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वहां पांचवी पीढ़ी का जो स्टील्स विमान रसिया से आ रहा है ना, वह बनेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जो भी बने ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ब्रम्होस्त्र वगैरह के लिये स्टील विमान पांचवी पीढ़ी के लिये वह रिजर्व है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरा मतलब है, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि वह माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलकर रक्षा उत्पादन के लिये...।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह बात सही है, बहुत कम राशि है और वित्त मंत्री जी उसको जरूर करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पिछली बार उत्तरप्रदेश का चुनाव रिजल्ट आया तो हम लोग बोलते थे कि उत्तरप्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या जो है, वह पुन्नूलाल जी के बच्चों से कम है । बिहार में अभी फिर रिपीट हो गया है । कौन से गणित में पैदा किये हैं कि कांग्रेस वाले इसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं । इनके बराबर में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य :- वह धुरंधरों के धुरंधर हैं जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आप सब का ही बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा ज्ञानवर्धक बात नहीं कर रहा हूँ । सभापति महोदय, जैसे आप पैसा भी दे दिये, सरकार पैसा दे देती है, विभाग से मंत्री मंजूर करा देते हैं, इसे बजट में ला देते हैं । यह टेण्डर नाम की समस्या से हम सब ग्रस्त हैं । टेण्डर के बारे में भी कोई एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाईये । मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ । एक विभाग का है, मैं नाम बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा । पांच लाख रूपये का कोई काम करना है तो उसका 21 दिनों का टेण्डर लगेगा । वर्क आर्डर होते डेढ़-दो महीने लगेगा । कब काम होगा, कैसे होगा, चार-पांच दिनों में टेण्डर बुलवा लो, सब कुछ ऑनलाईन तो है । सिस्टम में है, उसको दिखवा लीजिए । मैं तो डरता हूँ, कोई काम मंजूर हो जाता है तो बताते हैं कि टेण्डर लग गया है, मैं कांपते रहता हूँ कि पता नहीं यह टेण्डर खुलेगा कि नहीं खुलेगा । मैं एक अधिकारी को फोन करके पूछा कि फलॉ-फला काम का क्या हुआ, उसने कहा कि चौथी बार टेण्डर लगाना पड़ रहा है । अब बताईये कि चौथी बार टेण्डर, समझ में नहीं आता । उसे लगाकर काम करवा दो, गरीब जनता को काम चाहिये । उनको टेण्डर वगैरह से मतलब नहीं है, हम भी टेण्डर नहीं समझते हैं । आप इसको करा दीजिए । डीएमएफ मद, यह जहां गया वहां चकाचक है । कूबेर जी का बरसात हो रहा है । हमारे जैसे गरीब क्षेत्र के लोग बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, गौरेला, पेण्ड्रा, बलरामपुर, यहां बोलते हैं कि आपके यहां खदान नहीं है । जहां खदान रहेगा, वहां मिलेगा । रायगढ़ से कोयला निकलकर जो आता है, वह जाता कहां है, उसे खदान क्षेत्र में ही खपाओ । यह हमारे बिलासपुर से जाता है, जबलपुर जायेगा तो कवर्धा होकर जायेगा, मुंगेली में पूरा ट्रेफिक जाम करेगा । इसका धूल हम खाये, धक्का हम खायें, एक्सीडेंट में हमारे लोग मारे जायें, हमारे लिये नियम है कि वह आपको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा ? मिलना चाहिए। अगर DMF में नहीं मिल रहा है तो हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे लोगों की भी इच्छा है कि DMF मद से काम हो, हमारे भी बहुत से छोटे-छोटे काम हैं, जिनको हमको DMF मद से कराना पड़ता है, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था की जाए। सभापति महोदय, मैं तो यह भी कह रहा हूं कि अगर 2047 जाना है तो शुरूआती कदम में इस सदन में पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने विधायक निधि का पैसा बढ़ाया था, 2 से 4 करोड़ या 3 से 4 करोड़ किया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि विधायक निधि का पैसा बढ़ाईए, आप भी परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करिए और विधायक निधि की राशि को एक-एक विधायक का 10-10 करोड़ रूपए करिए। (मेजों की थपथपाहट) अगर आपको

उसमें दिक्कत है कुछ कंट्रोल करना है तो आप प्रभारी मंत्री को 5 करोड़ दे दीजिए, पर 10 करोड़ करिए। प्रभारी मंत्री को 6 करोड़ दे दीजिए लेकिन आप विधायक निधि को 10 करोड़ करिए। हाईस्कूल की हालत क्या है, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन सबकी हालत कुंभ कौणम जैसी घटना किसी दिन हो जाएगी। उसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- ये कुंभ कौणम क्या है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मद्रास में बच्चे लोग उसी में गिरकर मर गए थे। सारे स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है, बहुत बद्तर है, जब हम गांव में जाते हैं तो आवेदन आता है, जर्जर स्कूल है, बच्चों की जान को खतरा है, क्या जवाब दें ? कोई फंड है? कोई प्रावधान है ? मैं आपके माध्यम से इस 2047 विजन में मांग करता हूं कि बच्चों के जर्जर प्राइमरी स्कूल और मीडिल स्कूल को बनाने के लिए डेढ़, 2 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान करें ताकि हर विधायक अपने-अपने क्षेत्र में बच्चों का स्कूल बनवा सकें। अस्पताल की भी हालत खराब है, फूडपार्क राजनीतिक जुमला सरीके हो गया है, पिछली सरकार थी, वह भी फूडपार्क करते-करते रह गई, हमारे साथ कवासी लखमा जी थे, वे टोक्यो गए थे, मैं वहां बैठता था, वे इधर मंत्री थे, मैंने पूछा की लखमा जी टोक्यो कैसे गए थे तो उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाईल्स सेक्टर का अध्ययन करने के लिए गए थे। आज तक 5 साल के बाद कोई नट बनाने का कारखाना भी नहीं खुला है, पाना पेंचिस तक का नहीं खुला है, कहां आटोमोबाईल का अध्ययन करके आ गए। वैसे ही ये फूडपार्क है। फूडपार्क कहां है, मैं लेना चाहता हूं, मुझे बताईए। मैं 10 हजार रूपए का समान खरीदूंगा, फूडपार्क कहां है बताईए। साहब, ये बोलने में अच्छा लगता है, ये पिक्चर के डायलाग समान बहुत सुंदर लगता है, डायलाग डिलीवरी कर ले तो और अच्छा है। लेकिन ये है कहां ? टमाटर का इस्कास कहां है ? कटहल का डिब्बा कहां है ? गन्ने का डिब्बा कहां है ? यहां बहुत से फसल हैं, भैया इसी को करवा दीजिए। कम से कम दो चार दस परिवार के लोग जीयेंगे, खाएंगे। मेरे सबसे अच्छे मित्र मंत्री राजेश अग्रवाल ही बैठे हैं। बहुत हंसमुख आदमी हैं।

श्री रामविचार नेताम :- मैं इनके बारे में बता रहा हूं, मैं आपका एक मिनट लूंगा। सभापति महोदय, राजेश मूणत जी अभी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि टूरिज्म की ऐसी व्यवस्था करिए कि मैनपाट में जाएं तो नीचे न उतरें। (हंसी) उसके लिए राजेश जी बहुत सक्षम हैं। उनके यहां एक से अनेक योजना है, आप उतरने की बात कर रहे हैं, आप वहीं घूमते रहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, हम आप और राजेश तो तीन दिन नीचे न उतरे। मूणत जी एक घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। वे संभाल ही नहीं सकते। उसके लिए जो ग्रहण करना पड़ता है, वह कोई चीज ग्रहण नहीं करते। हम और आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। (हंसी) राजेश अग्रवाल जी बहुत अच्छे मंत्री हैं, बहुत हंसमुख हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। आदरणीय मंत्री जी, पर्यटन में बहुत सी बिल्डिंग बनी पड़ी हैं, उसमें सांप, बिच्छु, घोड़ा, भालू विचरण कर रहे हैं। यदि आपको जानकारी नहीं हो

तो आप सरगांव के पास चले जाइये। मैं आपको जगह भी बता देता हूं। सरगांव के नेशनल हाइवे में जो बिल्डिंग है, उसमें दुनिया भर का सब है, पर्यटन भर नहीं है। उसको आप ठीक कराइये। यदि वह आपके बस में नहीं आता है तो उसको वहां की महिलाओं को दे दीजिए। उसको कम से कम महिलाएं चलाएंगी। कुछ खाना बनाने से उनको दो-चार पैसे की आमदनी हो जाएगी। उसको वहां की महिला समितियों को दे दीजिए। रतनपुर में आपका टूरिज्म का एक भी होटल क्यों नहीं है? रतनपुर महामाया देवी का मंदिर है। जहां राष्ट्रपति से लेकर छोटे से छोटे लोग जाते हैं, वहां पर टूरिज्म का होटल क्यों नहीं है? वहां पर टूरिज्म ने होटल क्यों नहीं बनवाया? आप वहां पर भी विचार कर लीजिए। खुड़िया डेम को अंग्रेजों ने सन् 1930 में बनवाया था। वह इतना सुंदर डेम है। वह जंगल के बीच में है। वहां पर टूरिज्म ने होटल क्यों नहीं बनवाया? पिछली सरकार में टूरिज्म के कुछ नेता वहां गये थे। जमीन भी एलार्ट हो गया, सब हो गया। हम पेपर में पढ़ते थे। आपको वहां पर टूरिज्म का होटल बनवाने में क्या तकलीफ है? जहां अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, परिवार सहित जाएंगे और रहेंगे। वहां तो कुछ जगह नहीं है, वहां पर खेत-खार, झाड़-झड़ूखा है तो वहां पर आदमी क्या करेगा? आप वहां पर कुछ रहने का इंतजाम करवाएंगे, तब लोग जाएंगे और तब टूरिज्म बढ़ेगा। मैं भी 15-20 दिन, 1 महीने पहले उज्जैन गया था। उज्जैन में मैं एम.पी. टूरिज्म के होटल में रूका था। वह कितना बढ़िया चल रहा था। मैंने वहीं पर उनको बोला कि आप लोगों ने इतना बढ़िया व्यवस्था किया है, मैं राजेश अग्रवाल जी से बोलूंगा। आप खुद चले जाइये या आपका दिल थोड़ा बड़ा तो है ही तो हम लोगों को ले चलो। आप उज्जैन भी घूमा देना और टूरिज्म का होटल भी देखकर आ जाएंगे। आप उसी को सीखकर आ जाइये और यहां कुछ करवा दीजिए। आपके पास सब कुछ है। यदि कहीं आप उसको भी देखकर नहीं करेंगे, हमारे बोलने के बाद भी नहीं करेंगे तो आदमी खुड़िया बांध घूमने के लिए परिवार के सहित टेन्ट लेकर थोड़ी न जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, पर्यटन की बात हो रही थी। माननीय पर्यटन मंत्री जी, आप उपस्थित हैं तो मैं दो बातें बालूंगा, जो छूट गई थीं। एक तो अभी मैनपाट का उल्लेख किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से हो, चाहे नगर निवेश की ओर से हो, चाहे किसी की भी ओर से हो, उसका आप एक प्लान बनाइये। यदि वहां पर अनियंत्रित विकास हुआ तो एक बढ़िया पर्यटन स्थल हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा। कौन सी चीजें कहां पर कैसे बनेंगी, एक और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। जो आपका पुरखौती मुक्तांगन है, उसके पीछे परिकल्पना यह थी कि वह देश का सबसे बड़ा खुला मानव संग्रहालय बने।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप यह बात अनुदान मांग में बोल लीजिएगा। अभी एक महीने बाद वह आ ही जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, यह विजन बता रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, उसमें क्या हुआ। आप देख लीजिएगा कि हमने एन.आई.टी. को कुछ जमीन दे दी। उसकी कुछ जमीन हमने ट्रायबल म्यूजियम के लिए दे दी। हमने एन.आई.टी. को जमीन दी, क्योंकि ट्रिपल आई.टी. खोलना जरूरी था तो उस समय यह हुआ कि पीछे जो जंगल विभाग की जमीन है, उसमें से उनको देंगे। लेकिन उसका एरिया नहीं घटाएंगे, क्योंकि वह सबसे बड़ा मानव संग्रहालय बने। उसका बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना था, लेकिन अभी तक उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना कि कहां पर क्या बनेगा, कैसे बनेगा? नई-नई सरकारें आती-जाती हैं, नये-नये मंत्री आते-जाते हैं, उसमें वह वैसा बनता जाता है। इसलिए वह छत्तीसगढ़ की पूरी प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा खुला मानव संग्रहालय का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाकर आप उसको बढ़िया बनवाइये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह बात इसलिए कह रहा था कि भावना बोहरा जी पंडरिया की विधायक हैं। यह अमरकंटक से आ रही थीं तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र लोरमी के जंगलों से अचानकमार टाइगर रिजर्व के अंदर से आ रही थीं तो एक नदी के किनारे खड़ी हो गईं। बरसात का दिन था तो उसमें भयंकर बाढ़ थी। इनके लिए संदेशा भेजवाया गया कि उतरने का दुस्साहस न किया जाये क्योंकि वह नदी में उतरने का दुस्साहस करने वाली थी। मैंने कहा कि गड़बड़ हो जायेगी। वह जब खुड़िया आयीं तो वहां पर अंग्रेजों के जमाने का एक रेस्ट हाउस है और वहां एक आदमी के रूकने की व्यवस्था नहीं थी। वह बहुत सुंदर जगह है। आप एक बार माननीय मंत्री जी के संग जाईये और मंत्री जी के साथ जाकर देखकर आईये और वहां एक बढ़िया रेस्ट हाउस बनवाईये और बन जाये तब तो वहां रात गुजारेंगे।

पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- मैं आपके सुझाव को नोट कर रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी। जब रात गुजारना हो तो हमारे संग चलिये फिर सिंगल, डबल सब माल्ट चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे संग चलियेगा। मंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने एक-दो चिट्ठी लिखी थी और मैं थोड़ा दुखी था इसलिए अभी आपको ही बोल रहा हूं। पिछली बार बृजमोहन अग्रवाल जी पर्यटन मंत्री थे। उन्होंने विजयपुर में शेड बनाने के लिये 50 लाख रूपये देने के लिए कहा था। विजयपुर किला है, वहां बौद्ध देवी का मंदिर है। हम वहां 50 लाख रूपये का तो क्या दो साल में 5 लाख रूपये का शेड नहीं बनवा पाये हैं। एक चिट्ठी आयी थी तो उसको 5-10 लाख रूपये का शेड बनवा दीजिये न। 10-20 लाख रूपये में क्या फर्क पड़ता है ? यदि हमारे लोगों की धार्मिक आस्था संतुष्ट होती है या वह धार्मिक स्थल है और उससे पर्यटन न भी बढ़े तो धार्मिक पूजा-पाठ तो होगा, उसकी दुआ आपको मिलेगी। उसमें 50 लाख रूपये का एक बढ़िया शेड बनवाईये। मैंने बता दिया कि मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर खुड़िया में पार्टी दूंगा। वह तो ऐसी वाली पार्टी में

नहीं जायेंगे परंतु हम और आप चलेंगे। आप हमारे विजयपुर में 50 लाख रूपये का एक शेड बनवाईये। अध्यक्ष जी, यह विजन बहुत अच्छा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इस पार्टी के लिए सदन को विश्वास में लेना जरूरी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस विजन को हम सबको मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। आप सभी लोगों का ख्याल रखियेगा। मैं एक बात और बोल देता हूं। माननीय रामविचार नेताम जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और हमारे प्रिय मित्र भी हैं। हम जब अखबार में पढ़ते हैं तो फलाना मंत्री के क्षेत्र में यह खुल गया, वहां वह खुल गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं ? हम लोगों का भी तो ख्याल रखा करिये, जीतना तो सबको है । (मेजों की थपथपाहट) हम लोग जीतकर आयेंगे तब तो आप मंत्री रहेंगे। हम अगर नहीं जीतेंगे तो आप कैसे मंत्री बनेंगे (मेजों की थपथपाहट) ? इसलिए सबका ख्याल रखिये। सभापति महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी की बहुत तारीफ करता हूं। उनका विजन बहुत ही क्लीयर है, वह अच्छा काम कर रहे हैं और उनका काम साफ-सुथरा है। हमारे सभी मंत्री अपने-अपने विभागों में सर्वोत्तम प्रदर्शन दे रहे हैं। मुझे आप लोगों से थोड़ा-बहुत काम तो मिल ही जाता है। आप हमको भी काम दिया करिये। हमको भी जनता के बीच जाना पड़ता है तो हम बिना काम के उनके बीच में जाकर क्या करेंगे, आप ही बताईये ? हमें सिवाय गाली खाने के और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमारी मदद करिये और हम आपकी मदद करेंगे।

“तू धार है नदियां की
मैं तेरा किनारा हूं
तू मेरा सहारा है
मैं तेरा सहारा हूं”

बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सुश्री लता उसेण्डी (कोंडागांव) :- माननीय सभापति महोदय, आज के इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने विजन छत्तीसगढ़ अनजोर 2047 पर चर्चा करने के लिए इस सदन में विशेष सत्र का आयोजन किया और निश्चित तौर पर जब छत्तीसगढ़ अनजोर की बात आती है और विजन 2047 की बात आती है तो जितने जनप्रतिनिधि हैं, सबके मन में यह विचार भी आता है कि आने वाला 2047 कैसा हो, जिन सपनों के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। शुरूआत के तीन साल का कार्यकाल उसके बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम तेजी से आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़वासियों ने समझा कि अब हमारे सपने को उड़ान भरने का एक अच्छा अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से मिल रहा है। वर्ष 2018 से 2023 के बीच में फिर से 2003 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई

थी, लेकिन 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और आज विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में हमारी सरकार 02 वर्ष पूरा कर रही है और आज हम विजन-2047 में इस सदन में नये विधान सभा सदन के प्रथम दिवस चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य खनिज समृद्ध राज्य की श्रेणी में आता है और क्षेत्रफल के आधार पर देश का नवां सबसे बड़ा राज्य Low Seismic Area में हमारा छत्तीसगढ व्यापार की दृष्टि से भी एक बहुत अच्छे स्थान के रूप में उभरकर सामने आता है। जिस तरह से हम बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की ताकत हमारे युवाओं में है, यहां 27 का मिड इन एज बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है और युवा ऊर्जा से चमकते हमारे राज्य के पास भी असीम संभावनायें हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मोदी जी की एक बात को दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मार्केट, मेन पावर, माइंड सेट, टार्माबिलिटी का कॉम्बीनेशन हमारे देश में मिलता है और ये सारे कॉम्बीनेशन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि ऊंचाईयों तक पहुंचने के लिये जिस विकास की कल्पना हम करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा अगर किसी चीज का होता है और आगे बढ़ने का जो मार्ग प्रशस्त करता है, वह शिक्षा होती है। आप सड़क, बिजली, पुल नहीं देते, लेकिन अगर सुदूर अंचलों में शिक्षा पहुंचा दिये होते, चाहे सरगुजा, बस्तर के सुदूर अंचल हों, हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में हो, आज हम कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं और अगर अभी माओवाद से मुक्ति की बात कही जा रही है तो शायद अगर उस तरह की व्यवस्था उस समय हो गई होती तो वह संकट भी हमारे प्रदेश में हम सबके सामने नहीं होता। मैं बताना चाहूंगी कि विजन- 2047 में जो एजुकेशन की बात कही गई है जिसमें ये कहा गया है कि 1000 से अधिक माडल स्कूल, 36 नये आदर्श कालेज और 11 technical institute बनायेंगे। यह बिना किसी संदेह के स्वीकार करने योग्य है कि इन सभी संस्थानों में हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, आप 1000 माडल स्कूल, 36 नये आदर्श कालेज और 11 technical institute बनायेंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर हमें जल्दी से उपलब्धि को प्राप्त करना है तो इसके लिये यह प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो 33 जिले छत्तीसगढ़ में हैं, इन जिलों में जिस तरीके से दंतेवाड़ा में आस्था विद्यालय का संचालन हो रहा है जो सारी सुविधाओं से लबरेज है, मुझे लगता है कि वैसी संस्थाओं का निर्माण सभी जिलों में होना चाहिए। विशेषकर के मैं बस्तर और सरगुजा की बात करूंगी जहां पर वह होना ही चाहिए। अगर हम ये सुविधायें जल्दी नहीं देंगे तो हम इस क्षेत्र में जिस डेव्हलपमेंट की बात कह रहे हैं, वह डेव्हलपमेंट को छूने में हमको शायद थोड़ा सा और समय लग सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि नारायणपुर का जो रामकृष्ण मिशन आश्रम चलता है जिसमें वहां से खेल के क्षेत्र में जो प्रतिभावान बच्चे वहां से निकलकर जा रहे हैं, वैसा एक भी खेल परिसर या संस्था हमें छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलती है जिसके माध्यम से हमारे ट्राइवल क्षेत्र के बच्चो को आजादी के इस रजत जयंती वर्ष में भी जिस संख्या के साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, वह संख्या के साथ हम नहीं बढ़ पा रहे हैं।

अगर उस आंकड़ें को हमको छूना है और जिस तरीके से यहां विषय आया कि नशा से मुक्त छत्तीसगढ़ का भी निर्माण करना है। तो ऐसी संस्थाओं को भी मुझे लगता है कि आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा कि हम जल्दी उन संस्थाओं को जिलों में डेव्हलप करें ताकि वह सारी समस्यायें हम सबके सामने खत्म हों।

समय :

3.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, स्किल डवलपमेंट की बात आती है, निश्चित तौर पर सभी जिलों में स्किल डवलपमेंट के इंस्टीट्यूट खोले गये हैं । मुझे लगता है कि सभी ब्लॉकों में आई.टी.आई. हैं, लेकिन गुणवत्ता पर हम सब शंकित रहते हैं और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । एक कोई ट्रेड चल रहा है, सिलाई चल रहा है तो सिलाई चल रहा है । ड्राईविंग चल रहा है तो आप जान रहे होंगे कि 15-20 दिन के ड्राईविंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं । क्या हम वहां से अच्छे स्किल्ड लोग निकाल पा रहे हैं, यह बहुत सोचने का विषय है । आज आपके जितने भी लाईवलीहुड कॉलेज चल रहे हैं, अगर आप वहां से कल स्किल्ड लोगों को निकालने के लिये चले जायेंगे तो बहुत स्किल्ड लोग नहीं हैं, यहां हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वे सभी यह अनुभव कर रहे होंगे तो जिसमें गुड गवर्नेंस की बात आती है तो हम गुड गवर्नेंस के माध्यम से इन सभी चीजों को कैसे हमारे इस विजन के साथ और बेहतर बनाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए । गुड गवर्नेंस की बात आयी, फाईलों की बात आयी ।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगी कि कोण्डागांव विधानसभा में एक बहुत बड़ा मछलीपालन का केंद्र है । मैंने एक पत्र लिखा, शायद पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही फिशरी कॉलेज है तो मैंने संचालक महोदय को चिट्ठी लिखी कि हमारे यहां भी बहुत बड़ा मछलीपालन का केंद्र है तो आने वाले बजट में आप फिशरी कॉलेज के लिये एक प्रस्ताव आगे अपने सचिव और मंत्री जी को प्रस्तुत करियेगा । मेरे पास कुछ महीनों बाद एक पत्र आया कि हमारा एक फिशरी कॉलेज चल रहा है, वहां से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं उनको हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और आगे अगर हम कॉलेज खोलेंगे तो उनको भी नौकरी नहीं दे पायेंगे तो इसलिये इस तरह के पत्र की पुनरावृत्ति न की जाये तो इस तरह के पत्र भी आजकल आने लगे हैं तो यह चिंतन का विषय है, मैं इस बात को कह रही हूं । हमारे सभी माननीय मंत्रीगण बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे होंगे, माननीय वित्तमंत्री जी भी सुन रहे होंगे । हम यह सोचते हैं कि लोगों को कैसे अधिक से अधिक रोजगार दिलवायें । अभी मैं आंकड़े निकलवा रही थी, मैं अपने जिले की बात करूं तो 1 लाख 26 हजार से अधिक बच्चे पहली से बारहवीं तक के हैं । साढ़े 5000 से अधिक बच्चे बारहवीं पढ़ते हैं, लगभग-लगभग संख्या हमारे करीब साढ़े 4000 बच्चे बारहवीं पढ़ते हैं । हमारे 5600 बच्चे दसवीं में हैं और मैं जो 1 लाख 26,000 की संख्या बता रही हूं, इन 10 सालों के अंदर वह सब बच्चे बारहवीं पास करने वाले हैं । हम उनके लिये किस तरह की तैयारी करके रखे हैं, हमने उनके लिये क्या तैयारी की है ? इस विजन में कहीं न कहीं हमारे बच्चों का

जो आंकड़ा है, 10 साल के पीरियड में हमने हमारे बच्चों को कहां-कहां पर किस तरह के रोजगार से, आज एक बच्चा पढ़ता है और मिडिल क्लास की बात होती है, हमारे परिवारों की भी बात होती है तो हम भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले और कोई सरकारी नौकरी में चला जाये, बिजनेस की तरफ इधर-उधर बहुत सारी बातें हो रही थी लेकिन सब भयभीत रहते हैं कि कहीं कोई दूसरी दिशा में चला गया तो संघर्ष की बेड़ी पर चला जायेगा और पता नहीं उसकी लाईफ कैसी होगी तो हम आज भी अपने लोगों को यह सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि अगर आपको पेंटिंग में रूचि है तो आप पेंटिंग कीजिये, आपको गार्डनिंग में रूचि है तो आप गार्डनिंग कीजिये । आपको जिस भी विधा में रूचि है, अगर खेल में रूचि है तो आप खेल खेलिये, आप अपने भविष्य की चिंता मत कीजिये तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से वातावरण को निर्मित नहीं कर पायेंगे तो 2047 का जो सपना हम सब देख रहे हैं, शायद उसमें हम फिट नहीं बैठ पायेंगे । नगरनार स्टील प्लांट है, यह कहा जाता है, हम लोग बहुत टेक्निकल लोग नहीं हैं लेकिन उसके साथ छोटी-छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं । नगरनार स्टील प्लांट चालू हो गया है, छोटी इंडस्ट्रीज क्या, आज तक हम कोई एक छोटी इंडस्ट्री, जैसे कोई छत्तीसगढ़ का वासी हो, बस्तर का वासी हो, कोई छोटा यूनिट लगा ले । हमारे डॉक्यूमेंट्स में नियम-कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन क्या हमने इसमें पूरी अच्छे से तैयारी की है कि कोई एकाध यूनिट जैसे अभी धर्मजीत जी बता रहे थे कि एक नट भी बन रहा है क्या ? तो यह निश्चित तौर से हम सबके लिये बहुत सोचने की बात है और इसके लिये एक सामूहिक प्रयास की बात है । हमारे शासन-प्रशासन के दोनों पक्षों को, समाज के पक्षों को भी एक कदम आगे बढ़ाकर चिंतन करके काम करने की आवश्यकता है । अगर हम एक लाईन खींचकर काम करेंगे तो उस लाईन के इतर एक्स्ट्रा काम करने का नहीं सोचेंगे तो शायद हम उन सारे सपनों को पूरा नहीं कर पायेंगे। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में इस रजत जयंती के अवसर पर तीन या चार संस्थाएं ही हैं जो देश के टॉप 100 संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। यह भी हम सब के लिए एक प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

माननीय सभापति महोदय, जब स्वास्थ्य की बात आती है। माननीय सदस्य चन्द्राकर जी कह रहे थे निश्चित तौर पर मेरे सामने बस्तर का एक आकंड़ा है। वहां पर 15 से लेकर 49 साल की महिलाएं 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं एनिमिया की शिकार हैं। उस दिशा में हमें विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। जब हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं जो जब तक हम इस एजग्रुप पर चिंता करके काम नहीं करेंगे तो आने वाले स्वस्थ समाज का निर्माण करने में भी हम सब लोगों को थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह बात भी ठीक है अर्थव्यवस्था के ग्रोथ से गरीबी दूर की जा सकती है, पर यह बात भी पूर्ण तरीके से सत्य नहीं है क्योंकि हम सब देखते हैं कि कई विकसित देश में अभी भी गरीबी अलग-अलग रूपों में देखने को मिलती है। inclusive growth की बात भी अच्छी है। इसे सफल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में एन.एम.डी.सी. को 6 दशक हो गये हैं ।

शायद यहां वर्ष 1964-1968 से एन.एम.डी.सी. शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि खनिज समृद्ध राज्य होने के बाद एन.एम.डी.सी. का 6 दशक पूर्ण होने के बाद, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा को आंकड़ों में देखेंगे तो सबसे गरीब जिलों में इनकी गिनती होती है। अभी डी.एम.एफ. फण्ड की बात हो रही थी सब चाहते हैं कि हम सब के विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ. फण्ड का बजट मिले, लेकिन किन्हीं नियमों में बदलाव के कारण नहीं हो पा रहा है तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में अगर डी.एम.एफ. फण्ड नहीं है तो उन क्षेत्रों के लिए किस तरह की प्लानिंग हो ताकि किसी क्षेत्र में एक समानान्तर बजट जाए और वहां का स्पष्ट विकास हो। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि यहां संतुलन की बात आती है। माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह जी बहुत सारी बातों को कह रहे थे और गांधी जी ने भी कहा है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन जिस तरीके से हम सब के क्षेत्रों में जिस तरह का काम दिख रहा है कहीं न कहीं तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से विकास नहीं हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि आज रायपुर नगर निगम है। आपको यह लगता है कि रायपुर सेन्टर है, राजधानी है, आपने यहां पर नया रायपुर की कल्पना की तो आपने नया रायपुर खड़ा कर लिया। हमारे शहर के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे और बहुत सारी सड़कें निकल रही हैं। मैं हमारी सरकार को बधाई देती हूँ जिनके विजन की वजह से आज हमारा रायपुर congested नहीं है। वरना हमारी सरकार का वह विजन नहीं होता तो आज हमको रायपुर से निकलने में भी 2-2, 3-3, 4-4 घण्टे लग जाते। आप आज रायपुर के किसी भी कोने में चले जाईये आपको 15 से 20 या 25 मिनट लगता है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जिन्होंने रायपुर को एक नये विजन के साथ विकसित किया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि अगर विकास की बात करते हैं, हम पलायन को रोकने की बात करते हैं तो पलायन के अलग-अलग कारण होते हैं कोई शिक्षा के लिए जाता है, कोई बेहतर रोजगार के लिए जाता है, कोई अलग-अलग कामों के लिए जाता है किसी को लोकल में रोजगार नहीं मिलता है वह इसके लिए बाहर जाता है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अगर विकास की बात करें। जो हमारा जगदलपुर क्षेत्र है तो आपने वहां जगदलपुर के बाजू में एक नये शहर की कल्पना की है क्या ? आपके पास कोण्डागांव जिला है तो जिला के बाजू में एक नयी कॉलोनी, नये विकास की बात की है क्या ? कांकेर है तो आपने कांकेर के साथ कल्पना की है क्या ? धमतरी है तो आपने धमतरी के साथ कल्पना की है क्या ? क्या इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या किसी तरह की बातें मुझे समझ में नहीं आयीं। क्योंकि अगर कोई शहर है या कोई जिला मुख्यालय है तो उसके साथ जो ब्लॉक मुख्यालय है आपको उस ब्लॉक मुख्यालय की भी चिंता करनी पड़ेगी कि वहां का विकास भी बराबर हो ताकि जो आपकी बड़ी संख्या में काम करने के लिए रोजगार की तलाश में वर्कर सुबह से निकलते हैं और शहरी क्षेत्र की ओर जाते हैं, रोजगार नहीं होने की वजह से उसको हम कैसे डायवर्ट करें और उनके ही ब्लॉक में उनको कैसे काम मिले, उनके गांव में छोटे-छोटे लघु इंडस्ट्रीज

डालकर उनको रोजगार दें, चाहे वह फारेस्ट प्रोजेक्ट हो या जो भी हो, जैसा भी हो, जो हमारे यहां के बुनकर्स हैं, आप गांव में चले जाईए, हर बुनकर की कमर टूट रही है । वह काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ नाम के यूनिट लगे हुए हैं और उनकी स्थितियां बहुत खराब हैं । हम सिर्फ दिखावा करते हैं कि हमारे यहां इतने बुनकर हैं, इतने यूनिट लगे हुए हैं, इतने काम चल रहे हैं तो यह स्पष्टता होनी चाहिए। यदि आपके पास शहर हैं तो शहर के आसपास आपके पास जो भी नई यूनिट आ रही है, हैल्थ की यूनिट हो या जिस तरीके से हो, आप उस शहर का विस्तार किस तरीके से करेंगे, इसके लिए सारे छत्तीसगढ़ की एक अलग प्लानिंग होनी चाहिए । उसके बगैर छत्तीसगढ़ के विकास के मायने जो हम देख रहे हैं, वह नहीं होगी इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहां जितने गांव हैं, जितनी पंचायतें हैं, उन सारी पंचायतों का एक मास्टर प्लान होना चाहिए और उन पंचायतों के लिए एक मास्टर प्लान के साथ हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की बात आती है तो मैंने पहले भी कहा और अभी भी फिर से उस बात को रिपीट करना चाहूंगी । हम शिक्षा को रोजगार से, नौकरी से जोड़कर देखते हैं, रोजगार तो नहीं, लेकिन नौकरी से जोड़कर देखते हैं । हमने आजतक अपनी मानसिकता नहीं बदल पाये कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर उसमें कोई दक्षता है, क्वालिटी है तो वह क्वालिटी ही आपको बड़ा बनाती है । हम गार्डन में जाते हैं को बोनसाई का पौधा भी 2, 3 या 4 लाख रूपए में मिलता है, लेकिन हमारे यहां की जो शिक्षा की पद्धति है, उसमें भी कहीं न कहीं प्राईयरी क्लास से ही हमारे बच्चों में इन चीजों की ओर लाने की आवश्यकता है कि आप हर क्षेत्र में जाएं और काम करें, सरकार आपके साथ खड़ी है, जैसा विजन हमारा समाज आने वाले समय में चाहता है, वैसा हम तैयार करके अपने समाज के लिए एक रास्ता बनाकर दें ।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी बहुत सारी बातें हैं । अभी पेयजल की बात आई, पीएचई की बात आई, नलजल योजना की बात आई, अमृत जल मिशन की बात आई । आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने ईलाकें हैं, जहां पर फ्लोराईडयुक्त पानी है, जिनको हम फ्लोराईड मुक्त पानी नहीं दे पा रहे हैं और उनकी आने वाली दो-तीन पीढ़ी खराब हो रही है । आपने इसका सर्वे किया है तो आपके पास इसकी क्या प्लानिंग है, कितनों दिनों के अंदर आप इसको समाप्त करने वाले हैं ? जब किसी से बात करो तो यह कहा जाता है कि हम उसमें कुछ ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं और ट्रीटमेंट प्लान की बात होती है तो वह सक्सेस नहीं है। यह प्रक्रियाएं इतने वर्षों से निरंतर चली आ रही हैं । मेरा कहना है कि जो इंडीकेटर्स हैं, आपने उन इंडीकेटर्स में इस तरह की सारी बिन्दुओं को निश्चित तौर पर सम्मिलित किया होगा, पर जब मैं यहां पढ़ रही थी तो बहुत सारी चीजें मुझे नहीं दिखीं इसलिए मैंने इन बातों को यहां पर कहा है तो मुझे लगता है कि इन चीजों की ओर भी ध्यान दें । अगर हम पीढ़ी को खराब करेंगे तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ अंजोर के 2047 विजन है, उसको भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे इसलिए

बहुत जरूरी है कि हर क्षेत्र की अलग-अलग समस्या है । हम बस्तर जाते हैं तो वहां की समस्या अलग है, सरगुजा हम जाते हैं तो वहां की समस्या अलग है । मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ की समस्या अलग है, बोरे बासी की बात कही जाती है तो किरण देव जी, केदार जी बैठे हैं, हम लोग नहीं जानते, हम लोग पेज जानते हैं । रागी का पेज, पंडिया का पेज पीना जानते हैं । हमारे यहां के लोग बोरे बासी को नहीं जानते हैं तो ऐसी जगह का खान-पान, रहन-सहन सब थोड़ा सा डिफरेंट है तो डेव्हपलमेंट हो तो सभी तरह के, पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर इसमें और काम करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी । जिस तरीके से विकसित भारत, 2047 के लिए सजेशन आईडिया शेयर करने के लिए एक प्लेटफार्म और एक वेबसाईड बनाया गया है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए भी बनाया जाये, ताकि आम जनता भी इसमें अपना सुझाव दे पाएं, इसको कन्टीन्यू किया जाये। क्योंकि अभी यह काम अभी शुरूआती दौर पर हैं। आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिन बिन्दुओं को हम सभी को थोड़ा सा लग रहा है कि उसे नहीं छुआ गया है, हम सबने कहा है, उन बिन्दुओं को भी हमारी सरकार गंभीरता से लेगी और विजन 2047 में सम्मिलित करेगी, इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देती हूं। धन्यवाद।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर दक्षिण) :- सभापति जी, धन्यवाद। आज 2047 विकसित छत्तीसगढ़ के ऊपर यहां सदन में चर्चा हो रही है, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगणों को बधाई देता हूं कि इस विषय पर चर्चा कराकर 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, यह इच्छाशक्ति का प्रमाण है। आप देखेंगे कि जब आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, हमको यह बात आज समझ में आ रही है, सन् 2014 में प्रधानमंत्री जी जानते थे कि हम इस देश के अंदर अच्छा काम करेंगे तो बार-बार हमारी सरकार आयेगी। केवल देश का रजत जयंती वर्ष नहीं, स्वर्ण जयंती वर्ष 2047 तक हमारी सरकार रहेगी और हम उसे मनायेंगे। मैं स्वच्छ भारत मिशन चालू करने के पीछे का कारण बता देता हूं। मैं यह भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि छोटी-छोटी चीजों से छोटे-छोटे विकास से लोगों की आम समस्याओं को दूर करके विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा। जब तक जनता समस्याओं से जूझती रहेगी तो विकसित भारत में उनका योगदान नहीं होगा, उनका सहयोग नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जनता की समस्याओं का निराकरण करना होगा। उन्होंने सन् 2014 में पहली बार लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन और हर घरों में शौचालय बनेंगे, कहा तो लोग हंसते थे। प्रधानमंत्री आवास की कल्पना की गई। जनधन बैंक खाता खोलने की कल्पना की गई। गैस चूल्हा, गैस सिलेण्डर देने की कल्पना की गई। मैं उस समय सांसद था, जब मैं शुरूआती तौर पर घूमता था तो उस समय मैंने देखा कि हमारी माताएं-बहनें एक-दो किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं, थक जाती हैं, बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना। जब सब काम करके वह सोती

थीं तो सोचती थीं कि क्या मेरा जीवन केवल मेहनत के लिए है। उसकी आवाज को सुनकर 2019 चुनाव के बाद पहले बजट में इसका प्रावधान निर्मला जी वित्त मंत्री ने रखा था। 2 लाख 65 हजार करोड़ रूपये जल जीवन मिशन के लिए रखा। हर घर के अंदर नल होगा, इसकी कल्पना की गई। उस कल्पना के साथ देश का 50 प्रतिशत वूमेन पावर है, उनका योगदान आने वाले समय में विकसित भारत में लिया जायेगा। उन महिलाओं की भी भागीदारी इसके अंदर रहेगी, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करके ही उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने उस समय कल्पना की, मैं आम आदमी की सारी योजनाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आये, ऐसी 210 योजनाएं लेकर आये और उन योजनाओं को धरातल पर लागू करके दिखाया। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उस समय छत्तीसगढ़ के अंदर 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया, जल जीवन मिशन योजना को पूरा नहीं किया, जिसके कारण हम 5 साल पीछे हो गये। आज फिर से जनता ने अवसर दिया है। जनता ने इस बात को सोचा कि 15 साल तक डॉ. रमन सिंह की सरकार के अंदर कैसे तेजी के साथ विकास होता था, कैसे ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक पैसा मिलता है। जब इसे देखा तब उन्होंने डॉ. रमन सिंह की सरकार और भूपेश बघेल जी की सरकार की तुलना की और तुलना करने के बाद बेहतर माना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है, जो काम कर सकती है और पुन: विश्वास किया। अगर आप आज देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना, विकसित भारत का मतलब विकसित छत्तीसगढ़ भी है। कोविड कालखंड के समय पी.पी.ई. किट नहीं हुआ करती थी, एन-95 मार्क्स नहीं हुआ करता था। हम 395 रूपये में मास्क खरीद रहे थे। हम पी.पी.ई. किट 1400, 1800 रूपये में खरीद रहे थे, उसी समय उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की और आत्मनिर्भर भारत और हम उस समय उसी कालखंड के अंदर में हमने वहां पर विश्व के अंदर में अगर कहीं नाम को स्थापित करना है, भारत के नाम को स्थापित करना है तब जाकर पूरे विश्व के लोग यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो विकसित भारत बनेगा, यह कल्पना थी और जूझकर 18 घंटा, 20 घंटा मेहनत कर उस समय में हमें उसी कालखंड के अंदर में 8 रूपये, 10 रूपये के अंदर मार्क्स मिलना चालू हो गया। 120 में पी.पी.ई. किट मिलना चालू हो गया। हमने एक नहीं, दो वैक्सीन बनाया। हमने 140 करोड़ देशवासियों को जीवन रक्षक वैक्सीन लगाया और हमने 140 देशों को उनके जीवन रक्षा का कवच दिया। विश्व के अंदर में समझ में आया, अब यह वह भारत नहीं है, अब यह आत्मनिर्भर भारत हो गया। यह आगे बढ़ने वाला भारत हो गया। अब आत्मनिर्भर भारत में हम सैन्य हथियार बनाना चालू कर दिए। खिलौने जैसी छोटी चीज जो चाइना से हम इंपोर्ट करते थे, वह खिलौना बनाकर आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने खड़ा किया और जब विकसित भारत बनेगा तो जब तक विकसित छत्तीसगढ़ नहीं बनेगा तो विकसित भारत नहीं बनेगा और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उनके सामने में एक विजन आया कि जब तक जो बस्तर है, वह पूर्णत: विकसित नहीं होगा तो

छत्तीसगढ़ पूर्णत: विकसित नहीं हो सकता। एक टारगेट तय किया कि छत्तीसगढ़ को भी विकसित की दिशा के अंदर में ले जाना है और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी हमारे छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं। हमारे विष्णु देव साय जी का यहां पर जैसा नेतृत्व मिला है, हमारे मंत्री लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके अंदर आज जब विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो नक्सल मुक्त बस्तर का टारगेट 2026 रखा और आज हम नक्सल मुक्त की ओर बढ़ रहे हैं। बस्तर हमारा स्वर्ग है। छत्तीसगढ़ का अगर कोई स्वर्ग है, मैं कहता हूं कि लोग केरल घूमने जाते हैं, अन्य स्थानों पर पर्यटनों में जाते हैं, एक बार अगर बस्तर आकर देखें तो उसको लगेगा कि यहां पर कुसुम, महुआ की खुशबू, यहां का जंगल, यहां के अच्छे आदिवासी भाई-बहन, यहां के अच्छे लोग, यहां पर अच्छा खान-पान, उसको देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लगा कि हमको इसको नक्सल मुक्त करना चाहिए और जब नक्सल मुक्त होगा, यह विकास की दिशा में बढ़ेगा तो विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा और बस्तर और सरगुजा का विकास होगा। अभी लता जी इस बात को कह रही थीं, लता जी मैं आप ही की बात कर रहा हूं, अभी कह रही थीं कि विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। मैं सहमत हूं। हर चीजें सारे शिक्षण संस्थाएं रायपुर के अंदर में हैं। उद्योग आएंगे रायपुर के अंदर में। प्रदूषण फैलेगा रायपुर के अंदर में। अगर इसको हम विकेंद्रीयकृत करें, बस्तर के जो लोग हैं, वहां पर जो संस्कार है, वहां की संस्कृति है, उसको कायम रखकर उसका हम कैसे विकास कर सकते हैं, इस दिशा के अंदर में हमारा विजन होना चाहिए। हमारा विजन यह होना चाहिए कि वहां की संस्कृति समाप्त न हो, वहां के संस्कार समाप्त न हों। आज हम जब इस बात को कहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ 44 प्रतिशत ग्रीन है तो इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो हमारे आदिवासी भाई बहनों का है। उन्होंने पेड़ पौधों को अपना जीवन माना, अपना मित्र माना, अपना माता-पिता माना और उसको सुरक्षित रखने का काम किया, जिसको आज हम गर्व के साथ में हम कह रहे हैं। वह पेड़ पौधे भी हमारे रहे, लेकिन साथ में वहां पर इंडस्ट्री भी कहीं न कहीं डेवलप हो, उसके लिए हमको वहां के लोगों की पहले मानसिकता बनानी पड़ेगा। हमको मानसिकता बनानी पड़ेगी, सहमति बनानी पड़ेगी, छोटे-छोटे उद्योग के माध्यम से रोजगारयुक्त बस्तर के नौजवान होंगे, इस बात का हमको संदेश देना होगा, इस बात के लिए हमको प्रेरित करना होगा। अगर हम सीधा वहां पर बड़े उद्योग लगा देंगे, बड़े कारखाने वहां पर लगाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। हम छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करके वहां के लोगों की सहमति लें कि आपके जीवन के लिए हित में है, नौजवानों के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में है, आने वाली पीढ़ी वहां रोजगार प्राप्त करेगी। हम इस बात की व्यवस्था करें। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एक लाख करोड़ रूपये से अधिक पैसा बस्तर के अंदर में खर्च करेंगे, हम सरगुजा के विकास के अंदर में खर्च करेंगे, हम वहां पर अच्छी शिक्षण संस्थाएं लेकर आयेंगे, हम वहां पर अच्छे स्वास्थ्य के केन्द्र लेकर आयेंगे, वहां पर अच्छी हाऊसिंग होगी, वहां की पुलिसिंग अच्छी होगी, वहां की ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की पुलिसिंग अच्छी होगी, उसके लिए हमको

कहीं न कहीं व्यवस्था करनी होगी। आज मैं कहना चाहूंगा कि एन.सी.आर. की तर्ज पर एस.सी.आर. बनाया गया है। मैं जब उसको देख था, मैं भी दो बार महापौर रहा हूं। आज हम मास्टर प्लान की बात करते हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त हो रहा है, केन्द्र सरकार हमको पैसा दे रही है, हम आज तेजी के साथ में अनेक योजनाएं लाकर धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक हम इसकी छोटी-छोटी चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। हम एस.सी.आर. लेकर आए हैं। आपका मास्टर प्लान कहां है? वह मास्टर प्लान कब लागू होगा? मास्टर प्लान बनेगा तो जोनल प्लान कब बनेगा? आज अगर रायपुर की दुर्दशा हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है, जो हम देख रहे हैं। जोनल प्लान राजधानी है। मुझको यह कहकर दु:ख हो रहा है। मैंने उस समय भी कहा था कि यहां पर जब तक जोनल प्लान को नहीं लायेंगे, उसको सख्ती के साथ में लागू नहीं करेंगे, अगर हम राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक दबाव पर उसको बदलते रहेंगे तो एक अच्छा रायपुर, एक अच्छी राजधानी नहीं बनेगी। मैं जानता हूं कि इस शहर को कहीं न कहीं बनाने का अवसर भी मिला। मेरी पार्टी ने अवसर दिया। यहां जयस्तम्भ चौक की एक-एक सड़क, डिवाईडर विरासत में मिली थी और उस समय हमने कहा था कि इसका अच्छा जोनल प्लान बनेगा, मास्टर प्लान बनेगा तो हम एक अच्छी राजधानी का गठन कर सकते हैं। मैं लता जी की इस बात से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा था कि आज बस्तर नक्शल मुक्त हो रहा है। देश ही नहीं बल्कि वहां पूरा विश्व पर्यटन के लिए आने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जिस तेजी के साथ में इन्वेस्टमेंट होगा। यहां पर तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट होगा, वहां बड़े-बड़े उद्योग आयेंगे। हमारा एक कलंक था कि वहां बस्तर में कोई नहीं आना चाहता था क्योंकि वह एक नक्सली क्षेत्र है। आज वह हमारा कलंक समाप्त हो रहा है। कल ही अमित शाह जी ने कहा है कि हम बस्तर को देश का सबसे अच्छा संभाग बनायेंगे। यह टारगेट है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यह काम कर रहे हैं। यहां हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, वह भी मेहनत कर रहे हैं कि वहां एक अच्छा वातावरण निर्मित हो। वे बार-बार दौरा कर रहे हैं। आज जब बस्तर नक्शल मुक्त हो रहा है, बड़े-बड़े उद्योगों की नजर छत्तीसगढ़ के अंदर में है। यह खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। यह भगवान की बड़ी मेहरबानी है। खनिज संपदा व इस बात से किसी ने पहचाना है तो वह अटल बिहारी बाजपेयी जी ने पहचाना। इसी कारण से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को अलग बनाकर दिया। यहां के लोग भी मान-सम्मान के साथ रहे, स्वाभिमान के साथ में रहे, इनकी समस्याओं का निराकरण होना इनका हक है, इनके पास में सबकुछ है, उसके बाद भी वंचित है तो इस बात को किसी ने सोचा तो अटल जी ने सोचा था। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर हम नक्सल मुक्त हो रहे हैं, वहां पर फ्लोटिंग पापुलेशन बढ़ने वाली है तो हमको एक मॉडल जगदलपुर बनाना चाहिए। हमको ऐसा जगदलपुर बनाना चाहिए, जिसका विस्तार भी करना चाहिए। जब तक हम उसका विस्तार नहीं करेंगे, उसके अंदर अनेक गांवों को शामिल

नहीं करेंगे तो वह छोटा सा जगदलपुर में न ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, न रोड सिस्टम बनेगा, न नाली सिस्टम बनेगा, न डग सिस्टम बनेगा, न लाईट सिस्टम बनेगा, वहां कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा और जब वहां पर बाहर के पर्यटक आयेंगे तो हमारी जगदलपुर को बाहर के लोग देखेंगे, उसी से उनको समझ में आएगा कि हमारा विकासित छत्तीसगढ़ कैसा है? हमको उसकी विकास की ओर बढ़ना चाहिए। जब तक हम इन परिसीमाओं को नहीं बढ़ायेंगे। जैसे बस्तर के सारे जिलों के सीमाओं को बढ़ाना चाहिए कि वह नगर पालिका और नगर निगम की श्रेणी में आये, कोंडागांव नगर निगम की श्रेणी में आये । ऐसे श्रेणी में आबादी के आधार पर जब इसका फैसला होता है तो उसकी आबादी आसपास के गांवों को शामिल करके बढ़ाई जाती है । हमने रायपुर को किया है, रायपुर के अंदर में लगभग 40 गांवों को हमने शामिल किया है, मैं जब रायपुर का मेयर था तो 27 गांवों को हम ही ने शामिल किया था । यह सीमायें जब बढ़ती है तो महानगर का रूप लेता है और रायपुर भी आने वाले समय में महानगर का रूप लेगा । मेरा इसमें एक सुझाव है कि जितने संस्थान हैं, उसको भी हम जाकर कहीं न कहीं विकेन्द्रीयकरण करें, शहरों के अंदर में सबसे बड़ी चीज है वहां पर मार्केट और मार्केट का भी विकेन्द्रीयकरण करना चाहिये। रायपुर के गोलबाजार में पैदा होने से मरने तक का सामान वहीं मिलता है तो कहीं न कहीं मास्टर प्लान के तहत आने वाले समय में उसका विकेन्द्रीयकरण करें । हम औद्योगिक क्षेत्र का उसके अंतर्गत विकेन्द्रीयकरण करें । हम हाऊसिंग का विकेन्द्रीयकरण करें । आने वाले समय के अंदर में सबसे बड़ी दो समस्या आने वाली है । एक समस्या हमारी ट्रेफिक की आयेगी, दूसरी समस्या हमारी हाऊसिंग की आयेगी । आबादी बढ़ेगी, मकान नहीं है, जमीन खत्म हो रही है, अच्छे मकान उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उस समय रायपुर हो या छत्तीसगढ़ के अन्य शहर हो, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर हो, यह सब जगह आना है । हमारी ट्रैफिक व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसके लिये 28 लाख रूपये देकर भारत सरकार के उपक्रम राईटस कंपनी को हायर किया था । यह बहुत जरूरी नहीं है, हम अपने ही क्षेत्र के लोगों से बात करके समस्या का निराकरण कर सकते हैं । हमारे यहां बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रायवेट पार्टनरशिप लाकर हम उसका विकास कर सकते हैं, मैं उसे गिनाना नहीं चाहूँगा । हमने भी प्रायवेट पार्टनरशिप को लाकर विकास किया है । पीपीपी मॉडल नाम इसीलिये बना है कि एक आदमी के पास पैसा है और काम नहीं है । नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, यहां काम है लेकिन पैसा नहीं है । यह जब दोनों मिलते हैं तो प्रायवेट पार्टनरशिप बनता है । ऐसा काम जब हमारे छत्तीसगढ़ में होगा और तेजी के साथ में होगा, व्यवस्थित काम हो, सबसे बड़ा शक्ति मंत्रालय जो बना है, भारत सरकार ने जो योजना लाई है, उसके अंदर में वर्ष 2047 को जब हम 100 साल पूरा करेंगे, यहां 100 लाख करोड़ रूपया केन्द्र सरकार ने रखा है और उन्होंने कहा है कि एक छत्ते के नीचे सारे विभाग आये । माननीय अरूण साव जी बैठे हैं, आप भी सांसद रहे हैं, आपको भी यह मालूम है । अंडर ग्राऊंड जो सारे काम है, हम उसे पहले करेंगे । नाली बनाना है तो नाली बनायेंगे, पाईप लाईन डालना है

तो पाईप लाईन डालेंगे, डक सिस्टम बनाना है तो डक सिस्टम बनायेंगे । ड्रेनेज सिस्टम बनाना है तो ड्रेनेज सिस्टम बनायेंगे । लाईट सिस्टम लागू करना है तो लाईट सिस्टम लागू करेंगे और आखिरी में हम सड़क बनायेंगे । वह जो सड़क बनायेंगे, वह आने वाले 35-40 सालों तक टिकाऊ रहे, इसके लिये एक व्यवस्थित विकास, उसकी कार्ययोजना, यह जब तक हमारे आने वाले समय के लिये नहीं बनेगी तो विध्वंश और विकास में से विध्वंश ज्यादा होगा तथा विकास कम होगा और पैसे की हमेंशा कमी रहेगी । अगर विध्वंश नहीं होगा तो स्थायी विकास होगा और जितना पैसा हमारा है, वह खर्च करके इंन्फ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं । मेरा यही सुझाव है कि आने वाले समय में जो समस्यायें हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा, इसे सभी ने रखा है । मैं अरूण साव जी से आग्रह करूँगा कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आप भी उपस्थित थे, मैं उस समय सांसद था, विधायक भी थे, हमने कहा था कि आने वाले समय के अंदर में हम तात्यापारा से आजाद चौक तक चौड़ा कर देंगे। मैं उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, मुझको इस बात का दुख होता है कि मैंने आमानाका से वहां तक पहुंचा दिया था, उस समय भी मुझसे किसी अधिकारी ने कहा था कि पैसा नहीं है। मैने 70/30 में लोन लेकर उस सड़क का चौड़ीकरण करके वहां तक पहुंचाया था, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन आज 18 साल बीतने के बाद भी मुझे एक विधायक के तौर पर यहां बात करना पड़ रहा है। 18 साल बीत गए हम 200 मीटर नहीं बढ़ पाए, ये आवश्यकता है, आज शहर के अंदर चौड़ी सड़कों के साथ हमको फ्लाईओवर की भी प्लानिंग करनी होगी तब जाकर हम एक अच्छी राजधानी, अच्छे शहरों को डेवलप कर पाएंगे। उप मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि नगर पंचायत, नगरपालिका, इस स्तर में भी हमारा मास्टर बने, ताकि आने वाले समय के अंदर जो नगर पंचायत है, वह नगरपालिका में जाएगा, नगर पालिका नगर निगम के अंदर जाने लायक होगा, एक अच्छा मास्टर प्लान बनेगा। हमारे पास अभी से यह कल्पना होनी चाहिए। जब हम उसके आस-पास के गांव को उसके अंदर समाहित करेंगे तो ये जाकर कैसा शहर बनेगा, आप पंजाब जाईए, मैं लगभग पूरा प्रदेश घूमा हूं, जो बड़े-बड़े शहर हैं, घूमने के अनेक स्थान हैं, पर्यटक केवल बस्तर के लिए नहीं आएंगे, पर्यटक बिलासपुर भी जाएगा, पर्यटक राजनांदगांव भी जाएगा, कवर्धा भी जाएगा, सुनेगा वहां पर मंदिर है, आस्था का केन्द्र है, डोंगरगढ़ भी जाएगा, रतनपुर भी जाएगा, जब हर जगह जाएगा तो उसके लिए कहीं न कहीं हमारे पास एक ऐसा मास्टर प्लान हो कि इन सारे क्षेत्रों का विकास हम तेजी के साथ करें, केन्द्रित विकास न करके, हम विकेन्द्रित विकास को करेंगे तो आने वाले समय में हमारा एक विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अभी 10 लोगों की बात रखी जानी है, अत: अपनी बात को संक्षिप्त में 5-5, 10-10 मिनट में रखिए। मैं ऐसा आप सबसे सहयोग चाहता हूं।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे इस नये विधान सभा के सदन में भवन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है। हम शीतकालीन सत्र के दौरान इस नवीन विधान सभा भवन में उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि एक चर्चा शायद जिसके विषय में होनी चाहिए थी वह यह कि जब हम सदन के उपर देखेंगे तो जिन धान की बालियों के नीचे हम बैठे हुए हैं और छत्तीसगढ़ महतारी जिनको हम धान का कटोरा भी कहते हैं और जिसकी चर्चा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने उनका ध्यानाकर्षित किया था, ऐसे पवित्र सदन में आज हम बैठे हैं, हमें इस सदन में एक सदस्य के रूप में पहली बार बोलने का अवसर मिल रहा है, वह भी इतने अच्छे विषय पर यहां पर चर्चा हो रही है जो छत्तीसगढ़ का भविष्य और छत्तीसगढ़ का विजन तय करने वाला है। अंजोर छत्तीसगढ़ 2047 में हमें बोलने का अवसर मिला है। माननीय सभापति महोदय, ये विजन डॉक्यूमेंट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक विजन नहीं है बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को जिन ऊंचाईयों पर और भारत के नक्शे पर जो प्रमुख स्थान में देखना चाहते हैं, शायद उस विषय की आज ये चर्चा है। उस विषय की चर्चा की शुरूआत करने के पहले मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो दूरदर्शिता थी और कहीं न कहीं उनका जो उस समय का विजन था, जब मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ को एक नये राज्य का दर्जा मिला, आज छत्तीसगढ़ 25 साल का युवा हो गया है। सन् 2000 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन था, उस कारण से आज इस नये सदन में और नये छत्तीसगढ़ का निर्माण जो आज हुआ है, वह उनकी देन है, मैं उनको सभा के माध्यम से सदन के माध्यम से अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूं। सभापति महोदय, जब विभिन्न विषयों पर छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है, विभिन्न सदस्यों ने अपना ध्यानाकर्षित किया, बहुत सारे विषय जो भविष्य में होने चाहिए, उस पर चर्चा हुई। अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में थोड़ा जाएं तो मुझे लगता है कि इतिहास को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें भविष्य ठीक करना है तो कहीं न कहीं इतिहास की भी जानकारी और इतिहास को भी दिमाग में रखना जरूरी है। जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना, हम सब जानते हैं कि भूख से छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मौतें होती थी। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि पलायन की संख्या सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ राज्य में थी। यहां न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य था, न ही सुरक्षा और न ही सड़क की व्यवस्था थी। अंधकार में हमारा छत्तीसगढ़ था। जहां भय और अहिंसा प्रमुखता से अपना स्थान रखते थे। उसके बाद वर्ष 2003 का समय आया, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार

छत्तीसगढ़ में बनी और आज जो हमारे अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं, हमारे विधान सभा अध्यक्ष, जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली और भाजपा को पहली बार छत्तीसगढ़ में मार्गदर्शन करने और अपने विजन को प्रस्तुत करने का मौका मिला। जिस तरीके से 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सुशासान के 15 साल में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ने भारत के नक्शेमें अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, कहीं न कहीं आज विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा हो रही है, मुझे यह लगता है और मेरा यह मानना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके साथ हमारे वित्तमंत्री जी की दूरदर्शिता में जो विजन हम लेकर चल रहे हैं-2047, निश्चित ही हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। महोदय जी, वर्ष 2003 की उपलब्धियों की मैं थोड़ी सी चर्चा इसलिए करूंगी कि आने वाले समय में जो माइलस्टोन भाजपा ने सेट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के कार्यकाल में जो अपनी उपलब्धियों का एक माइलस्टोन सेट किया है, कहीं न कहीं उस माइलस्टोन को आगे ले जाने का काम आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करने वाले हैं। महोदय जी, उस समय जब वर्ष 2003 में भाजपा की सरकार आई तो पहली बार किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया। जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक निर्णय उस समय की सरकार का था। फसल उपार्जन में उस समय अभूतपूर्व वृद्धि हुई। साथ में धान की खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 70 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय के कार्यकाल की थी। 1 रूपये किलो में चावल का जो वितरण हुआ, छत्तीसगढ़ उसका पहला मॉडल बना। जिसका बहुत सारे अन्य राज्यों ने अनुसरण किया। सरप्लस बिजली वाला सबसे पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बना। जिसमें हमें जीरो पावर कट राज्य का दर्जा मिला। उसके अलावा अनेक स्कूल, जिसकी अन्य सदस्यों ने भी चर्चा की। अनेक स्कूल, कॉलेज, आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स जैसी जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, वह हमारे छत्तीसगढ़ में आईं। जिसका लाभ हमें मिला। चाहे हम कोरोना के समय की बात करे। हम सबको ध्यान होगा कि जो एम्स खुला, उसका विजन उस समय जो था, उसका लाभ हमको जाकर वर्ष 2019-20 में कोविड के समय मिला। जिस तरीके से वहां के डॉक्टर्स ने लाखों-हजारों जिंदगियां बचाईं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ से सटे हुए बहुत सारे राज्यों से वहां पर पेशेन्ट्स आकर कोरोना के समय उन्होंने यहां पर स्वास्थ्य का लाभ लिया। इन्हीं विषयों को लागे बढ़ाकर जब हम वर्ष 2047 की चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सुनहरे 15 साल के कार्यकाल की चर्चा जरूर होनी चाहिए। आज जिस विजन डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं-अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि आने वाले छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम युग की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसका हम सबका एक विजन है। सभापति महोदय जी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं कि वर्ष 2047 में भारत कैसा होगा? लेकिन जब इसकी शुरूआत में हम जाए तो शायद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा होगा कि हर गांव तक बिजली पहुंचे, हर घर

तक शौचालय जाये, हर गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य का लाभ मिले, पहली बार ऐसा किसी ने सोचा होगा कि हर महिला को उज्जवला गैस का लाभ मिले, उसे गैस सिलेण्डर मिले, जिससे उसको स्वास्थ्यगत लाभ हो, उसकी समय की बचत हो, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि किसी युवा के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल हो, जो आज भारत की पहचान बन चुकी है तो निश्चित ही जो विजन डॉक्यूमेंट हम लेकर चल रहे हैं, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ ने उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विजन 2047 के विषयों पर हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया है। कहीं न कहीं उसके जो प्रमुख बिंदु हैं, उसकी 13 थीम तय की गई है। जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मंत्र है, मुझे लगता है कि उस 13 थीम की चर्चा यहां पर एक बार जरूर होनी चाहिए। जिसमें सबसे प्रमुखता से हैल्दी एण्ड हैप्पी छत्तीसगढ़, दूसरा है-टूरिज्म एवं कल्चर इनोवेशन, तीसरा है-स्टेट ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड स्कील, डिजिटल सिटीजनशिप, स्टील एंड इंडस्ट्रीयल ड्रिवन इकोनॉमी, क्लीन एंड ग्रीन छत्तीसगढ़, न्यू जनरेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप इन्वेस्टमेंट, फॉर्मिंग एंड एग्री इनोवेशन, ट्रायबल वेलफेयर एंड एक्टीविटिज, आर्ट एंड द कल्चर की नई पहचान, वीमन इम्पॉवरमेंट, गवर्नेंस फॉर लास्ट माइल डिलीवरिज। ये जो 13 प्रमुख चीजें हैं और कहीं न कहीं जब हम बजट की ओर देखते हैं तो इन्हीं थीम को छूता हुआ जो हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो विजन 2030 तक और वर्ष 2030 से 2047 तक जो 3 स्टेप में बांटा गया है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इसका क्रियान्वयन आने वाले समय में सरकार के सभी मंत्रियों के द्वारा, साथ में सभी लोगों के द्वारा जरूर किया जाएगा। महोदय जी, जब हम छत्तीसगढ़ के GDP की बात करते हैं तो आज वर्तमान में हमारी जो GDP है, कहीं न कहीं उसे बढ़ाकर वर्ष 2047 का जो विजन है, उसमें 75 लाख करोड़ रूपये की बात की गई है। यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारी जी.डी.पी. 98 हजार करोड़ रूपये है, जिसे 2047 में 10-11 लाख करोड़ रूपये तक पहुंचाने की बात की गयी है। यदि हम उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो 2.13 लाख करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2047 तक इसे 25-26 करोड़ रूपये करने की बात की गई है। यदि हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो 1.72 लाख करोड़ रूपये से बढ़ाकर उसे 37 से 39 लाख करोड़ रूपये तक बढ़ाने की बात की गई है। यह कहीं न कहीं जो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, मुझे विश्वास है कि इस प्लानिंग के तहत जो हमारी 2047 की जी.डी.पी. है, हम निश्चित ही उसे प्राप्त कर पायेंगे। मृत्यु अनुपात जो 137 है, उसे 10 से भी कम किये जाने का प्लान है। साक्षरता दर में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाने की जो बात कही गई है, उसे 2047 तक 99.9 प्रतिशत बढ़ाने की बात कही गई है। महिला श्रमिकों की सहभागिता की जो बात की गई है, जिसे हम महिला empowerment के तहत जोड़कर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, 2047 तक इसका क्रियान्वयन जरूर होगा। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि कुछ विषय है जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर पहले भी सदस्यों ने

चर्चाएं की हैं, मैं उस विषय को भी यहां पर जरूर इंगित करना चाहूंगी क्योंकि हम सब को जनता ने चुनकर यहां पर भेजा है और निश्चित ही जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से कुछ उम्मीदें और कुछ विश्वास रहता है तो मुझे लगता है कि कुछ विषय और है जो इसमें शामिल होने चाहिए या जिस पर विचार होना चाहिए, मैं उन विषयों को जरूर एक बार रखना चाहूंगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक है आपका रूरल एरिया और एक है आपका अर्बन एरिया। हम जितने प्रोजेक्ट्स की बात करें तो निश्चित ही पिछले दो सालों में बहुत सारी गारण्टियों को, जिसे मोदी जी की गारण्टी कहते हैं। जैसे हम महतारी वंदन योजना की बात करें, हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे अन्य विषयों की बात करें तो उसमें लगातार काम हो रहा है। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा के साथ-साथ ऐसे बहुत सारे वनांचल क्षेत्र हैं, जैसे मैं जिस पंडरिया विधान सभा से आती हूं। महोदय जी, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया ट्राइबल भाई-बहनों का है। मुझे लगता है कि जो प्लानिंग हमारे बस्तर और सरगुजा के आदिवासी भाई-बहनों के लिये हो रही है, कहीं न कहीं अन्य क्षेत्रों में तुलनात्मक बाकी जगहों का कुछ हिस्सा डेव्हलपमेंट के लिए जरूर देना चाहिए। चाहे वह पर्यटन हो या अन्य स्थल हो। जहां तक पर्यटन की बात करें तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे स्थल हैं, जो आज कहीं न कहीं उपेक्षित है। बहुत सारे पुरातत्व विभागों की चर्चा हुई। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वहां भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जहां आज भी पुरातत्व की चीजें जानने समझने को मिलती है लेकिन शायद हमारा विभाग आज भी वहां तक पहुंच नहीं पाया है। ऐसे बहुत सारे डेव्हलपमेंट हैं, जैसे उदाहरण के लिये मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने भोरमदेव कॉरिडोर की शुरूआत की और भोरमदेव को नई पहचान दिलाने की शुरूआत की। मैं इसके लिए उनका बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी लेकिन साथ ही साथ एक विषय जरूर जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके से भोरमदेव में काम हो रहा है, उसी तरीके से हमारे अन्य जो धार्मिक स्थल है, जिन्हें धार्मिक आस्था का केन्द्र बनाकर सभी सदस्यों से उनके स्थान के सिर्फ एक-एक नाम लिये जाये, जहां पर काम होने चाहिए। चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में हो चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में हो। उनसे कम से कम एक नाम जरूर लिया जाये।

सभापति महोदय, दूसरा विषय स्वास्थ्य को लेकर हमारी चिंता है। हम सभी चिंतित है। जैसे मैंने कहा कि रूरल और अर्बन, यदि हम दो तरीके से क्षेत्रों को डिवाईड करें और आज अगर हम जिले को प्रमुख स्थान बनाकर चले, जैसे उदाहरण के लिए बिलासपुर जिला है और बिलासपुर जिले में यदि तीन विधान सभा क्षेत्र आते हैं या चार विधान सभा क्षेत्र आते हैं। उदाहरण के लिये जैसे कर्वधा जिला है और उसमें दो विधान सभा क्षेत्र आते हैं तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि सिर्फ जिला को हर चीज का सेंटर न बनाया जाये बल्कि उसके आस-पास जो ब्लॉक हैं, जिस पर माननीय लता उसेण्डी जी ने भी चर्चा की थी, उस पर प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि हर जिले की अपनी एक क्षमता है। चाहे जमीन की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें तो मुझे लगता है कि उनकी अपनी क्षमता है। इसलिए मुझे लगता है कि

सिर्फ जिले को चिन्हांकित न करके आस-पास लगे हुए जो ब्लॉक हैं या जो एरिया है, उन पर भी एक बार आने वाले समय में चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें या फिर अन्य विषयों की बात करें, तो बाकी जगहों पर भी फोकस होना चाहिए।

सभापति महोदय, तीसरा विषय स्कूल को लेकर आता है। मैं अभी पिछले दो दिन पहले ही एक स्कूल में गई थी। एक जगह पंचायत में हमारा कार्यक्रम था। मैं जब उस स्कूल में गई तो वहां जाने के बाद 2.15 बजे का समय हुआ था। लंच ब्रेक 1.30 बजे से लेकर 2.00 बजे तक होना था परंतु 2.20 हो चुका था। वहां पर बेल नहीं लगी थी और क्लास रूम में ताले लगे थे। कैमरा चल रहा है लेकिन कैमरे की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। जब मैं वहां गई तो चूंकि जनप्रतिनिधि आई हैं इसलिए टीचर ने बच्चों को बहुत हड़बड़ी में बुलवाया। जब मैंने उन्हें क्लास में बुलाकर उनसे चर्चा की कि आपके लैब्स कहां है ? वह 11वीं और 12वीं क्लास के साइंस के बच्चे थे और साइंस के बच्चों को जब मैंने बोला कि आपकी बायोलॉजी की lab कहां है, आपकी अन्य labs कहां हैं, आपकी फिजिक्स lab कहां है? जब हम उनके lab में गये तो चार माइक्रोस्कोप रखा हुआ था। जब मैंने शिक्षक से पूछा तो उसने कहा कि मेडम ये 4 माइक्रोस्कोप हैं, इसमें हमारा काम हो जाता है। चूंकि मैं भी साइंस की छात्रा रही हूं तो मुझे इंट्रेसट आया कि माइक्रोस्कोप सामने है, चलो इसमें हम कुछ देखें, समझें, कुछ सीखें। जैसे ही मैंने उसमें देखा तो टीचर ने तुरंत बोला कि मेडम ये काम नहीं करता है। ये बहुत पुराना है, एक्सपायरी हो चुका है, इसलिए हमने इसे निकालकर रखा है। महोदय जी, यही स्थिति है, मैं सिर्फ एक विद्यालय का उदाहरण दे रही हूं। मुझे लगता है कि इसके बजाय हम बहुत बड़ी-बडी योजनायें पहले लायें, धरातल पर जो हमारी चीजें हैं, कम से कम हर विधानसभा में या हर जिले में 5 ऐसे माडल स्कूल हम बनाने की बात करें, बजाय इसके कि हम बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी लायें। हम सिर्फ 5 माडल स्कूल को चिन्हांकित करें, 5 माडल स्कूल हर जिले में हो, जिसमें देखने से, जिसको सुनने से, जिसको समझने से, जहां बच्चों के विजिट कराने से बाकी शिक्षक का भी ज्ञान अर्जित हो और छोटे स्कूल उन चीजों से अपना मार्गदर्शन ले सकें। मुझे लगता है कि स्कूल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सभी मुझसे सहमत होंगे। हम जो नई उद्योग नीति, नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, उसका क्रियान्वयन भी जमीनी स्तर पर, एक-एक ब्लाक स्तर पर हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आज भी हमारे वनांचल क्षेत्र हैं, जहां पर चाहे बिजली, पानी की बात करें, चूंकि चढाव वाला क्षेत्र है, वहां आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है। हम 2047 की बात कर रहे हैं तो आने वाले समय में ऐसा न हो कि हमारा वह वनांचल क्षेत्र 2047 तक भी पानी के लिये तरसता रहे। तो ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हांकित करके मुझे लगता है कि उन क्षेत्रों के लिये कुछ योजनायें जरूर बननी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसमें तीसरा विषय है, हालांकि मैं मांग नहीं रख रही हूं। चूंकि विषय चर्चा का है, इसलिए ध्यानाकर्षित मैं जरूर करना चाहूंगी। हमारे क्षेत्र में बहुत पुरानी कुछ समस्यायें थीं, जैसे हाफ नदी परियोजना है, मैं उसकी चर्चा जरूर यहां करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस पर जरूर कुछ क्रियान्वयन हो, हाफ नदी की बहुत पुरानी मांग है आज भी लोग जिसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कभी उसकी चर्चा नहीं हुई। उसके अलावा मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आऊंगी। मैं वही कहना चाहूंगी कि आज भी जो हमारे छोटे हॉस्पिटल ब्लाक स्तर पर हैं, वहां आज भी सोनीग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन के लिये भी हमारे मरीजों को तरसना पड़ता है। पैसे खर्च करके उनको आज भी जिले तक आना पड़ता है। जो ब्लाक मुख्यालय है, कम से कम वहां ये बेसिक सुविधायें हों, तब हम कह सकते हैं कि वाकई में शार्ट टर्म, लांग टर्म विजन की जिसकी बात करते हैं कि 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा होगा, उस विजन तक पहुंचने के लिये छत्तीसगढ़ के छोटे-छोटे गावों में, कस्बों में, ब्लाक में भी हमारा कार्यों का क्रियान्वयन हो तो वाकई में हम जो विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम जरूर उस उपलब्धि तक पहुंच पायेंगे। जिस तरीके से 2047 का विजन लाया गया है, मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, उसे पूरे करने का प्रयास कैसे करेंगे। जो सपना हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और हम सबने मिलकर के देखा है कि छत्तीसगढ़ 2047 में कैसा होना चाहिए। विकसित भारत के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ भी बने, उसके लिये हमने जो विजन लाया है, इस बात का हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मागदर्शन में हम सब उन ऊंचाईयों को जरूर एचीव करेंगे। इस पवित्र सदन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत अभिंनदन करके, फिर से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूं जिसके मार्गदर्शन में हम सब अपने क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अभिंनदन।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ अंजोर विजन- 2047 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। छत्तीसगढ़ एक राज्य भर नहीं है, इस देश को उत्तर और दक्षिण से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब हम उत्तर छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो जहां अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी का असर हमारी भाषा में दिखाई देता है। वहीं जब हम दक्षिण छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं तो द्रविड़ परिवार की भाषाओं का असर देखने को मिलता है तो यह महत्वपूर्ण कड़ी है। जब भारत 2047 में कहां होगा तो ये महत्वपूर्ण कड़ी इस भारतवर्ष को कहां तक लेकर जाती है तो ये पूरी दुनिया देखेगी और इसके लिये ये डॉक्यूमेंट आया है जिसे छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 का नाम दिया गया है। माननीय सभापति जी, आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज इस विधान सभा में सबकी सहभागिता के लिये 25 वर्ष हो रहे हैं और आज ऐतिहासिक दिन है, जब हम लोग एक नये भवन में आज एक नयी शुरूआत कर रहे हैं और एक नयी भावना के साथ शुरूआत कर

रहे हैं और ऐसे में विपक्ष का यूं चर्चा से भाग जाना, यह बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे लोकतांत्रिक मैदान में लोग रण छोड़कर चले जायें यह छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता देखेगी, समझेगी ।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबके साथ, सबका विकास को अपना मंत्र माना है और यह 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है अंजोर । छत्तीसगढ़ अंजोर, इस पर मैं बात करूंगा कि आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां हम आने वाले 23 वर्ष बाद के विषय में सोच रहे हैं, 2047 के बारे में और मैं इसके पहले एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि सन् 1929 में लॉर्ड इर्विन ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव किया था तब भारतवर्ष ने नकार दिया था और पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी और आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि माननीय विधायक जी के इसमें डोमिनियन स्टेट की बात आयी है तो कांग्रेस पार्टी बहुत बात करती है कि हम लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है । आज बेचारे नहीं हैं, परिवार की लड़ाई लड़ने गये हैं लेकिन कांग्रेस का इतिहास 3 खंड में पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है, उसमें उन्होंने स्वतंत्रता की मांग ही नहीं की है । उसके इतिहास की प्रस्तावना में लिखा है कि डोमिनियन स्टेट की मांग के लिये कांग्रेस बनी है करके ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि भारत न ही किसी देश पर निर्भर है और न ही आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम 2047 की भी तैयारी कर रहे हैं । माननीय सभापति जी, हमन छत्तीसगढ़िया हवन । हमन कुलुप अंधियार के बात ला नइ करन, हमन अंजोर के बात ला करथन अऊ एखरे सेती हमर विजन डॉक्यूमेंट 2047 चर्चा में हे, जेकर नाम हे छत्तीसगढ़ अंजोर । मोला बहुत अच्छा पंक्ति याद आत हे - फिटिक अंजोरी निर्मल छईंया गली-गली बगराओं वो, पुन्नी के चंदा मोर छत्तीसगढ़ मा । वह उजियारा, वह अंजोर, वह प्रकाश की बात छत्तीसगढ़ के इस अंजोर डॉक्यूमेंट में है लेकिन इस शब्द अंजोर को मैं एक अलग नजरिये से देखता हूं । ANJOR, A- आत्मनिर्भर, N-निवेश, J- जनभागीदारी, O-अपॉर्चुनिटी, R-रिसर्च एण्ड रिफॉर्म्स । यह डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है जिसमें आने वाला 23 वर्ष में छत्तीसगढ़ कहां होही, ये देश के विकास में का योगदान दिही ? एखर बर बात होत हे ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ मैन्युफैक्चरिंग मिशन की संकल्पना को लेकर यह डॉक्यूमेंट है । आज जी.डी.पी. में 45 प्रतिशत योगदान हमारे उद्योगों का है, मैं विस्तार से अपनी बात रखना चाहता था लेकिन आज समयाभाव है, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगा लेकिन मैं कुछ बातें अवश्य कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलवाद का उन्मूलन हुआ ऐसा ही भविष्य में कुपोषण का भी उन्मूलन होना चाहिए । छत्तीसगढ़ के लिये एक महत्वपूर्ण

समस्या है और उसके लिये भी इस विजन डॉक्यूमेंट में बराबर तैयारी की गयी है । मैं माननीय वित्तमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा, जिनकी दूरदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डॉक्यूमेंट में दिखाई देती है ।

समय
4.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, विजन 2047 कोई तारीख नहीं है यह विजन 2047 एक विश्वास है, विजन 2047 एक प्रतिज्ञा है। विजन 2047 वह क्षण है जब पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में उजला सितारा बनेगा। आज हम इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं और इसके पीछे हमारी विरासत है और सामने हमारा विजन है और बीच में खड़ी है हमारी आज की मेहनत, नीति और नियत। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस विकास की लड़ाई को लड़ने की हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले की पीढ़ियां हमें एक आजाद भारत सौंप कर गई थी और अगली पीढ़ी यानी हमारी अगली पीढ़ी को एक विकसित समृद्ध उज्जवल छत्तीसगढ़ सौंपने की जिम्मेदारी हम सभी की है। माननीय सभापति महोदय, जब वर्ष 2047 आएगा तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि उन्होंने सिर्फ सपनें नहीं देखें, सपनों को योजनाओं में बदला और योजनाओं को जमीन पर उतारा और छत्तीसगढ़ की अंजोर से दुनिया को प्रकाशित किया। मैं विभिन्न विभागों के विषय में बात करूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आने वाले भविष्य में उद्योगों के विकास के साथ-साथ पर्यावरण के साथ संतुलन और श्रमिकों के अधिकार को भी ध्यान में रखकर, यह अंजोर डॉक्यूमेंट बनाया गया।

"अभी तो राह में कांटे हैं हम डरने वाले थोड़े हैं
हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी से हैं लोहे जैसे कड़े हैं
अभी तो सिर्फ अंजोर बोया है कल यह उजाला दुनिया देखेगी
यह सिर्फ विजन नहीं यह पीढ़ियों की किस्मत लिखेगी।

हम वक्त के मोड़ पर झुकते नहीं, उसे मोड़ कर आगे बढ़ जाने वाले लोग हैं। तो हम विजन 2047 की बात नहीं करते, हम विजन 2047 को अपनी ओर बुलाने वाले लोग हैं।

सभापति महोदय, मैं आज इस ऐतिहासिक दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को पुन: अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर जो यह अंजोर डॉक्यूमेंट बनाया है और पूरे देश और छत्तीसगढ़वासियों के समक्ष अपना रोडमैप रखा है। क्योंकि यह ऐसी सरकार है जो समयबद्ध तरीके से काम करने वाली है, यह सरकार संकल्प लेकर काम करने वाली है जो यह कहती है कि हम 31 मार्च, 2026 को नक्सलवाद समाप्त कर देंगे और उस तारीख तक करने वाली सरकार है तो निश्चित पूरा देश, पूरी दुनिया यह मानकर चलें कि इस अंजोर डॉक्यूमेंट में जो बातें

हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ साबित करके रहेगी और अपना योगदान देगी। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद्। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सुशान्त शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्।

सभापति महोदय, अगर छत्तीसगढ़ को कहा जाये कि संभावनाओं का गढ़ है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। एक पंक्तियां छत्तीसगढ़ के साथ गुंजती हैं, वह यह है :-

"वह कहते हैं कि हमें इश्के बुखार है और कहते हैं हममें लावा ला ज्वाल है
राह से भटका हुआ मुसाफिर न समझना हमको
और मंजिल भी हमें कहती है तेरा इंतजार है।।

लेकिन जब छत्तीसगढ़ को संभावनाओं का गढ़ माना जाये तो छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की इस अविरल गाथा या गंगारूपी गाथा को लिखने में जब कलमकार लिखेंगे तो नक्सलवाद के उस कुरूप चेहरे को भी लिखा जायेगा और पिछले 5 सालों की विसंगतिपूर्ण सरकार ने जो भ्रष्टाचार का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, वह भी उन पन्नों में अंकित किया जायेगा। आज छत्तीसगढ़ को क्या आवश्यकता है ? 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा यह छत्तीसगढ़ है व्यावाहरिक तौर पर उन राज्यों के साथ बाजार स्थापित कर सकता है क्या? क्योंकि आज विकास किसी एक चीज का मोहताज है तो वह बाजार का है और अगर बाजार चाहिए तो छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी । चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है । 2047 तक हमारा उद्देश्य है कि कृषि केवल आजीविका का साधन न हो, बल्कि आर्थिक शक्ति और नवाचार का भी केन्द्र बनकर उभरे, परन्तु देखने में क्या मिलता है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ सिंगल क्राप राज्य की तरफ बढ़ता जा रहा है । अगर हम देखें कि एक फसलीय राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दूसरे फसलों को हम लेने की जहमत नहीं उठाते । रबी की फसल में जो जल संकट पैदा हो रहा है, उस संकट से भी हम रोज दो चार हो रहे हैं । हम लघु वनोपज की बात करें तो वनाच्छादित होने के कारण छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की नैसर्गिक प्रचुरता है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से वनोपज और औषधि पौधों की अर्थव्यवस्था को नवाचार और वैल्यू चेन देने के लिए भी जो चेन बननी चाहिए, उसकी सार्थकता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । जब हम लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ अंजोर तो वन क्षेत्र को हटाकर इस नवा अंजोर की परिकल्पना नहीं की जा सकती । तो प्रयास क्या होने चाहिए ? वन क्षेत्र तो बचे हीं, साथ में एग्रो फारेस्टिक पर भी छत्तीसगढ़ राज्य प्रयास करे और वनोपज की व्यवस्था एग्रो फारेस्टिक के माध्यम से उन क्षेत्रों में भी बढ़े, जो छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव का क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र है, जहां पर कृषि आधारित सिर्फ एकल फसलीय व्यवस्था है, उस पर एग्रो फारेस्टिक की बात आनी चाहिए ।

सभापति महोदय, जब हम शिक्षा और कौशल विकास की बात करते हैं तो शिक्षित समाज, समृद्ध राष्ट्र का आधार है । बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता

है, वह भी शेर बनकर ही निकलता है । तो शिक्षा के अभाव में जब यह तंत्र छत्तीसगढ़ का मंत्र बनकर भारत में गूंजे, उसके लिए शिक्षकों को उत्कृष्ट अवसर, डिजीटल संसाधन, नवीनतम कौशल से लैश हों, व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दो । मैं आपके माध्यम से मंत्रिपरिषद से यह आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग भी खोली जाये । मैं आपके माध्यम से मंत्री परिषद से यह भी आग्रह करूंगा कि तकनीकी शिक्षा में आईटीआई जैसे छोटे प्रकल्प हैं, उनको विदेशी कम्पनियों के साथ जोड़कर उनकी भाषाओं का संवाद और उनकी तकनीकी से रूबरू करायी जाये, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें ।

सभापति महोदय, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वस्थ नागरिक ही समाज की नींव होती है । उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि डिजीटल स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत के साथ-साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए, परन्तु देखने में क्या मिलता है कि हम उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजनीतिक कारणों से खोल देते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । आप आवश्यकता के आधार पर खोलें, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम वह बुनियाद हासिल कर सकें, जिसके ऊपर रहकर हम छत्तीसगढ़ की नवीनतम छत्तीसगढ़ के भव्य ईमारत की परिकल्पना करते हैं । मातृ शिशु एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण उन्मूलन जो मेरे साथी अनुज शर्मा जी कह रहे थे, मानसिक स्वास्थ्य, डिजीटल स्वास्थ्य नेटवर्क का व्यापक विकास होना चाहिए । जब हम निवेश के क्षेत्र में बात करते हैं तो एमएसएमई जैसी योजनाओं में छत्तीसगढ़ के युवाओं को अगर हम लोन दे रहे हैं तो लोन के पहले ही दिन हम उसको कर्जदार बनाने की चिन्ता करते हैं । वह कैसे करते हैं, वह मैं आपको बताता हूं । 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगाकर हम उसको कर्ज दे रहे हैं और एक लाख रूपए उस पूरे लोन का एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी अपने ही राज्य के युवाओं से हम बगैर लाभ के लाभांश के हम प्राप्त कर लेते हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो एमएसएमई योजना लघु उद्योग, मध्य, सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो लोन सब्सिडी आधारित दी जाती है, उस पर एक प्रतिशत का स्टाम्प ड्यूटी है, वह उससे उन युवाओं को मुक्त किया जाये, जो छत्तीसगढ़ में नए उद्योग डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उद्योग खोलने जा रहे हैं ।

सभापति महोदय, लॉजिस्टिक की बात हुई है । भौगोलिक स्थिति और कनेक्टिविटी राज्य की ताकत है । ये सर्वविदित है । हम संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर पर काम करते हैं तो जब छत्तीसगढ़ की परिकल्पना लॉजिस्टिक के आधार पर हो तो वायु क्षेत्र को भी उससे दूर नहीं रखा जा सकता है। जैसे धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि वर्तमान में रायपुर ही एक ऐसा एयरपोर्ट है, जिसकी कनेक्टिविटी है। दूसरे विमानपत्तनों को उसकी कनेक्टिविटी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्रिमण्डल से आग्रह करूंगा, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिलासपुर एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में स्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। एयरोनाटिकल मेन्टनेंस के लिए

बिलासपुर का एयरपोर्ट को विकसित किया जाये। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बिलासपुर के एयरपोर्ट को क्यों विकसित किया जाये क्योंकि एमरजेंसी लैण्डिग के लिए अभी रायपुर के अतिरिक्त पास में कोई एयरपोर्ट ऐसा नहीं है, जहां कोई एमरजेंसी लैण्डिग की व्यवस्था बनें।

श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा :- लास्ट लैण्डिग नहीं है, नन्दिनी नगर, अहिवारा में एयरपोर्ट है, उसको संचालित करें, वहां पर व्यवस्था दें, सुधार करें। निश्चित तौर पर अहिवारा विधान सभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य ने एक विषय उठाया है, परन्तु मैं एक जानकारी देता हूं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अपने नियम होते हैं। उन नियमों के अधीन रहते हुए बिलासपुर का एयरपोर्ट विकसित किया जा चुका है। थोड़ा उन्नत करने की आवश्यकता है। आपको कार्गो एयरपोर्ट, एयरोनाटिकल मेन्टनेंस या हैंगर के रूप में बिलासपुर एयरपोर्ट को विकसित करेंगे तो उसको बाजार मिलेगा तथा यहां की यातायात सुविधा मजबूत होंगी।

सभापति महोदय, जब उद्योग की बात कर रहे हैं तो उद्योग राज्य की समृद्धि और रोजगार के लिए मजबूत इकाई है। अगर आप देखें कि छत्तीसगढ़ के उद्योग केन्द्र, खासकर जो हमारे औद्योगिक केन्द्र हैं, वह अदद से फायर बिग्रेड के लिए भी तरस रहे हैं। वहां स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। वहां बच्चों के लिए खेलने के मैदान नहीं हैं। वहां औद्योगिक केन्द्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र जैसी सुविधाएं नहीं हैं। यह वर्तमान 25 साल के छत्तीसगढ़ की सच्चाई है। मापदण्ड, प्रावधान दस्तावेजों में उपलब्ध हैं, परन्तु मौके पर उपलब्ध नहीं है। जब आप चर्चा कर रहे हैं तो औद्योगिक केन्द्रों या औद्योगिक क्षेत्रों पर फायर बिग्रेड हों, स्वास्थ्य केन्द्र हों, खेल के मैदान हों, स्कूल हों ताकि वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, उनकी व्यवहारिक व्यवस्था भी खड़ी की जा सकें। छत्तीसगढ़ में आई.टी.आई., ए.आई. अधोसरंचना के बहुत सारे काम चल रहे हैं। नवा अंजोर, कला संस्कृति पर भी ध्यान दे रहा है, मैं उनका पूरा परिशिष्टि पढ़ा हूं। पर्यटन विकास की बात कर रहे हैं। मैं आपको 25 वर्ष पूर्व ले जाना चाहता हूं। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो बिलासपुर का एक बड़ा पर्यटन केन्द्र अमरकंटक होता था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग का एक भी केन्द्र अमरकंटक में संचालित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्रिपरिषद् से आग्रह करूंगा कि अमरकंटक में वह पर्यटन केन्द्र या रेस्ट हाऊस प्रारंभ किया जाये। मैं विजय शर्मा जी की बात सुन रहा था। उन्होंने आग्रह किया है, जमीन आवंटित किया है। लेकिन वह सिर्फ कवर्धा तक सीमित ना हो, छत्तीसगढ़ के लिए बने, इसका आग्रह है।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, भाई वह पूरे भारत वर्ष के लिए होगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जब मध्यप्रदेश था तो पूर्व में विकास में बाधाएं थीं। क्योंकि जिस रायपुर की विधान सभा से आवाज लगा रहे हैं, यहां से भोपाल दूर था हैदराबाद पास था,

जिस रायपुर की विधान सभा से जनता की आवाज उठा रहे हैं यहां से नागपुर, हैदराबाद, रांची पास था, लेकिन भोपाल दूर था। जिस रायपुर की विधान सभा से आवाज लगा रहे हैं यहां से लखनऊ पास था, लेकिन भोपाल दूर था, तब धोती वाले नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इस विकास की व्यवस्था को जन-जन तक पहुंचाने के लिए दलगत भावना से हटकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ अपनी तरूणाई को प्राप्त कर चुका है। अब छत्तीसगढ़ युवा है, जवानी की कहानी भी होती है तो विसंगतियां भी खड़ी होती हैं। तो छत्तीसगढ़ जो अब तक हुआ है, वह विकास कोई कम नहीं है और भारत वर्ष में राष्ट्रिवितियों को संकल्प है, उसका कोई विकल्प नहीं है और वह विकल्प भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से " सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास" के साथ विकास मूलमंत्र आधार लोकतन्त्र के तर्ज पर जनता के बीच में जनता से होकर और जनता के लिए पहुंचने का काम कर रहा है। सभापति महोदय, लेकिन कुछ सुझाव हैं। छत्तीसगढ़ ग्राम की सड़कें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि रेत घाट के टेंडर होते हैं, परंतु पी.एम.जी.एस.वाई. और सी.एम. जी.एस.वाई. की सड़कों की एन.ओ.सी. नहीं ली जाती है। वह 12 टन के दबाव के आधार पर बनते हैं और 50 टन के ट्रक वहां चलते हैं तो ऐसी भी कोई नीति बने कि गांव की सड़कें यातायात के लिए इतनी उपयुक्त बनें कि आने वाले समय में एक लंबे समय तक वह चल सकें। छत्तीसगढ़ की आज दिनांक तक कोई खेल नीति नहीं है। खेल नीति बननी चाहिए, खेल मैदान तय हों, संरक्षित हों, पल्लवित हों, पोषित हों और वह प्रशिक्षण के केंद्र बनकर उभरें, इसके लिए प्रयास हो। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि छत्तीसगढ़ का शहरी स्वरूप जो नगरीय निकाय के रूप में स्थापित है, सभापति महोदय, उनसे लगे हुए निवेश क्षेत्र टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो सबसे बड़ी व्याख्या है कि ग्रामीण निवेश उनसे लगे हुए पंचायतों में ग्रामीण निवेश पर जो आवासीय निर्माण, व्यावसायिक निर्माण हों, उस पर आज योजना बननी चाहिए ताकि जब शहरों के विकास की बढ़ोत्तरी हो, तब वह उस संरचना के आधार पर प्राप्त हों, जिस संरचना के वह हकदार हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। पूर्ववर्ती सरकार ने बिलासपुर में 70 वार्डों के एक नगरीय निकाय की सीमा खींची। 12 पंचायतों को, दो नगर पंचायतों को और एक नगर पालिका को उसमें सम्मिलित किया और एक 5 साल में एक ढेला विकास कार्य के लिए वहां पैसा नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बिलासपुर जाते थे, 100 करोड़ की मांग होती थी, 10 करोड़ की घोषणा होती थी, 60 लाख रुपए नगरीय निकाय के झोले में आते थे। आज मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसे सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों को विशेष पैकेज के आधार पर इस योजना के साथ नवा अंजोर को जोड़ा जाए ताकि हमारे शहरों को एक व्यावहारिक व्यवस्था के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके। कृषि के क्षेत्र में एग्रो फॉरेस्ट्री की मैंने बात की, लेकिन वृक्षारोपण भी एक छत्तीसगढ़ की सच्चाई है। कई लाख पौधे रोपे जा चुके हैं। अगर जितने पौधों की संख्या जोड़ी जाए तो शायद तक हमको खड़े होने की जगह न मिले इतने पौधे रोपे जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है? वृक्षारोपण के नाम पर जो खानापूर्ति

होती है, यह राज्य का अपराध माना जाना चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण के संरक्षण पर काम करने के बजाय जेब के संरक्षण पर काम करते हैं, यह व्यावहारिक व्यवस्था की दिक्कत है और वृक्षारोपण के साथ कोई भी कोताही बरतना हम अपनी पीढ़ियों की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए हम बहुत सारी योजनाओं पर अभी काम कर रहे हैं। जो नवा अंजोर पर काम कर रहे हैं, 2047 की योजनाएं हम बना रहे हैं, परंतु व्यावहारिकता क्या है कि दशकों के लिए बनने की बजाय योजनाएं वर्षों के लिए बनाई जाती हैं और जब सत्ता बदलती है तो योजनाओं के चेहरे और कार्य करने के तरीके बदल दिए जाते हैं जिससे छत्तीसगढ़ की नुकसान की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री परिषद से आग्रह करूंगा कि योजनाएं दशकों के लिए बनें, वर्षों के लिए नहीं और वह यथार्थ की धरातल पर उतरने के लिए बने, उसका पहले दिन ही यह प्रयास होना चाहिए कि वह दशकों के लिए बने और उसको जनहितैषी योजना का लाभ मिल सके। शिक्षा के केंद्र मैंने सुना विश्वविद्यालय बना रहे हैं, लेकिन नोडल सेंटर फॉर एग्जामिनेशन बनकर रह गए हैं, सिर्फ डिग्री बांटने के संस्थान। उस पर भी चिंता करनी चाहिए। प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले पड़े हैं, परंतु डिग्री बेच रहे हैं। शिक्षा दे नहीं रहे हैं। इस पर भी इस विषय को इस नवा अंजोर में जोड़ना चाहिए । निर्माण के क्षेत्र में हमने भवनें बहुत बनाईं। यह विधान सभा भवन बना है। अभी-अभी हम यहां पहले सत्र के पहले दिन खड़े हैं। लेकिन मेंटेनेंस का प्रावधान हमारे बजट में आज दिनांक तक 25 वर्ष के बजट में भवनों का कभी भी मेंटेनेंस का प्रावधान उल्लेखित नहीं है। चाहे वह खेल के मैदान हों, चाहे कोई भी भवन या परिसर हों, उसके मेंटेनेंस के लिए कोई भी प्रावधान बजट में उल्लेखित नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री परिषद से आग्रह करूंगा कि अपने विभागों के भवनों और जन हितैषी योजनाओं के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान अपने बजट में जरूर करें। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर जैसे बहुत सारे हमारे केंद्र हैं। किसी प्रदेश का वास्तविक चेहरा उसका लॉ एंड ऑर्डर होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था पर जब प्रश्न उठता है तो मानवाधिकार की चर्चा तो हम आम लोगों के लिए जरूर करते हैं, लेकिन पुलिस सेवा में रहने वाले हमारे कर्मचारी मानवाधिकार से सबसे ज्यादा वंचित रहते हैं। न उनके पास आवास है, न उनके पास सुविधा है और छत्तीसगढ़ के मौसम चक्र को अगर आप देखें तो उनकी वर्दी ही उनके साथ न्याय नहीं करती है कि वूलन की टोपी और जूते की गर्मी से अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आप यह उम्मीद करें कि वह 8 घंटे से ज्यादा नौकरी फील्ड पर रहकर कर सके तो मानसिक स्थिति समझी जा सकती है कि किसी के पहनावे पर आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह आपकी अपनी सेवा का 100 प्रतिशत आपको दे। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए पुलिस को मनोबल देने के लिए आवास की व्यवस्था सुनिश्चित हो। पुलिस को मनोबल देने के लिए भत्ते की व्यवस्था सुनिश्चित हो। पुलिस को मनोबल देने के लिए उनके वर्दी में संशोधन होना चाहिए। अगर पुलिस मनोबल के साथ होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस की बूटों का जो दम है, वह

असामाजिक तत्वों के लिए पर्याप्त है और यदि पुलिस मनोबल पाएगी तो असामाजिक तत्व अपने घर में ही घुसे रहेगी, वह बाहर नहीं निकलेंगे। उद्योग क्षेत्रों में मैंने फायर स्टेशन की बात की, लेकिन अपनी बात की अंतिम कड़ी पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ में डी.एम.एफ. की योजना पर केन्द्र सरकार के सुझाव पर एक व्यापक संशोधन किए गए हैं या केन्द्र सरकार ने नियम बनाया है। वह नियम यह है कि खदान क्षेत्र से 15 किलोमीटर और 16 से 25 किलोमीटर की रेडियस पर है। यह डी.एम.एफ. की नई राशि का वितरण तय हुआ है, परंतु विकास कार्य की एक और राशि है जिस पर आज तक कोई नीति नहीं बनी है। वह नीति सी.एस.आर. की नीति है। सी.एस.आर. में देखने में यह आता है कि जो संस्थान औद्योगिक हैं, उनके अधिकारियों के परिवारजन सी.एस.आर. को अपने में गोल-गोल रानी, इतना-इतना पानी करके खेलते रहते हैं। उस पर प्रदेश में कोई प्राधिकरण बनें, ताकि सी.एस.आर. की राशि का, जिसको हम सामाजिक औद्योगिक उत्तरदायित्व के रूप में जानते हैं, उसका समुचित उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में किया जा सकें और भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। हमने पूर्व में संवाद से सुशासन कार्यक्रम करवाया था और यही परंपरा स्थापित रखने के लिए हम हिमायती भी है कि संवाद से सुशासन हो, परंतु जन संवाद और जनप्रतिनिधियों से प्रशासन का संवाद शायद तक टूट रहा है। इसके लिए भी एक नवाचार की व्यवस्था स्थापित हो कि कम से कम जनप्रतिनिधि और आमजनों के जो सुझाव है, उस पर प्रशासन समय पर जवाब दें। वह पत्राचार के माध्यम से सही जवाब दें, ताकि संरक्षण बना रहे। जब हम छत्तीसगढ़ के सुशासन रथ का अंत करते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ अंजोर के माध्यम से सुघ्घर डहर, उज्जर भविस का नारा तय करते हैं तो दुष्यंत जी की कुछ कवितायें याद आती है। दुष्यंत जी कहते हैं कि -

जो मरुस्थल आज अश्रु भिगो रहे हैं,
विकास रूपी भावना के बीज जिस पर हम बो रहे हैं,
सिर्फ़ मृग-छलना नहीं चमचमाती रेत है वह!
क्या हुआ जो युग हमारे आगमन पर मौन है?
सूर्य की पहली किरण को पहचानता ही कौन है?
अर्थ कल लेंगे हमारे आज के संकेत,
तुम न मानो शब्द है नहीं कोई नामुमकिन,
कल उगेंगे चाँद-तारे, कल उगेगा यही दिन,
कल फ़सल देंगे समय को, यही संभावनाओं का खेत,
जय छत्तीसगढ़ के साथ हम निभेंगे छत्तीसगढ़ की जनता के विशेष।

सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम, जो हमारे भांजा भी हैं। श्रीराम आ चुके हैं। अब राम राज्य की परिकल्पना इस नवा अंजोर के माध्यम से

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी स्थापित करेंगे। सभापति महोदय, इसी परिकल्पना एवं संकल्पना के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री, श्री अरूण साव जी।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय,

मंजिलें उन्हें मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है।

पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। आज से ठीक 25 साल पहले 14 दिसंबर, 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में टेंट से हमारे छत्तीसगढ़ के पहले विधान सभा का शुरूआत हुई ।

समय
4.25 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह 25 सालों के सफर के पश्चात इस भव्य और विशाल इमारत के रूप में यहां पर छत्तीसगढ़ विधान सभा पहुंचा है । यह छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा को दर्शाने वाला है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने इतिहास रचा है, रविवार के दिन विधान सभा का सत्र लगाकर जनसेवा का इससे बड़ा और कोई उपक्रम नहीं हो सकता है कि जब रविवार को पूरी विधान सभा संचालित हो रही है । यहां पर सभी लोग छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य की चिंता कर रहे हैं, इससे बड़ी जनहितैषी बात और कुछ नहीं हो सकती है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें आज यह दिन देखने का अवसर कैसे मिला है, मैं कहना चाहता हूँ और प्रश्न स्वयं अपने से करता हूँ कि कोई व्यक्ति सपना कब देख पाता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है, जब व्यक्ति सपना देख पाता है । जब वह बहुत इत्मीनान से सो रहा होता है, तब वह सपने देखता है और इत्मीनान से सोता कब है, जब उसका पेट भरा होता है, जब उसके बच्चे खाकर सो रहे हों, तब व्यक्ति सपने देखता है । आज यदि विजन 2047 पर जब इस विधान सभा में चर्चा हो रही है तो यह चर्चा करने का अवसर जिस महापुरूष ने हमें उपलब्ध कराया, वह भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनके कारण आज हम यह सपना देख पा रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ वर्ष 2047 में कैसा होगा ? मैं आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूँ कि जिन्होंने छत्तीसगढ़वासियों के दर्द को समझा है और हमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके दिया । यह 25 सालों का सफर इस तरीके से तय हुआ है, वह अद्भूत अकल्पनीय है । छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले यहॉ के हालात क्या थे, क्या परिस्थितियॉ थी, देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारों ने क्या दिया

था ? देश और प्रदेश की सरकारों ने छत्तीसगढ़ को दिया क्या था ? छत्तीसगढ़ पर भगवान की कितनी कृपा है, हर काल में कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है । छत्तीसगढ़ का इतिहास कितना वैभवशाली और गौरवशाली रहा है, माता कौशिल्या की यह धरती है, भगवान राम का ननिहाल है, बड़े-बडे संत, महात्मा, ऋषि मुनि छत्तीसगढ़ की धरती में पैदा हुये हैं । यहां प्रकृति की असीम कृपा है, बड़े-बड़े जंगल, बड़े-बड़े पहाड़, बड़ी-बड़ी नदियां, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार और सबसे बड़ी जो ताकत छत्तीसगढ़ की है, वह सीधे-साधे, भोले-भाले, ईमानदार और मेंहनतकश लोग हैं । 50 सालों के कांग्रेस शासनकाल में इस छत्तीसगढ़ के लिये कांग्रेस का योगदान क्या रहा है ? आज जैसे उनकी उपस्थिति शून्य है, ऐसा ही छत्तीसगढ़ के विकास में कांग्रेस की सरकारों का योगदान रहा है । कांग्रेस का योगदान शून्य रहा है, कभी विकास से स्वयं को जोड़ा नहीं है, आज छत्तीसगढ़ के विजन की चर्चा हो रही है और सदन में कांग्रेस पार्टी नहीं है, यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के विकास में उसी तरह से उनकी अनुपस्थिति रही है । कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिया क्या था, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, यही कांग्रेस ने दिया । उपेक्षित किया, विकास से दूर रखा, महरूम रखा, आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति सपने कब देखता है, जब सुकून से अच्छी नींद आए, सुकून से नींद तो तब आती है जब पेट भरा हो और सपना देखने लायक यदि आज छत्तीसगढ़ हुआ है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण हुआ है, अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के कारण हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) आज हम सपने देख रहे हैं, मैंने यह भी कहा कि पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होता है। देश में एक हौसले वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के काम में लगे हुए हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन है, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर काम करने का हौसला विष्णुदेव साय जी में है, इसलिए हम ये अंजोर 2047 को लेकर काम कर रहे हैं, ये अंतर है। आज जिस प्रकार से हमारी सरकार विजन 2047 को लेकर चल रही है यह विजन हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे इस संकल्प को लेकर आज हम काम कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया है तो उसे संवारने का काम भी हम करेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का जो रोडमैप है, यही हमारा विजन 2047 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विश्वास कोरा नहीं है, ये विजन 2047 कोरा नहीं है, इसके लिए हमने ठोस रणनीति और चरणबद्ध योजना बनाई है कि कैसे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। हमारी यह यात्रा GYAN पर आधारित है। G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता, N से नारी की सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। उसको केन्द्र बिन्दु बनाकर हमने विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की है, उसी का ये डॉक्यूमेंट है, चरणबद्ध योजना है, जो विजन 2047 के रूप में हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया है।

सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं

न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के बजाए अपनी विभागों से संबंधित थोड़ी बातें सदन के सामने रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- शायरी के बाद उन्होंने इरशाद नहीं किया। (हंसी) जब प्रमुख मुद्दा में आ रहे हैं न तो इरशाद करना चाहिए।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, धीरे से दाद दे रहे हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नई गाथा को लिखने में प्रदेश के शहरों की भूमिका और योगदान के विषय में आज आप सभी के समक्ष संक्षेप में कार्ययोजना और शहरी विजन प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ एक तीव्र गति से विकसित होता हुआ शहरी राज्य है जहां आज वर्तमान में 193 नगरीय निकाय है जिनमें 14 नगर निगम, 56 नगरपालिका और 123 नगर पंचायत शामिल है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है, राज्य की शहरी जनसंख्या लगभग 78 लाख 10 हजार है, जो 2047 तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक होने का अनुमान है। जनसंख्या तीव्र वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि बुनियादी सेवाओं आवास, आधारभूत संरचना, शहरी परिवहन, पर्यावरणीय प्रबंधन, डिजीटल शासन के क्षेत्रों में व्यापक और चरणबद्ध सुधारों की नितांत आवश्यकता है। विभाग का उद्देश्य वर्ष 2047 तक ऐसे शहरी तंत्र का निर्माण करना है जो आधुनिक, सुरक्षित, समावेशी, स्वच्छ, हरित जलवायु, सहिष्णु तथा तकनीकी रूप से सक्षम हो। पिछले 2 दशकों में शहरीकरण की दर 23 प्रतिशत से बढ़कर 27.1 प्रतिशत हो चुकी है तथा स्थानीय निकायों की संख्या 97 से बढ़कर 193 तक पहुंच गई है। यह प्रत्यक्ष संकेत है कि आने वाले वर्षों में राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रमुख संवाहक शहर ही होंगे। आप सबके समक्ष वर्ष 2047 तक सभी नगरीय निकायों के समग्र रूप से रूपांतरण एवं विकास की कार्य योजना को बिंदुवार संक्षेप में रखने का प्रयास करता हूं। जिसमें शहरी जनसंख्या का पूर्वानुमान, भूमि उपयोग योजना, सड़क नेटवर्क, जल आपूर्ति व्यवस्था, सीवरेज प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्क, तालाब संरक्षण, स्ट्रीट लाइटिंग, सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना, डिजिटल अधोसंरचना, पर्यावरणीय जोखिम का आकलन तथा निवेश आवश्यकताओं का विस्तृत एवं सुव्यवस्थित मूल्यांकन सम्मिलित हैं। इन सबको सम्मिलित करके शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में एक व्यापक चरणबद्ध योजना हमने बनाई है। आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी अलग-अलग योजनाओं से हमने शहर को सिटी डेव्हलपमेंट प्लान के माध्यम से, नगरोत्थान योजना के माध्यम से, नालंदा परिसर के निर्माण के माध्यम से, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से अपने शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में हमने

चरणबद्ध काम करना प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे शहर विश्व स्तरीय शहर बने। आज मुझे इस सदन में कहते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे राज्य के 7 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने का गौरव मिला है। (मेजों की थपथपाहट) यह हमारे सुव्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध तरीके से शहरों को विकास की दिशा में ले जाने का परिणाम है, जो आने वाले समय में और तेज गति से आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद हमने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं। विरासत में हमें जो कुछ मिला था, वह आप सबके माध्यम से जनता को भी ध्यान में है कि दिसम्बर, 2023 से नवम्बर, 2025 तक कुल 1053 कार्यों, 864 सड़क, 4464 किलोमीटर लंबाई, 171 पुलों, 18 भवनों के निर्माण के लिए 7151 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। वर्तमान में 3641 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति और पूर्णता पर है। दिसम्बर, 2023 से नवम्बर, 2025 तक 164 पुल निर्माण कार्य किये गये तथा 143 पुल निर्माण कार्य प्रगति तथा पूर्णता पर है। इस अवधि में कुल 252 भवन निर्माण कार्य पूर्ण किये गये, 262 भवन निर्माण कार्य प्रगति और पूर्णता पर है। इस अवधि में लोक निर्माण विभाग में भृत्य से लेकर मुख्य अभियंता के पदों पर कुल 371 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी गई है। विगत 2 वर्षों में लोक निर्माण विभाग के कार्यों के बेहतर संचालन एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से 7 नवीन संभागीय कार्यालय, 12 नवीन उप संभागीय कार्यालय सृजित किये गये। इस अवधि में लोक निर्माण विभाग में 19 लाभार्थी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई, 113 उप अभियंताओं की भर्ती के लिए व्यापम के द्वारा विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें 80 उप अभियंताओं की नवीन नियुक्तियां कर दी गई हैं तथा 7 मानचित्रकारों की भर्ती की गयी है। लोक निर्माण विभाग अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आज काम कर रहा है। आने वाले समय में हमने 19 ऐसे मार्गों का चिन्हांकन किया है, जिसे हाई स्पीड रोड के रूप में बनायेंगे। आने वाले समय में कोई भी गांव पहुंचविहीन न रहे, वहां सड़कें पहुंचे, इसकी योजना बनाकर हमने काम किया है। लगातार सुशासन, पारदर्शी व्यवस्था के कारण आज सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। आने वाले समय में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रोड सेफ्टी पर हम विशेष फोकस करके काम कर रहे हैं। इसी तरह से जल जीवन मिशन का जो काम है, वह पूरी तरह से अव्यवस्थित था। आज जल जीवन मिशन के कामों को गति प्रदान करके हम 5 हजार से अधिक गांवों में घर-घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिये लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 70 मल्टी विलेज स्कीम बनाई है जो Surface water को लेकर है, उसके काम को भी हम तेज गति से पूरा कर रहे हैं ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके। खेल, खिलाड़ियों के लिये योजना बनाकर हम लगातार काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल बस्तर ओलंपिक का समापन हुआ है, उसमें 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया और ऐतिहासिक रूप से बस्तर ओलंपिक लगातार

दूसरी बार संपन्न हुआ है (मेजों की थपथपाहट)। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। किस प्रकार से जो निर्वासित, पुनर्वासित नक्सली है, जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, उन्होंने भी खेल का जज्बा दिखाया, उनके चेहरों में जो प्रसन्नता थी, उनके चेहरों में जो खुशी थी, जो युवाओं का उत्साह दिख रहा था, वह दिखाता है कि खेल के माध्यम से बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ने के लिये तैयार है। खेल अधोसंरचना के क्षेत्र में हम प्रत्येक जिले में आधुनिक मेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स विकसित करेंगे। वैज्ञानिक प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को डेटा आधारित प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी और पोषण सहायता देने के लिये स्पोर्ट्स साईंस सेंटर स्थापित करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये एग्रीटेक रोबोटिक, फिनटेक और ए.आई. जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप का विस्तार किया जायेगा। आने वाले समय में हम सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन करने वाले हैं और यही नहीं हमारे इन प्रयत्नों के आधार पर भारत सरकार ने नेशनल ट्राईबल गेम की मेजबानी करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया है। यह बताता है कि आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में हम अपने छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताओं को, माननीय अध्यक्ष महोदय आप बखूबी वाकिफ है कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि उनको अच्छा प्रशिक्षण देने की, उनको अवसर उपलब्ध कराने की और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिये प्रतिबद्ध है और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि

“रूकना नहीं है हमें
झुकना नहीं है हमें
रास्ते मुश्किल है सही
पर थमना नहीं है हमें
भारत माता के भाल पर चंदन सा हम सजेंगे
विकसित भारत की गाथा में स्वर्णिम अध्याय हम
छत्तीसगढ़ के माध्यम से रचेंगे।” (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अपनी बात की शुरूआत की कि

“उड़ान पंखों से नहीं होती है
उड़ान हौसलों से होती है”

आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2047 तक छत्तीसगढ़ को समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के लिये यह विजन डाक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। मैं उस संकल्प को फिर दोहराना चाहूंगा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस दिशा में हमारा जो कदम है, वह हमारा विजन 2047 बताता है। यही कहते हुए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सार्थक चर्चा ऐतिहासिक रूप से, आज जब हमारे विधान सभा का 25 साल पूरा हुआ है,

25 सालों के सफर का ये बड़ा उदाहरण हमारी ये छत्तीसगढ़ की विधान सभा का भवन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामविचार नेताम जी, जो कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। इधर-उधर की बात नहीं कहूंगा। मैं कान लगाकर आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री रामविचार नेताम :- आप कान लगाकर सुनिये, कुछ और लगा लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ऐतिहासिक मौके पर जब हमारे विधान सभा के नये भवन में प्रथम दिवस हम प्रवेश किये तो उसमें छत्तीसगढ के संदर्भ में 2047 तक का हमारा विजन क्या होगा, इस पर चर्चा करने का आपने सुअवसर दिया है। यह हमारा 2000 से लेकर के 2025 तक का जो लंबा सफर रहा, उस सफर में हम लोगों ने अधिकांश समय पुराने विधान सभा में दिया और आपके ही नेतृत्व में हम सबने छत्तीसगढ़ की बेहतरी की इमारत का एक फाउंडेशन भी डाला और जो एक बेहतरीन फाउंडेशन डाला गया, उस फाउंडेशन के आधार पर आज इतना फलता-फूलता, इतना विकसित छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश के सामने सीना तानकर के खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, ये सब देख करके मैं समझता हूं कि आपको भी सुकून होता होगा, आपको प्रसन्नता होती होगी। एक-एक ईंट को जोड़ने का, एक-एक चीज को संवारने का काम किया। मुझे मालूम है कि जब नये केपिटल के संदर्भ में चर्चा हो रही थी तो उस बारे में न जाने कितनी बार बैठकें हुईं और उन बैठकों में हम सबको, मुझे भी उपस्थित रहने का अवसर मिला। इतनी बारीकी से, इतने अध्ययन के साथ वहां चर्चा होती रही। मैं समझता हूं कि इसी का नतीजा रहा कि आज देश का एकमात्र हमारा ऐसा केपिटल सिटी बना है जो एक तरह से ग्रीन जोन है, जिसके पास सबसे अधिक लैंड है। इतने सुव्यवस्थित तरीके से सिटी को बसाने की योजना बनाई, अध्यक्ष महोदय, उसमें अगर सबसे अधिक श्रेय जाता है तो आपको जाता है। उस रूप में छत्तीसगढ़ को ऊंचाईयों तक ले जाने के लिये जो अभी हम लोगों ने 25 साल का सफर तय किया है, आगे आने वाले 2047 तक के लिये हमारा विजन क्या होगा, इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट रखा। यहां तक पहुंचने के लिये हमारे प्रदेश के जितने भी सारे विभाग हैं, उन सारे विभागों की क्या-क्या कार्ययोजना है, हमारी क्या-क्या कल्याणकारी योजना हो सकती है, यहां कौन-कौन से ऐसे विषयों को हम समाहित कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के हित को भी साध सके, उनके बेहतर भविष्य का भी निर्माण कर सके और ऐसा सोचकर के हम लोगों ने एक विजन रखा है । मैं इस विजन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिये हमारे प्रदेश के बहुत ही मेधावी और बहुत ही कुशल नेतृत्व के धनी और जिन्होंने अपने करियर को दांव पर लगाकर हमारे इस राजनीति के क्षेत्र को चुना है, मैं ओ.पी.चौधरी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी की बातों को समाहित करने का पूरा प्रयास किया है । कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं

होता, हो सकता है कि माननीय वित्तमंत्री जी की, इनकी टीम ने कहीं किसी विषय को छोड़ा होगा लेकिन हम तो बैठे हैं । हम सरकार चला रहे हैं, तमाम् सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है । उनके सहयोग से अगर किसी बात की कोई कमी होगी तो हम पूरा करेंगे, हम शामिल कर लेंगे, यही थोड़ी पूर्ण हो जाता है । हम उसके लिये तो बैठे हैं, उसे ठीक करने के लिये बैठे हैं । कहीं भी अगर हमें कुछ दिखायी दे कि यह हमारे प्रदेश के हित में यह ठीक जाने वाला नहीं है, यह ठीक संदेश नहीं जायेगा तो हमारे पास अवसर है, हमारे पास बाकी संसाधन हैं, हम उसे ठीक कर लेंगे और इसलिये इस दिशा में हम आगे बढ़ें । हम अगर यात्रा की बात करें, अगर देखें तो प्रभु राम जी को भी प्रभु बनने के लिये जंगल-जंगल तक भटकना पड़ा था । एक रोड मेप बनाकर के चलना पड़ा, वहां तक जाकर लंका विजय फतह करना पड़ा, लंका विजय फतह करने के पहले उनको न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा, उनको एक रोड मैप तो बनाना पड़ा । हमें भी लाल किला तक प्राचीर तक पहुंचने के लिये सन् 1951 से लेकर के अभी तक न जानें हमारे कितने थिंकर, कितने विचारकों का, कितने हमारे ऐसे मनीषियों का, उनका विचार और उस विचार को बढ़ाते-बढ़ाते, एक जमाना ऐसा भी था कि अब की बारी अटल बिहारी बोलते थे और विपक्ष जो इधर बैठ रहे हैं वह बोलते थे कि दिये में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं और इसके बाद बोलने लगे कि दिये में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं । हम लोगों ने दिये को भी भरा, सरकार भी चलाते देखा और चलाते-चलाते हम लोग यहां भी पहुंचे । हमें जब लाल किला तक पहुंचना पड़ा तो वर्ष 2012-13 से हम लोगों ने यात्राएं शुरू कीं । प्रभु राम मंदिर बनाना हुआ तो 500 साल तक क्योंकि रोड मैप बन चुका था, 500 साल पहले तक रोड मैप बना हुआ था कि हमें यहां राम मंदिर बनाना है, हमें प्रतिष्ठा स्थापित करनी है । वह 500 साल तक की लड़ाई और हमने तो इतनी कम लड़ाई का लक्ष्य रखा है तो हमें यहां तक पहुंचने के लिये और अगर हम बात करें, यहां लाल किला तक तो वर्ष 2013 में आपके नेतृत्व की सरकार ने विकास यात्रा के समापन के अवसर पर अंबिकापुर के उस ऐतिहासिक मैदान में आपकी उपस्थिति में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में विकास यात्रा के समापन का जो आगाज हुआ और वहां पर लाल किला एक प्राचीर रूप में, एक काल्पनिक लाल किला बनाया गया और दिखाया गया कि हमारा लक्ष्य यह है । (मेजों की थपथपाहट) हम यहां से चलते हुए, हम वहां लाल किला तक झण्डा फहरायेंगे, यह लक्ष्य था तो लक्ष्य तो हमें हासिल करना ही पड़ेगा और लक्ष्य रखना ही पड़ता है और उस लक्ष्य के लिये हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया, हमारी लगातार यात्राएं चलती रहीं, हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहे और अंततः जुलाई, 15 अगस्त, 1900 और 2014 में हमारा लाल किला में झण्डा फहर गया तो यह हम उस रोड मैप के आधार पर चले तो हम जब इस आधार पर चल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का हमारा जो रोड मैप बना है, हमें उस दिशा में पहुंचना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो रोड मैप बना है वह बलरामपुर, रामानुजगंज की ओर जाता है या नहीं जाता है?

श्री रामविचार नेताम :- मैं वह भी बता रहा हूँ। उस समय जब देश आजादी के 100 सालों को मनायेगा तो हमारे देश की जो स्थिति है हम जब विकसित भारत की श्रेणी में रहेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान क्या रहेगा ? उस दिशा में सोचकर, हमारी सरकार ने एक रोड मैप रखा है, विजन रखा है उसके आधार पर तमाम् विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के आधार पर हमें जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पायेंगे। हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह माध्यम जरूरी है और इसलिए आप और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे संगठन में मुझे ऐसा दायित्व मिला है जो छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोगों का हम कह सकते हैं, जो 70 से 80 प्रतिशत कृषि पर निर्भर होते हैं। मुझे ऐसे लोगों के बीच में काम करने का यह अवसर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। इस विभाग के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की बेहतरी कैसे कर सकते हैं ? इसलिए हमारे विभाग के माध्यम से हमारे विभाग ने बहुत सारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। जब हम बजट की बात करेंगे तो एक जमाना ऐसा भी था कि हमारा बजट कृषि के सेक्टर में एक नगण्य हुआ करता था, नहीं के बराबर होता था। कृषि के क्षेत्र में समृद्ध बजट की बात करें तो वर्ष 2013-2014 तक हमारा 8542 करोड़ रूपये का बजट होता था, जो आज की स्थिति में बढ़कर 26 हजार 84 करोड़ का बजट हुआ है। इतना बड़ा लक्ष्य है। यह करीब 205 प्रतिशत की वृद्धि है। हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम उद्यानिकी के क्षेत्र की बात करें तो जहां 2 लाख 1 हजार उद्यान विभाग में 2 हजार के लगभग हेक्टेयर का रकबा था, वर्तमान में आज 8 लाख 40 हजार हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है। एक जमाना था कि हमारे यहां छत्तीसगढ़ में सब्जियां दूसरे प्रदेश स आयात होती थी, लेकिन आज यह स्थिति है कि हम यहां से फल भी निर्यात कर रहे हैं, सब्जियां भी निर्यात कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी मीट की बात कर रहे थे कि आपके यहां के मत्स्य पालन की क्या स्थिति है ? हमारी अण्डे उत्पादन में क्या स्थिति है ? हमारी कुक्कुट पालन में क्या स्थिति है ? मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूँ और आपको भी यह गर्व होना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ की वह शक्ति है, वह क्षमता है आज हम निर्यात कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भईया, मैं अण्डे उत्पादन, मुर्गी पालन और मछली पालन पर गर्व करूं या नहीं करूं। मैं आपके ऊपर गर्व जरूर करता हूँ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं फल, सब्जी, मसालों, पुष्प, पॉम आईल, सिंचाई इन सब में भी हमारा काफी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, हमारी वृद्धि हुई है। जब छत्तीसगढ़ में हमारा पूरा जो जी.डी.पी. है उसमें 20-25 के लगभग हमारा अकेले कृषि सेक्टर का एक भार होता है। उसमें हमारी भागीदारी हो रही है। यह जरूरी है कि हम इस सेक्टर को कैसे मजबूत करें,

ऐसा सोचकर हम लोगों ने इसमें बेहतर तरीके से और अलग-अलग क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है। जितने भी देश के 100 आकांक्षी जिले हैं उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन क्षेत्रों के लिए भी अभी पी.एम. धनधान्य कृषि योजना लागू की है। मुझे गर्व है कि हमारे छत्तीसगढ़ तीन जिलों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, जिसमें दंतेवाड़ा, जशपुर और कोरबा है।

समय :-

5:00 बजे

अध्यक्ष महोदय, इनमें बेहतर तरीके से धन-धान्य योजना के तहत हम उत्पादन को कैसे बढ़ा सकें । वहां कोदो है, कुटकी है, जो श्री अन्न है, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकें । आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की कोदो, कुटकी, ज्वार-बाजरा या इस तरह की जो खेती होती थी, उसका महत्व पूरे विश्व मंच पर उन्होंने उद्धृत किया और विश्व मंच पर उन्होंने बताया कि यह श्री अन्न है और इसका महत्व किस प्रकार से बढ़ा है ? आज हर क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ा है । हम कह सकते हैं कि आज हम सबका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में खेती के साथ-साथ पशु-पालन, मत्स्य पालन और बकरी पालन में भी एक विशेष प्रयास करते हुए हम उसमें काम कर रहे हैं । जिस प्रकार से धान खरीदी में हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है । वैसे भी छत्तीसगढ़ को लोग धान के कटोरे के नाम से जानते हैं। निश्चित ही हमारे लिए धान तो एक-एक घर तक पहुंच गया है और एक-एक घर की मुख्य खेती हो गई है। इसलिए हमारे सामने जब अवसर है तो हमारे सामने एक चुनौती भी है । उस चुनौती के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हम सिर्फ धान पर आश्रित न रहें, धान के बदले में कौन-कौन सी उपज हम ले सकते हैं, इस दिशा में हमारा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सब इसमें काम कर रहे हैं कि धान के बदले में फल-फूल और भी सब्जियों की ओर लोगों का रूझान कैसे बढ़े, फल की खेती की ओर कैसे रूझान बढ़े, तिलहन की समस्या को हम कैसे दूर कर सकें और तिलहन के उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकें, आज पूरे देश में दलहन की इतनी मांग है, देश की जितनी आवश्यकता है, हम उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । प्रदेश में जितना आवश्यकता है, हम उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । हम इसको कैसे मजबूती दिला सकें, ऐसा सोचकर भी हम सब काम करें ।

अध्यक्ष महोदय, हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में आज एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस प्रकार से खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से उपज तो जरूर बढ़ता है, लेकिन खेत की जो उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है और यही कारण है कि समय पर विभाग जागा और देश के हमारे यशस्वी कृषि मंत्री जी ने एक अभियान चलाया और यह भी अभियान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को साकार करने के लिए चलाया । विकसित संकल्प अभियान पिछले वर्ष में मार्च-अप्रैल में हमने चलाया और उसका परिणाम यह रहा कि कृषि के

क्षेत्र में जितने भी एलाईड सेक्टर हैं, उनका हम कैसे विकास कर सकें, बेहतर तरीके से हम खेती को कैसे विकसित कर सकें । रासायनिक खाद पर हमारी निर्भरता कैसे कम हो, हम जैविक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर हम कैसे लोगों को बढ़ावा दे सकें, ऐसा सोचकर उनके गुण-दोष के बारे में भी आये हुए तमाम कृषि वैज्ञानिकों ने और विभाग के अधिकारियों ने जब किसान मेले में, किसानों के बाजार हाट में, किसानों के बीच में इस बात को रखा तो उसमें जरूर क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है और इसीलिए इस बार भी बहुत सारे किसानों ने धान के बदले कोई दूसरा फसल लेने का भी संकल्प लिया है । मैं तो उम्मीद करता हूं कि हम चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इस बार हम संकल्प लें कि आने वाला जो मई-जून का महीना है, इस मई-जून के महीने में गर्मियों में जो धान लेते हैं, उस धान के बदले में हम दूसरी फसल को बढ़ावा दें। धान की फसल लेने से हमारे जमीन के अंदर जो जल है, वह जल स्तर हर साल नीचे जा रहा है । उससे हमारे जानवरों को, पालतु पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है । कई-कई गांवों में तो पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है । इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है । इसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं। हम आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में यह संकल्पित होना पड़ेगा, अगर हम छत्तीसगढ़ की बेहतरी चाहते हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ के जल जीवन को ठीक करना चाहते हैं, यहां की उर्वरा शक्ति, यहां के जलस्तर को मेन्टेन करना चाहते हैं तो हमें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। तालाबों से बेतरतीब तरीके से पानी का दोहन हो रहा है, नदियों से पानी का जिस बेतरतीब दोहन कर रहे हैं, नदियों और तालाब को जे.सी.बी. से खोद-खोद कर पानी खींच ले रहे हैं, वहां पूरा जल स्तर समाप्त हो रहा है। उसके चलते हमारे जितने भी गौ-माता हैं, पालतू पशु हैं, जंगली जानवर हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है। हम इस दिशा में आगे बढ़े, हम इसके लिए बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग इस विधान सभा में आये हैं। यह प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश के आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सपना देने जा रहे हैं, हम उनको क्या रास्ता दिखाने जा रहे हैं, हम ऐसा सोच लेकर आगे बढ़ें। आज हम लोग इस दिशा में काम करने के लिए यहां पर आये हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार चुनकर आते रहेंगे। लेकिन एक बार भी किसी को अवसर मिला है, जो अवसर मिला है, उसको प्रदेश की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते हुए उस बूढ़ी मां के, उस गरीब तबके का, उस दबे-कुचले लोगों को देखते हुए, उसके टूटे-फूटे घर को देखते हुए उसके सपने को सजा सकते हैं। हमें देखना है कि उसके घर को कैसे बनाना है। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, हम उनका अभिनन्दन करते हैं कि आज ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सपनों को साकार किया है। लोगों का सपना होता है कि हम उन लोगों का घर बनायें। हमारे सपने को छिनने का जो काम पिछली सरकार ने किया, उसकी सजा यहां की जनता दे चुकी है। अब हमें उसके सपने को संवारने का समय है, उसे सजाने का समय है और हम उसे लेकर

आगे बढ़े। अगर हमारी सरकार ने 18 लाख मकान देने का काम किया है तो उसका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और हम यह काम कर रहे हैं। अगर हम 26 लाख किसानों को एम.एस.पी. के अलावा अतिरिक्त लाभ दे रहे हैं, हम उनको उत्पादन बढ़ाने के लिए राशि दे रहे हैं, उनकी क्षमता के विकास के लिए दे रहे हैं, उनके जीवन की बेहतरी के लिए दे रहे हैं तो निश्चित ही एक बड़ी सोच के आधार पर दे रहे हैं। इसलिए इस दिशा में काम करना शुरू किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज हम लोगों ने कृषि उन्नति योजना के तहत फसल विविधिकरण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। हमने कहा है कि हमारे सामने धान की चुनौती है। धान के बदले दलहन-तिलहन लगाने वाले कृषकों को भी 11 हजार रूपया प्रति एकड़ अनुदान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका प्रचार-प्रसार जितना होना चाहिए, उससे कम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज आपकी उपस्थिति में, आपके निर्देश में इसका निश्चित ही हमारे प्रदेश के किसान भाई लोग इसका लाभ उठायेंगे। निश्चित ही इसका बेहतर लाभ कमायें, लेकिन हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखते हुए इस योजना पर काम कर रहे हैं। पाम इडीबल आयल, सीड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषक समग्र विकास योजना, राज्य सरकार के फसल प्रदर्शन के माध्यम से तिलहन क्षेत्र का भी विकास कर रहे हैं। दलहन क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मक्का एवं लघु धान्य विस्तार के लिए आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आत्म योजना, राज्य सरकार के फसल प्रदर्शन इस तरह से इन सबके माध्यम से मक्का का भी काफी विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। आज हमें प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कोण्डगांव में मक्का प्रसंस्करण बना है। उसमें कुछ कमियां हैं। मैं स्वयं वहां उपस्थित होकर उन कमियों को देखा था। यह भी देखा था कि और क्या किया जा सकता ह। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी हमारे यहां पर बहुत सारी आज उसकी संभावना है और 2047 तक इसी बात के लिए हम ला रहे हैं कि आगे चलकर हम चाहे फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो, चाहे एग्रो के क्षेत्र में और भी यूनिट लाने की बात हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज आप सबने यह बात रखी है कि नेचुरल फार्मिंग एक चुनौती है। नेचुरल फार्मिंग की बात जब हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि अभी शुरुआत है, लेकिन हमने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें भले ही समय लगेगा, लेकिन वह लक्ष्य हम हासिल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में बढ़ते हुए हम सब काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। आज छत्तीसगढ़ में हम सबके लिए यह सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जब काम कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसको पूरा करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही हमारी डबल इंजन की सरकार है और देश में जिस प्रकार से विजन लेकर के भारत की सरकार चल रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व की निगाहें हमारे देश की ओर है।

हम यह चाहते हैं कि देश की निगाह हमारे छत्तीसगढ़ की ओर हो। छत्तीसगढ़ की ओर आज निगाह है, क्योंकि यहां की जो 32 प्रतिशत पापुलेशन है, वह ट्राइबल है और इन ट्राइबलों के लिए भी हमारी सरकार ने बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास नाम की संस्था खोली थी। किसने सोचा था कि इस प्रयास में पढ़ने वाले बच्चे आज आई.ए.एस. और आई.पी.एस. होंगे। किसने सोचा था कि यह प्रयास विद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे छात्र दिल्ली में जाकर के कोचिंग करेंगे। दिल्ली में कोचिंग की व्यवस्था किए थे। दिल्ली में हॉस्टल बनाने के निर्णय आपका निर्णय था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उस समय मुझे भी काम करने का अवसर मिला था। यह निर्णय आपका था, उस निर्णय को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक का लक्ष्य हम और आगे हासिल करेंगे और इसीलिए आपके नेतृत्व में 2025 तक हम लोगों ने 185 कहां 50 और कहां 185 हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 185 सीट की वहां स्वीकृति करके वहां आई.ए.एस, आई.पी.एस. की कोचिंग करने के लिए योजना चलाएं। आगे चलकर जिस प्रकार से धरती आबा के माध्यम से हम प्रदेश में जिस प्रकार से ट्राइबल क्षेत्रों का विकास हम कर रहे हैं, वह सब आप देख सकते हैं। किस प्रकार से आज 32,000 गरीब परिवार को जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, उन 32,000 लोगों को मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि यह तो पी.वी.टी.जी. के लोग हैं। आगे चलकर जिस प्रकार से हमारे जो 6,691 विलेज हैं, वह जो धरती आबा प्रोजेक्ट है, उस योजना में शामिल है। वहां की बेहतरी के लिए एक वृहत कार्य योजना बनना है। इस विषय को लेकर के आदरणीय अजय चंद्राकर जी का भी कल क्वेश्चन है, मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आप एक मात्र आदमी बचे हैं, जिसके साथ टोका- टाकी हो। समझ रहे हैं? पर आप 2047 में बोलिए, डिमांड मांग की तरह मत बोलिए। आप इस सदन में सबसे सीनियर हैं। आप डिमांड मांग की तरह बोल रहे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- आप ध्यान दीजिए, उस चीज को मैंने बताया। अध्यक्ष महोदय, हमने लक्ष्य रखा है, उस चीज को हम पूरा करेंगे। अभी हमारी सरकार तीसरी बार धान खरीदी करने जा रही है। निश्चित ही आज धान खरीदी करने का जो हमारा सिस्टम बना है, उसमें हम यह कह सकते हैं, सुकून के साथ कह सकते हैं, प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं कि पूरा इतना सुव्यवस्थित तरीके से हमारी व्यवस्था चल रही है। कहीं-कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। इतने बड़े पैमाने पर जब हम काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर किसानों का जब हम धान खरीदी कर रहे हैं तो निश्चित ही कहीं-कहीं कुछ दिक्कतें आएंगी, शिकायतें आएंगी, कुछ पॉलिटिकल भी होगा, कुछ व्यावहारिक भी हो सकता है। जो व्यावहारिक होगा, उसको हम दूर करने के लिए बैठे हैं, उसका हम निराकरण करेंगे। कहीं कूपन की समस्या आ रही है, कहीं लोगों के रजिस्ट्रेशन की समस्या आ रही है, उसको भी दूर करते हुए हमारी सरकार बेहतर काम करने वाली है। अध्यक्ष महोदय, आप वैसे भी चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं । आपने गरीबों

का पेट भरने का काम की शुरूआत की थी। आपके समय में उस योजना की शुरूआत हुई थी। आपके समय में धान खरीदी में पी.डी.एस. का जो व्यवस्थित मॉडल स्थापित हुआ था, इसके बाद किसानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही कारण है कि जब से हमने 3100 रूपये में धान खरीदी की शुरूआत की है, तब से हमारे खेती के रकबे में काफी विस्तार हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि खेती के साथ-साथ हमारे सामने पशुधन का विकास, मत्स्य पालन का विकास व अन्य क्षेत्रों का विकास भी हैं, जिसके बगैर हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकती है। अगर हम गांवों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अगर हम ट्रायबलों के बीच उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो इसके बिना हो ही नहीं सकता। हमें इसके लिए बिल्कुल कंपोजिट प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा। जहां तक वर्ष 2003-2004 की बात करें तो पशुधन विकास के लिए मात्र 65 करोड़ रूपये का प्रावधान होता था, जो आज 65 करोड़ से बढ़कर 748 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान है। आगे चलकर हम वर्ष 2047 तक जो करना चाहते हैं, इसमें इन सबको पूरा करना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- 748 करोड़ में अभी दिसंबर तक कितना खर्च हुआ है?

श्री रामविचार नेताम :- वह मैं बजट सत्र में बताऊंगा। आप चिंता मत करिये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अगर मैं दूध उत्पादन के क्षेत्र में बात करूं तो दूध उत्पादन में प्रति दूध प्रदायक संख्या लगभग 11,100 है। जो अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ जनवरी, 2025 में समझौता ज्ञापन होने के बाद में स्थिति है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि शुरूआत में हमारे सामने समस्या थी, जो दूध प्रदायक की संख्या 11,000 हुआ करता था, आज उसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 13,500 है। जहां दूध संकलन 55,000 लीटर हुआ करता था, वह आज 65,000 लीटर प्रतिदिन हो रहा है और जहां तरल दूध बिक्री का 48,000 लीटर प्रतिदिन होता था, वह आज 50,000 लीटर प्रतिदिन हो रहा है। आगे चलकर इसमें जो वृहद कार्ययोजना बनी है, उसके आधार पर निश्चित ही छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी विस्तार करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आज आपने अन्य ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा संक्षिप्त करेंगे।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, आज अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो खासकर जो ट्रायबल जन-जीवन है, उसमें मत्स्य पालन का, बकरी पालन का, मुर्गी पालन का, कुक्कुट पालन का, बतख पालन का एक विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से उनका आर्थिक उन्नयन हो सकता है। ऐसा सोचकर एक वृहद योजना बनाकर विभाग काम कर रहा है। आगे चलकर मत्स्य सेक्टर में भी बहुत विस्तार होगा। वर्तमान में जल क्षेत्र 2 लाख वर्ग हेक्टेयर है, उसे वर्ष 2047 तक 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि कर 2.24 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार से जो वैकल्पिक जल क्षेत्र राज्य में जहां-जहां माइनिंग होते हैं, वहां बहुत सारे माइनिंग एरिया में जल क्षेत्र का भराव होता है। उन जल क्षेत्रों में कोई उपयोग नहीं होता था। वहां भी मत्स्य पालन विभाग इसको लेकर मत्स्य

पालन करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से हम यहां उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जहां तक मत्स्य पालन की बात है कि राज्य 583 करोड़ मत्स्य बीज प्रति वर्ष उत्पादन कर देश में छठवें स्थान पर है, जिसमें आपका धमतरी का विशेष योगदान है। (सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर की ओर देखते हुए) इसे वर्ष 2047 तक दूसरा या तीसरा पर लाने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसमें विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार से हम कुक्कुट पालन के क्षेत्र में भी निर्यात के बारे में बहुत प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र को विदेशी निर्यात से जोड़कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु कार्य किया जा रहा है । वर्तमान में तीन कंपनियां इनके माध्यम से 380 टन तिलोपिया मत्स्य यूएसए एवं अर्जेंटिना को निर्यात किया जा रहा है । (मेजों की थपथपाहट) ऐसा होना चाहिये । हम इसे वर्ष 2047 तक 4000 मीट्रिक टन करने वाले हैं, आप भी वहां एकाध तालाब रख लीजिए, बढ़िया वहां करिये । अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार से योजना बनाकर काम कर रहे हैं । बीज उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर हो गये हैं । यहां हमारे पास जितना बीज का उत्पादन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि बीज भंडारण की बात करें तो आज हमारे पास 6 लाख 40 हजार 788 क्विंटल की उपलब्धता है । हम इस तरह से सक्षम हुये हैं । जब छत्तीसगढ़ बना तो उस समय की स्थिति क्या थी, आपके नेतृत्व में चलते-चलते इस क्षेत्र में भी आज कितना काम हुआ है । छत्तीसगढ़ कृषि के सेक्टर में देश में आगे बढ़ा है । आपने तमाम विषयों पर चर्चा करने का अवसर जो हम सब को दिया है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में जो करना चाह रहे हैं, उसे अधिक फोकस करने की जरूरत है । हम निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा के पठार क्षेत्रों में जो जलवायु है, उस जलवायु के आधार पर हमारी कृषि नीति क्या होनी चाहिये, उन क्षेत्रों में हमारे कौन-कौन से फसलों का उत्पादन अधिक हो सकता है, यह योजना हमारी सरकार ने आरंभ की है । मैं समझता हूँ कि 2047 तक का जो लक्ष्य हमारे सामने है, वह हमारे लाखों-लाख किसान, माताओं एवं बहनों के सहयोग से तथा आप सब के आर्शीवाद से हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे । वर्ष 2047 जब विकसित भारत बनेगा तो निश्चित रूप से कृषि विभाग और ट्राईवल विभाग के सहयोग से हमारा यह प्रदेश विकसित छत्तीसगढ़ प्रदेश बनेगा । आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये आभार ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री विजय शर्मा जी ।

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, देश के भीतर विजन 2047 बनाकर काम किया जा रहा है और विभिन्न प्रांतो ने भी इस काम को किया है । ऐसी ही चर्चा विभिन्न प्रांतों के सदनों में हुई है और होना भी चाहिये । मुझे घोर आश्चर्य भी है और इस विषय पर आपत्ति भी है कि विपक्ष ऐसी चर्चा से नदारद कैसे रह सकता है, इस चर्चा में है क्या ? इस चर्चा में यह है कि छत्तीसगढ़ की उन्नति कैसी हो, इस बात पर चर्चा है ? छत्तीसगढ़ की उन्नति वह नहीं चाहते हैं, शायद ऐसा है । यह बड़ी विचित्र स्थिति है, यह सोचना बड़ा अजीब है कि विपक्ष नदारद कैसे हो सकता

है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह न रहे? माननीय केदार जी सही कह रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे । हमारा लक्ष्य है, हम उसे जरूर पूरा करेंगे । छत्तीसगढ़ के विकास के लिये राह का निर्धारण होना है और आप अच्छा बोलें, बुरा बोलें, सही बोलें, गलत बोलें, जो बोलना हैं, बोलें। आप नहीं बोलेंगे, भाग जायेंगे । यह विषय तो स्वीकार नहीं हो सकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तो पक्ष और विपक्ष का नाता है, छत्तीसगढ़ की जनता आज के बाद इस बात को बिल्कुल समझ लेगी कि यह जो कांग्रेस है, यह विपक्ष में बैठने वाले जो लोग हैं, वह भले ही इस सदन के सदस्य हैं, परन्तु छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा से इनका दूर-दूर तक कोई लेन-देन नहीं । जैसा पहले से चाहते हैं। जब भी भारत की शौर्यगाथा हो, जब भी भारत के पराक्रम की बात हो, जब भी भारत के विज्ञान में उन्नति की बात हो, जब ये कहा जाए कि भारत परम कम्प्यूटर बना लेगा, सुपर कम्प्यूटर बना लेगा तो उसको हास्यास्पद बनाना, भारत की परंपराओं को हास्यास्पद बनाना, भारत की प्रक्रियाओं को हास्यास्पद बनाना, जब हर समय ऐसा होता रहा तब-तब कांग्रेस ऐसा ही करती रही, आज जब हम सब मिल करके एक बड़े लक्ष्य की ओर पूरा देश बढ़ रहा है, उसी के समनांतर सारे प्रदेश बढ़ रहे हैं तब ये चर्चा से गायब हैं, ये सदन से गायब हैं, यह इनकी बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इन लोगों को कहते हुए 10 बार सुना कि 2047 की बात करते हैं, तब तक जाने किसकी सरकार रहेगी, खुद जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस तरह की बात बार-बार करते सुने हैं। इनको ध्यान नहीं है, इनको पता नहीं है, हम लोग वह लोग हैं जो हर दिन यह कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें। वर्षों की योजनाओं के साथ काम करने वाली हमारी विचारधारा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रामविचार नेताम जी कह रहे थे, लक्ष्य का संधारण हुआ, निर्धारण हुआ, समाज ने लक्ष्य बना लिया, समाज में 500 सालों तक संघर्ष चलता रहा लेकिन अंततोगत्वा हमारे भारत के समाज ने लक्ष्य को प्राप्त किया। भारत के समाज ने भारत के मानबिंदु को प्राप्त किया, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ। (मेजों की थपथपाहट) ये पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन संकल्प जिंदा रहता है। संकल्प पीढ़ियों की दूरियां तय करता है और पीढ़ियों की दूरी तय करके संकल्प अपने स्थान पर पहुंचता है, यदि कोई समाज संकल्प ले लेता है, इसीलिए इस संकल्प की जरूरत है, पूरे देश में इस संकल्प की जरूरत है और प्रदेशों में भी संकल्प की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संकल्प लेने में बड़ा साहब भी चाहिए, बहुत साहस की आवश्यकता होती है, संकल्प सामान्यत: नहीं लिया जा सकता है। 31 मार्च, 2026 को समूचे देश से नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, यह कहना कितना बड़ा संकल्प है। ऐसे संकल्प को लेने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है और इन संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए बड़े ही सामर्थ्य की जरूरत होती है। ऐसे संकल्पों को धरातल पर उतार लेना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम है। हम लोगों ने विभिन्न संकल्प समाज के तौर पर, विभिन्न संकल्प सरकारों के तौर पर लिए हैं और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए प्राण लगाया है। 2047 के इस संकल्प को अगर न लिया जाए,

अगर ये न कहा जाए कि 2047 तक देश उन्नत देशों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा, अगर ये न कहा जाए कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ की श्रेणी में आकर देश के समानांतर खड़ा होगा तो ये अभियान जनता के बीच कैसे बनेगा, कैसे लोगों को ये पता होगा कि कैसे चलना है, कैसे सरकार ये जानेंगी। सरकार किसकी होती है, किसकी नहीं होती है, ये चिंता का विषय कभी हमारे बीच में होता नहीं। सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, परंतु ये देश अमर होना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए, लोकसभा में हमारे नेता ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, छत्तीसगढ़ निर्माता ने ऐसा कहा है, वह हमारे लिए ध्येय वाक्य है, वह हमारे लिए काम करने का रास्ता है। सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, परंतु हमारे विकास के मार्ग को निर्धारित करने वाला यह लक्ष्य 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा, यह लक्ष्य हम लोग जरूर पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागों की चर्चा भी हुई है, यह भी कहा गया है कि विभिन्न विभाग किस तरह से काम करेंगे, उसके शार्ट टर्म के लिए भी गोल निर्धारित किए गए हैं, लॉग टर्म के लिए भी गोल निर्धारित किए गए हैं और ऐसा निर्धारित किया जाना आवश्यक भी है। मुझे इस विषय का बहुत अच्छे से ध्यान आता है कि बहुत सारे राज्य हैं, जिनके पास बहुत सारा खनिज है। लेकिन जिन राज्यों के पास खनिज है, वही राज्य गरीब हैं। ऐसा भी दिखता है। हम झारखंड को देख लें, अन्य कई राज्यों को देख लें, अफ्रीका को देख लें। अफ्रीका ऐसा देश है, जिसके यहां हीरे निकलते हैं, लेकिन वह देश गरीब है। उसका कारण यह है कि यदि प्रोसिसिंग करके खनिज निकाली जाए और उसकी प्रोसिसिंग वहीं की जाए तो उन्नति हो सकती है और यदि उसकी प्रोसिसिंग नहीं की जाएगी तो उन्नति नहीं हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इस बात को भली-भांति आकलन करते हुए छत्तीसगढ़ में यह कानून बनाया कि उसी कंपनी को कोई माइनिंग की लीज दी जाएगी, जो कंपनी यहां पर इंडस्ट्री लगाएगी। हमारे माइंस के माध्यम से निकलने वाली संपदा को प्रोसेस करके उसके पूरे ही पूरे उपयोग को हम अपने प्रदेश में कर लें। यह उसी के माध्यम से हुआ है। मैं आपका इस बात के लिए हृदय से आभार व अभिनंदन करता हूं कि माइनिंग उसी को दी जायेगी, जो इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में लगाएगी। ऐसा निर्धारण उस समय आपने किया था।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि आप सभी सहमत होंगे।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा (क्रमशः)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है कि वर्ष 2047 का यह डॉक्यूमेंट जब जनता के बीच में रखा जा रहा था, तब आपने अपने भाषण में कहा था कि आपने अपने ही जीवनकाल में छत्तीसगढ़ में मिट्टी का नेशनल हाइवे देखा है। अब यदि इसका निर्धारण न हो कि किस तरीके से नेशनल हाइवे बनना चाहिए, कितनी दूरी पर बनना चाहिए, कितनी स्पीड से बनना चाहिए तो हमारे लक्ष्य का ही निर्धारण नहीं होगा तो संधान किस लक्ष्य का होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी सभा में कहा था कि हम महानदी और इंद्रावती को मिलाना चाहते हैं और हमारे इस प्रोजेक्ट से लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि उस समय सिंचित होगी। इसके लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तो फिर संधान किस लक्ष्य का होगा? इसलिए ये सारी बातें, जिसके लिए आज विपक्ष बहुत बड़ा दोषी हुआ है, आज की चर्चा में भाग नहीं लेना, इस बात को वह कभी जस्टीफाई नहीं कर पायेंगे। वह कभी नहीं कह पायेंगे कि आज की बैठक में, आज की इस चर्चा में भाग न लेकर उन्होंने कोई राजनीतिक काम कर लिया, उन्होंने कोई अच्छा काम कर लिया, यह कभी नहीं कह पायेंगे। छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग को निर्धारित करते समय किसी बैठक में छत्तीसगढ़ का अगर वह जनप्रतिनिधि है, इस सदन का सदस्य है तो वह कैसे नहीं रहेगा। हर हाल में यह होना ही चाहिए था, लेकिन यह नहीं हो पाया। यह बहुत ही निंदनीय है। विभिन्न विषयों में चर्चा हुई है। मुझे संक्षिप्त में अपनी बात रखनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गृह विभाग के माध्यम से भी काम करते हुए चूंकि सुरक्षा और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो पूरे ही देश की बड़ी समस्या है, वह नक्सलिजम है और नक्सलिजम को समाप्त करने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करके और उस दिनांक के पीछे दौड़ लगाकर काम पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के सशस्त्र बल के जवान प्राणपन से लगे हुए हैं। जवानों की भुजाओं की ताकत पर ही छत्तीसगढ़ से निर्धारित समय में सशस्त्र नक्सलिजम समाप्त होगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी का जिस समय यहां आगमन हुआ था, तब से लेकर रणनीतियां बनीं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने लगातार इस बात की चिंता की और इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में आज बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने जा रहा है। यह हमारे छत्तीसगढ़ में 2047 के लक्ष्य के निर्धारण के लिए उसके संधान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम लोगों के द्वारा यहां पर विभिन्न दिशाओं में काम करते हुए यदि यह संभव हो सका है तो अनेक आयामों में एकसाथ काम करने से संभव हो सका है। साइबर क्राइम पर भी चर्चा हुई है। डिजिटल अरेस्ट पर चर्चा हुई है, पुलिस की ट्रेनिंग पर चर्चा हुई है, एन.डी.पी.एस. पर भी चर्चा हुई है। साइबर क्राइम बढ़ा है। मुझे ध्यान है कि सदन में जिस समय मोदी जी की सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने की बात कही थी, उस समय सदन में कैसी चर्चा हुई थी ? प्रणव मुखर्जी ने उस समय कहा था

कि Is there wi-fi will it work there ? इस लहजे में हंसी उड़ाते हुए बात कही थी और आज मुझे आपके सामने इस सदन में खड़े होकर यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला यदि कोई देश है तो वह हमारा देश भारत है। (मेजों की थपथपाहट) चूंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है तो चैलेंजेस भी सबसे ज्यादा हमारे पास हैं। साइबर क्राईम के लिये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत से काम किये हैं जैसे साईबर थानों को खोलने का, रायपुर में बड़े सेंटर बनाने का, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर बहुत इनवेस्टमेंट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिये काम किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शीघ्रता से समाप्त करता हूं। पुलिस की ट्रेनिंग या एन.डी.पी.एस. के लिये भी विशेष काम किये गये हैं। एन.डी.पी.एस. मतलब यदि कोई नशे का व्यापार कर ले और नशे का व्यापार करके पैसा कमा ले फिर जेल में जाकर 6 महीना जेल काटकर आकर उस पैसे का उपभोग कर ले, अब यह छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है। हमने इस सरकार में यह निर्णय किया है कि End to end investigation भी होगा और साथ ही साथ अगर किसी ने नशे के व्यापार से पैसा कमाया तो उसकी संपत्ति राजसात होगी, वह कुर्क होगी और उसकी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा कर दी जायेगी और वह आदमी उसका उपभोग नहीं कर सकता। इस बात का भी निर्धारण हुआ है। विष्णुदेव साय जी की सरकार में सफेमा के कोर्ट से अनेक प्रकरण पहली बार पारित होकर छत्तीसगढ़ में लागू हुए हैं (मेजों की थपथपाहट)। यह सारे ही काम इसलिए ही किये जा रहे हैं कि 2030 का एक लक्ष्य का निर्धारण है, जिसके माध्यम से 2035 के लक्ष्य का संधारण करना है और उसके बाद 2047 तक छत्तीसगढ़ हमारा उन्नत प्रदेश बने इसके लिए भी हम सब को मिलकर काम करना है। ए.आई. आधारित अपराध भी आने वाले समय में होने वाले हैं। ए.आई. आधारित अपराध तो इतने बड़े होने वाले हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ए.आई. के कारण ही अनेक फेक ऑडियो, फेक वीडियो, फेक टैक्स्ट, फेक फोटो के कारण अनेक आत्महत्याएं, अनेक फसाद, अनेक तरह की चीजें, अनेक तरह के क्राईम होने वाले हैं। इसलिए यह टैक्स्ट, यह वीडियो, यह फोटो, यह जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है या डिजिटल कंटेंट है, वह ए.आई. जनरेटेड है या फिर वह सीधे-सीधे बना हुआ है, रियल है, इसको क्लीयर करने का भी काम विभाग के माध्यम से हो रहा है। जनता के बीच यह टूल जल्द ही उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से इस बात का निर्धारण होगा कि यह जो कंटेंट है, यह ए.आई. जनरेटेड है या फिर यह सामान्य कंटेंट है। मतलब ऐसे भी Aspect पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में समूचे प्रदेश में 112 की व्यवस्था कर ली जायेगी और बहुत सारे और विषय हैं, जिस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। घुसपैठियों के विषय पर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है कि जहां के लोग सीधे-साधे है, सरल है और दूर-दूर से लोग आकर यहां घुसपैठ करना चाहते हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार में पहली बार छत्तीसगढ़ में एस.टी.एफ. का गठन किया गया, होल्डिंग्स सेंटर्स नोटिफाई किये गये और पहली बार

क्विट इंडिया के ऑर्डर हुए और लोगों को डिपोर्ट किया गया। (मेजों की थपथपाहट) यह छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद पहली बार हुआ है। बहुत सारे और मामले हैं लेकिन मैं उन सारी बातों पर नहीं जाता हूं। पंचायत के हिसाब से भी यह विषय है कि हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इसी 2047 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही हमको कर भी पंचायत से लेना है तो 2030 तक यह 300 करोड़ रूपये हो जाना चाहिए, इसका भी ध्यान है। 2047 तक हमारे समूचे प्रदेश के एक-एक गांव तक सड़कें तो पहुंचेंगी लेकिन उसमें केबल भी पहुंचना चाहिए। इसमें फाईबर ऑप्टिक केबल भी पहुंचना चाहिए। इस बात के निर्धारण के साथ भी हम सब काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह लक्ष्य का निर्धारण बहुत अच्छा है और होना ही चाहिए, नहीं होने से नहीं हो सकता है। पता ही नहीं होगा कि किस स्पीड से चलना है और पता ही नहीं होगा किस दिशा में चलना है तो चला कहां जायेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि "पंख है उड़ान भरे, लक्ष्य के संधान तक, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब आपके साथ है आगाज से अंजाम तक"। बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर जब हम सब सदन में विकसित भारत 2047 और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस अवसर पर इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज आप सहित, आपको भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी, सभी सम्मानित मंत्रीगण और सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई। कल ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपने कार्यकाल के 02 साल पूरे किये हैं, उसके लिये भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन, उनका धन्यवाद सहित उनको भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज हम सब विकसित भारत 2047 और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के परिप्रेक्ष्य में सदन में चर्चा कर रहे हैं। आज हम सब श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी को भी याद करते हैं। बिना किसी खून-खराबे, बिना किसी जद्दोजहद के छत्तीसगढ़वासियों की इच्छा के अनुरूप उन्होंने हमें पृथक करके छत्तीसगढ़ प्रदेश दिया, उसके लिये भी उनका अभिनंदन, उनको नमन करते हैं। पूर्व में वरिष्ठ सदस्यों ने बहुत सारा विषय इस विजन के संबंध में आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। कई वरिष्ठ सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले 02 कार्यकाल, आपके नेतृत्व में 15 वर्षों तक और अब 02 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उन कई कामों को हमें बार-बार याद करना चाहिए। विकसित भारत के संधारण के लक्ष्य को लेकर जब ये छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार हुआ, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि 2047 में विकास की दृष्टि से हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि जिन्होंने देश में 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत में

परिवर्तित करने का ये लक्ष्य रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही मूलमंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर, सबके प्रयास से, सबको विश्वास में लेकर पूरे देश का समग्र रूप से विकास करना। उनकी योजनाओं में, उनके कार्यक्रमों में ये परिलक्षित होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के डेव्हलपमेंट का विजन 2047 तक का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रियों ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो यहां पर प्रस्तुत किया है, वास्तव में ये इसी बात से परिलक्षित होता है। मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 वर्ष मुख्यमंत्री थे, समग्र रूप से छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आपके माध्यम से जिस तरीके की कल्याणकारी योजनायें बनाई गईं। ऐसी कई योजनायें हैं, जिसको देश में अन्य राज्यों ने गांव, गरीब, किसान, युवाओं, पढ़ने वाले बच्चों के लिये यहां से सीखकर उसको लागू किया। 1 रुपये, 2 रुपये किलो चावल की योजना, हालांकि ये विषय पहले आया है। 1 रुपये, 2 रुपये किलो चावल की योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर तक, बस्तर के सरगुजा तक, कोई परिवार, वंचित परिवार की मौत भूख से न हो, खाली पेट से न हो, इसकी चिंता आपने की और इतनी अच्छी कार्ययोजना आपने जो तैयार की, वह पूरे देश में रोल माडल बना। इसके लिये भी आपका अभिनंदन करता हूं। ऐसी कई योजनायें हैं। सरस्वती सायकल योजना हो, उस समय हमारे वनवासी क्षेत्र बस्तर, सरगुजा में जब हम देखते थे कि हमारी बेटियां जब हमारे स्कूलों की दूरी ज्यादा होती थी, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाईस्कूल, ऐसे समय में बच्चियों को उनके परिवारजन स्कूल इतनी दूर होने के कारण आने-जाने में अव्यवस्था के कारण स्कूल नहीं भेजते थे और उनको पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता था। इसकी चिंता आपने की। 2 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 5 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 7 किलोमीटर में हाईस्कूल ऐसा आपने स्थापित किया । साथ ही साईकिल जो बच्चियों के लिये था, उसमें उनको आगे बढ़ाने में इसके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ । इस तरीके से हमारे देश के कई ऐसे कार्यक्रमों में, मैं इसीलिये पीछे जाता हूं कि यदि हम अविभाजित मध्यप्रदेश की ओर देखें, उसकी कल्पना करें तो चूंकि मैं बस्तर से आता हूं, बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में कोई मध्यप्रदेश में उस समय के मुख्यमंत्री, वह किसी भी दल से हों, उनका आना साल में एक-बार ही हो पाता था । विकास के कार्यक्रम, विकास की योजनाएं और बहुत सारी चीजों में बस्तर वंचित रह जाता था, मैं बस्तर में फिर से आउंगा लेकिन अभी जो विजन है और जब उसके लिये हम लोग बार-बार बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार और उसके फायदे । भारतीय जनता पार्टी की आपके नेतृत्व में बनने वाली सरकार के पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो कांग्रेस की सरकार कुछ समय तक की थी, जनता ने उसको भी देखा । आपके नेतृत्व में 15 साल, उसको भी देखा और इन 2 वर्षों में, 2 वर्ष का समय, मैं इन 2 वर्ष के समय में यह सोचता हूं कि जितनी योजनाएं और जब हम अपनी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तो हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता

पार्टी जो कहती है वह करती है । जो-जो वचन, जो-जो वादे किसी भी चुनाव के पहले चाहे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हों । अब यदि हम प्रधानमंत्री आवास को लेकर बात करें और आज बड़ा दुख होता है कि पूर्व में हमारे सभी श्रेष्ठ वक्ताओं ने इस बात को भी रखा कि जब आज छत्तीसगढ़ के 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के विषय पर चर्चा हो रही है तो यह बड़ा दुखद विषय है कि आज सारा विपक्ष सूना है । इनको तो छत्तीसगढ़ की जनता और क्षेत्र की जनता को जवाब देना पड़ेगा, जब विकास के एजेंडे तय होते हों, जब 2047 तक का विकास का रोड मैप तय हो रहा है, उसमें आपकी भूमिका क्या है ? कांग्रेस के लोग 5 साल सरकार में रहे, किस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई हुई ? अत्याचार-अनाचार किस तरीके से बढ़ा? भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ा ? आज के दिवस पर उसको भी याद करने की जरूरत है और हम 2 वर्ष में, चूंकि ऐसी कई योजनाएं हैं, मैं प्रधानमंत्री आवास पर पुन: आता हूं । मैं प्रधानमंत्री आवास की बात कहूं तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि शपथ लेने के बाद आपने निर्णय लिया कि जब तक छत्तीसगढ़ के 18 लाख ऐसे गरीब परिवारों के लिये, मैं प्रधानमंत्री आवास की फाईल पर साईन नहीं करूंगा तब तक मैं मुख्यमंत्री निवास में कदम नहीं रखूंगा, यह दृढ़ इच्छाशक्ति होती है । (मेजों की थपथपाहट) विकास की ओर पहला कदम, केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार के साथ क्योंकि जब हम मोदी जी की बात करते हैं, उनके नेतृत्व की, उनके नेतृत्व क्षमता की बात करते हैं । अभी मुझसे पहले हमारे कोई श्रेष्ठ वक्ता, कोई वरिष्ठ सदस्य इस बात को कह रहे थे कि आज उस समय जब, वित्त मंत्री जी ही कह रहे थे कि जब केंद्र में मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली उसके पहले आर्थिक रूप से, आर्थिक विकास की दृष्टि से जी.डी.पी. हमारा आर्थिक उन्नति की दृष्टि से हम दसवें नंबर पर रहते थे और इन 11-साढ़े 11 वर्षों में उनकी नीतियां, उनकी विदेश नीतियां, उनकी आर्थिक नीतियां, उनका प्रबंधन, उनकी कल्याणकारी योजनाओं ने आज हमको पूरे विश्व के मानचित्र पर चौथे नंबर पर हमारा देश आर्थिक रूप से उन्नति और विकसित भारत के रूप में बढ़ रहा है । (मेजों की थपथपाहट) आने वाले कुछ समय में हम तीसरे नंबर पर आयेंगे, यह यूं ही नहीं हुआ । इसके पीछे सबसे बड़ी भावना है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना, राष्ट्र हित सर्वोपरि और उसके अंदर समाहित है आत्मनिर्भर भारत । आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम अपने संसाधनों का सद्उपयोग करते हुए और उनको एक अच्छी दृष्टि से, अपने आपको, अपने इस देश का विकास करने में उस आत्मनिर्भर भारत की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी । इसकी शुरूआत भी कर चुके हैं, चाहे हमारे बाह्य रक्षा का मामला हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, इस दृष्टि से आज यह स्थिति है कि आज ऐसे कई देश हैं, जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं, जो हमारे हथियार हैं उनको खरीदने की होड़ लगी हुई है । जबकि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हम बाहर से गोली, बारूद, बम और लड़ाई के लिए युद्ध के विमान खरीदा करते थे। स्वाभाविक रूप से इन बातों को लेकर समय-समय पर इस बात को भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। उसको उन्होंने

चरितार्थ करके दिखाया है। इस पर स्वदेशी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरीके से जी.एस.डी.पी. का जो रिफार्म हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से यह पूरे देश और देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतना कम है। उन्होंने ऐसे कई नये रिफार्म्स लाये। इस सदन में मैं आपके माध्यम से उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर संक्षिप्त में बात रखना चाहूंगा कि विजन 2047 छत्तीसगढ़ अंजोर के अंतर्गत लक्ष्य यह है कि हम 2047 में हम अपनी योजनाएं, अपनी सोच इस तरीके से बनायें कि वर्ष 2047 तक उन कार्यक्रमों, उन योजनाओं को सुचारू, व्यवस्थित रूप से संचालित करते हुए, इस विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करना है। उसका एक रोड मैप तैयार हुआ है। आज उसकी शुरूआत है, लेकिन हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार में आते ही योजनाएं और कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। मेरे पास संक्षिप्त में ऐसे लगभग 20 रोड मैप की योजनाएं हैं जिसका विचार संधारण करने की दृष्टि से विजन 2047 छत्तीसगढ़ अंजोर में समाहित किया गया है। राज्य का जी.डी.पी. 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर, 2047 तक 75 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। Nothig is wrong inning.इसमें इसकी दृष्टि से आगे कार्ययोजना बनाकर, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में काम करेगी। ऐसे और भी विषय हैं जी.डी.पी. में, सेवा क्षेत्र में जो वर्तमान में 35 प्रतिशत है, उसे 50 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। विशेषकर साक्षरता दर जो वर्तमान में 78.2 प्रतिशत से 99.9 प्रतिशत है। अगर हम इस तरीके से लक्ष्य को साध के चलें। अभी हमारे आदरणीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सपने वह भी सकारात्मक सोच के साथ, हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और वह हमारी सरकार कर रही है। इसमें किसानों की आय के संबंध में 2047 तक 10 गुना जो उनका आय का लक्ष्य है, उसको रखा गया है । मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। वर्तमान में जो बेरोजगारी दर है जिसके विषय में कांग्रेस तरह-तरह से सेट करने का काम करते आ रही है। जो अभी 27 प्रतिशत है, 2047 तक 2.7 प्रतिशत को 1 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रति व्यक्ति आय 2047 तक 10 गुना वृद्धि तक लक्ष्य रखा गया है। इस तरीके से बहुत सारे विषय हैं। अब राज्य में रेल मार्गों की लम्बाई से लेकर जब हम वन्दे भारत की बात करें, केन्द्र की योजनाओं को समाहित करके चलें। चाहे हम अभी जो हमारा भारत माला मार्ग निकला है, इस तरीके से यह सोच हो। जब पूरे देश में केन्द्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गड़करी जी ने जो 1 लाख 10 हजार से भी ज्यादा प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा है और फोर लेन, टू लेन रोड बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त भी कर रहे हैं क्योंकि मैं बस्तर से आता हूँ। बस्तर को समझना भी बहुत आवश्यक है। बस्तर के विषय में सभी ने कुछ न कुछ अपना विषय रखा है। हम बस्तर को ही देख लें। वर्तमान में कल ही आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी ने बस्तर ओलम्पिक का समापन

किया। उस कार्यक्रम में आप, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उपमुख्यमंत्री, अरूण साव जी, विजय शर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी उपस्थित थे । इसके पहले आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा, वह पूरी तरीके से नक्सलवाद की गिरफ्त में था और उन्होंने दृढ़ इच्छा के साथ निश्चय किया कि मार्च, 2026 तक बस्तर ही नहीं, पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देने का जो निर्णय लिया, उस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं । उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, धन्यवाद । हमारे गृहमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी विराजमान हैं । इसके बाद उन क्षेत्रों में जो योजना लाई गई- नियद *नेल्लानार*, उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं । ऐसे गांव जो वर्षों से, करीब 3 दशकों से सरकारी सुविधाओं से वंचित थे । उससे पहले से तो कुछ था ही नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद और अब 25 वर्ष का हमारा युवा छत्तीसगढ़ है, लेकिन वे सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित थे, जिनको पाने का उनका अधिकार है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि उन जगहों पर और वहां जो कैम्प लगे हुए हैं, उसके आसपास बसे हुए गांव में सरकार की 25 से 27 योजना का लाभ मिले, चाहे वहां सड़क का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेव्हपलमेंट हो, स्कूल खुले हों । वहां स्कूल भी नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं था, स्वास्थ्य और शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी । वहां पर 1 रूपए और 2 रूपये किलो चांवल की योजना का लाभ भी उन लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पाता था, बड़ी दूर से लाना पड़ता था । उसको सम्पूर्ण रूप से विकसित करने का लक्ष्य अपने आप में बहुत बड़ी बात है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब बस्तर की बात करते हैं तो हमारा बस्तर वास्तव में स्वर्ग है । मैं बस्तर से हूं, इसलिए उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस्तर में बस्तर का अपना सांस्कृतिक महोत्सव है । सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ वहां के बोलचाल, बोली-भाषा, वहां का खान-पान, रहन-सहन भी है । मैं उसको भी यहां पर स्मरण करना चाहूंगा कि इसमें बस्तर ओलंपिक के साथ-साथ बस्तर परब भी वहां पर प्रारंभ किया गया है, जो कि इस तरीके से बस्तर की 7-8 विधाएं हैं जैसे बस्तर के जो परिधान है, वहां के गीत हैं, गायन है, नृत्य है, संगीत है, वहां का खान-पान है, बोली-भाषा को लेकर और बस्तर को, बस्तर के हमारे युवाओं को, बस्तर के अंदर रहने वाले हमारे गांव के लोग हैं, उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक प्लेटफार्म मिल गया । (मेजों की थपथपाहट) बस्तर ओलंपिक में गत वर्ष भी आदरणीय गृहमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय पहली बार 1,65,000 युवा प्रतिभागियों ने, हमारे बेटे-बेटियों ने विभिन्न खेलों में, पारम्परिक खेलों में हिस्सा लिया और इस बात को कहते हुए मुझे सदन में गर्व हो रहा है कि इस वर्ष प्रतिभागियों की संख्या बढ़कर 3 लाख, 91 हजार हो गई है । बस्तर जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्रों में सरकार की पहुंच कितने नीचे तक पहुंच रही है । हमारे बस्तर में प्राकृतिक सौंदर्य है । अभी तीरथगढ़ जैसी अन्य जगहों भी हैं । मैंने माननीय वन मंत्री केदार कश्यप जी से भी इस बात को कहा, वे हमारे बस्तर से ही हैं । तीरथगढ़ में उसी दिन मेरा जाना हुआ था तो वहां पर बैम्बू

राफ्टिंग की कई तरीके से विधाएं चालू हो गई हैं और साथ ही साथ वहां पर्यटन की दृष्टि से, बस्तर और सरगुजा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात आ रही थी । इस तरीके से वहां पर होम स्टे का जो कार्यक्रम चालू हुआ है, जिससे कि अब बस्तर के जो युवा हैं, वे वहीं रहकर वहीं रोजगार से जुड़ने का काम हो रहा है तो रोजगार के अवसर भी वनांचल क्षेत्रों में उनको प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां के लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है, सरकार की योजनाओं के प्रति बढ़ा है । मैं बहुत सारे विषय रखने की इच्छा रखता था, बहुत सारे विषय आ भी गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन का जिक्र करना भी मैं आवश्यक समझता हूं, हमने यह भी वचन दिया था । महतारी वंदन में प्रति माह 70 लाख से भी ज्यादा बहिनें, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनको 1 हजार रूपए प्रतिमाह 1 से 3 तारीख तक उनके खाते में राशि डालने का जो निर्णय है, वह जब से चालू हुआ है, अभी तक निरंतर चल रहा है, आगे भी निरंतर चलेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है । (मेजों की थपथपाहट) बिना गैप के 3100 रूपए में प्रति क्विंटल धान खरीदी का भी एक विषय है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने संसाधनों की लूट मचाई थी, उस समय चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता, किसान भाईयों को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार बनते ही 3,100/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदना चालू करेंगे। उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमण्डल बधाई पात्र हैं। मैं उनका अभिनन्दन करता हूं कि हम जो कहते हैं, वह करते हैं, आप इसको चरितार्थ करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं में सुपर स्पेशयालिटी हास्पिटल की बात हुई थी, वह बस्तर में चालू हो रहा है। मेरे ख्याल से 3 फैकलीटीज चालू भी हो गया है, इसलिए उसके लिए भी अभिनन्दन है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो तीर्थ योजना चालू की गई थी, उसे पुन: रामलला दर्शन योजना के तहत 37 हजार से भी ज्यादा दर्शनार्थी श्रद्धालुओं का लगातार ट्रेन के माध्यम से जाने की व्यवस्था सरकार ने की है, उसके लिए भी अभिनन्दन है। मैं अपनी बात समाप्त करूं। यह छत्तीसगढ़ महतारी का प्रताप है। जब हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो यदि आप अनुमति दें तो संक्षिप्त में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ महतारी का प्रताप है कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय नितीन नवीन जी और बिहार के कैबिनेट मंत्री को आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं सभी की तरफ से उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पुन: इस बात के साथ कि डेवलपमेंट का विजन वही रखते हैं, जो डेवलपमेंट की सोच रखते हैं और जिनके पास विजन नहीं है, उनकी सारी कुर्सियां खाली हैं। इनकी तो पलायन की आदत है। अध्यक्ष महोदय, हम तो लोकसभा की कार्यवाही देखते हैं तो उसमें भी यही देखते हैं। सांसद प्रश्न करते हैं और जब हमारे गृहमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और अन्य केन्द्रीय मंत्री का जवाब आता है तो

दो मिनट में पूरा पलायन कर जाते हैं। पूरा सदन खाली करके चले जाते हैं। वही स्थिति इनकी भी है। निश्चित रूप से जिन्होंने कभी डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं है, आज भी इन्होंने पलायन किया है। मैं पुन: धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र के पवित्र मन्दिर छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस नये भवन का आज पहला दिवस है। मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) साथ ही सभी सदस्यगणों को भी बधाई देता हूं और अधिकारियों को भी बधाई देता हूं। आज का यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि आज के ही दिन 14 दिसम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ विधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। इसीलिए आज रविवार होते हुए भी आपने यह सत्र आयोजित किया है, सत्र आहूत किया है। 14 दिसम्बर, 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हाल में छत्तीसगढ़ विधान सभा का पहली बैठक हुई थी। मैं जशपुर हॉल के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपको तो मालूम होगा। राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल 14 दिसम्बर, 2000 को पहली बैठक हुई। वह हॉल हमारे जशपुर के लाल, पूर्व सांसद, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री स्व. दिलीप सिंह जूदेव जी ने अपने सांसद निधि से बनवाया था। (मेजों की थपथपाहट) वह जशपुर के होने के कारण मुझे इसका बड़ा फ़क्र भी है। आज हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को रजत जयंती वर्ष की भी बधाई देते हैं। अभी 1 नवम्बर, 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन इस नए भवन को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ वासियों को सौंपा, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी है (मेजों की थपथपाहट) और उस समय जो उन्होंने प्रेरक संदेश छत्तीसगढ़ वासियों को दिया है, वह हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहेगा और लगातार उस पर हम लोग अमल करेंगे। आज विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा सदन में हो रही है और मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी और विद्वान वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, (मेजों की थपथपाहट) जिनके मार्गदर्शन में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और सरकार में आने के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है, इसलिए छत्तीसगढ़ का भी यह दायित्व है कि उसमें छत्तीसगढ़ सहयोगी बने और पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि 2014 में वह पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले लगातार 10 वर्षों तक यू.पी.ए. के गवर्नमेंट में हमारा यह देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर स्थिर रहा, लेकिन वर्ष 2014 में पहली बार आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, आज इस देश की जनता ने उनको तीसरी बार

प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा है और ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो नये भारत का निर्माण कर रहे हैं और उन्होंने अपने दूरदृष्टि और अथक परिश्रम के कारण देश को आर्थिक दृष्टिकोण से चौथे स्थान पर लाकर खड़ा किया है तो पूरे देश को भरोसा भी है कि वर्ष 2047 तक हमारा यह भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया। उन्होंने आज अपने प्रस्तावना उद्बोधन में सारी बातों को बताया भी है। हर वर्ग से मुलाकात करके युवा, महिला, किसान, व्यापारी, सभी वर्गों से अलग-अलग बैठकर उनसे राय मशविरा करके यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और मैं भी अनेक अवसरों पर उनके साथ रहा हूं तो इस तरह से हमारा यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और इसमें कुल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे अधोसंरचना जैसे 13 क्षेत्रों को विशेष फोकस करके और 10 विजन का गठन करके हम लोगों ने इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया है और उस अनुसार कार्य करने का सरकार का प्रयास है और उस पर आज हमारे बहुत सारे सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इसकी प्रस्तावना तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना उद्बोधन देकर किया है, लेकिन इस पर हमारे विद्वान सदस्य श्री अजय चंद्राकर जी, श्री धरमलाल कौशिक जी, श्री धर्मजीत जी, सुश्री लता उसेण्डी जी, श्री सुनील सोनी, श्रीमती भावना बोहरा, श्री अनुज शर्मा, श्री सुशांत शुक्ला हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, सबने भी इस पर भाग लेकर अपने सुझाव दिए हैं, मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने 18 नवंबर को पुराने विधान सभा में एक दिवस का अंतिम सत्र रखा था, जिसमें हम सब लोगों ने छत्तीसगढ़ निर्माण की जो 25 वर्ष की यात्रा थी, उसके जो अनुभव थे, उसको साझा किया और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा की है। यह छत्तीसगढ़ जो एक गरीब और पिछड़ा हुआ प्रदेश था, उसको आपने देश में एक नई पहचान दिया। चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूं, मैं सरगुजा संभाग का हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होती है। गरीब लोग कोदो, कुटकी, महुआ खाते थे, कभी-कभी उनको वह भी नसीब नहीं होता था। यह वह क्षेत्र था, जहां लोगों की भूख से मौत होती थी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात् खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया। आज कोई भूख का नामो-निशान नहीं है और आप चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास किया। 18 नवंबर की चर्चा में हम सब लोगों ने यह साझा किया और अभी वर्ष 2023 के विधान सभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति से हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके गारंटी पर विश्वास करके फिर से हम लोगों को सरकार में चौथी बार बैठाया है तो आज दो साल के कम समय में ही हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा था, उसको हमने अल्पकाल में पूरा करने का प्रयास किया है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहां सब बातों को रखा है। 18-18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित

हो गये थे। सरकार शपथ लेने के दूसरे ही दिन पहले केबिनेट में सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। आज मुझे सदन में यह बात बताते हुए फक्र होता है कि दो साल के अंदर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गई है। अभी तक 7-8 लाख प्रधानमंत्री आवास बन भी चुके हैं। पिछले दो अवसरों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब बिलासपुर आये थे और स्थापना दिवस में भी आये थे तो उस समय उन्होंने करीब 7-8 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराया। बीच में हमारे देश के पंचायत मंत्री और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आये थे। उनके करकमलों से भी 51 हजार गृह प्रवेश हुआ था। हमारी सरकार ने किसानों का वादा भी पूरा किया है। अभी हम लोग तीसरा साल किसानों का धान खरीद रहे हैं। 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम महतारी वंदन योजना में 22 किश्त दे चुके हैं। हर महीना पहले ही सप्ताह में 70 लाख महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रूपये भेजने का काम करते हैं, जिससे सुदूर नारायणपुर जैसे क्षेत्र में, जहां पर पी.व्ही.टी.जी. के लोग हैं, महिलाएं हैं, अबूझमाड़िया जनजाति के लोग हैं, वहां भी इसका लाभ हो रहा है। आज प्रदेश में 5 लाख 62 हजार से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी पं. दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में 10 हजार रूपये देने का काम कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना में 37 हजार से ज्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। हमारे राम भक्त लगातार अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम जी का दर्शन कर रहे हैं। आपने बुजुर्गों के लिए एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किया था, जो पिछली सरकार में बंद हो गया था। उसको भी हमने फिर शुरू किया है। आज हमारे 5 हजार से ज्यादा बुजुर्ग भी उसका लाभ ले चुके हैं। इस तरह से दो साल में मोदी की गारण्टी के काम को पूरा करने का हम लोगों ने प्रयास किया है । विजन 2047 में 13 बिन्दुओं को फोकस करके हम लोगों ने मिशन बनाये हैं और उसके अनुसार काम कर रहे हैं । इसके साथ ही हम लोगों ने नई उद्योग नीति भी लाया है, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 को हमारे उद्योग मंत्री और उनकी पूरी टीम ने तैयार किया है, जिसकी सराहना पूरे देश और विदेशों में भी हो रही है । इसका परिणाम यह है कि अभी एक साल भी नहीं हुये हैं, लगभग 8 लाख करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, केवल निवेश प्रस्ताव ही पास नहीं हुये हैं, बल्कि कई चीज धरातल में दिखने भी लगा है । सेमी कंडक्टर प्लाण्ट का काम शुरू हुआ है, डाटा सेंटर का काम शुरू हुआ है, आने वाले एकाध साल में धरातल में और बहुत कुछ दिखेगा कि उद्योग यहां पर भूमि आबंटित करा लिये हैं। हमारे प्रदेश को इस तरह से नई उद्योग नीति का लाभ भी मिलेगा । हम लोगों ने नई उद्योग नीति में विशेषकर रोजगार को जोर दिया है, अभी तक दो साल में 10-12 हजार से ज्यादा हमारे बेटा-बेटियों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सभी बेरोजगार बेटा-बेटियों को, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते । हमने उद्योगों में रोजगार की विशेष व्यवस्था की है और नई उद्योग नीति में अगर कोई उद्यमी अपने

उद्यम में स्थानीय 1000 लोगों को रोजगार देता है तो वहां पर विशेष प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है । यह हमारी नई उद्योग नीति है । नई उद्योग नीति लाने के बाद एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का एम.ओ.यू. हुआ है । अभी हमारा प्रदेश 30 लाख मेगावाट बिजली पैदा करता है, लेकिन अभी जो एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का एम.ओ.यू. हुआ है, उससे हम आने वाले वर्षों में 30 लाख मेगावाट बिजली और पैदा कर पायेंगे । हम अपने प्रदेशों के साथ ही और भी अन्य पड़ोसी राज्यों को उर्जा देने में सक्षम होंगे । माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, हम लोग उस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं । हम अपने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की ओर ले जा रहे हैं, प्रदेश में भी सब्सीडी का प्रावधान हुआ है । भारत सरकार से 1 किलोवाट में 30 हजार का सब्सीडी है और हम लोग अपने प्रदेश में 1 किलोवाट में 15 हजार का सब्सीडी दे रहे हैं, इस तरह से 1 किलोवाट में 45 हजार का सब्सीडी और 2 किलोवाट में उससे डबल और तीन किलोवाट में भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलाकर 1 लाख 8 हजार का सब्सीडी है और अभी तक 11-12 हजार से ज्यादा घरों में हम लोग सोलर पैनल लगा चुके हैं । हम लोगों का आगे लक्ष्य बड़ा है और उस दिशा में काफी काम हो रहे हैं । हम लोग छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और आज इस सदन में काफी बातें हुई है । यहां बस्तर की भी बात हुई है, लेकिन सब को मालूम है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है । यह खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहां की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहां के मेहनतकश किसान हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां पर गरीबी थी, उसका मुख्य कारण ये नक्सलवाद था । आज डबल इंजिन की सरकार है, उसका भी लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा है । जब हम लोग सरकार में आये और दिसम्बर 2023 में सरकार ने शपथ ली तो अगले महीना ही वर्ष 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी यहां पर आये और हम सब लोगों का, हमारे जवानों का हौसला औफजाई किया, तब पता चला कि देश का 75 प्रतिशत से ज्यादा माओवाद, नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में ही बचा है । हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनका आर्शीवाद तथा हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और उनकी रणनीति के कारण आज हमारे जवान उत्साह के साथ माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगातार सफलताएं मिल रहीं हैं, बड़े-बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हुए हैं और हम यह कह सकते हैं कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, नक्सलवाद की कम टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसे ले रहा है। ये जो अभिशाप हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, यहां के विकास के लिए था, इससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी। अभी हम लोगों ने बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम का प्रयोग किया है, पिछले साल बस्तर ओलंपिक की शुरूआत हुई थी, जिसमें हमारे 1 लाख 65 हजार युवा बेटा, बेटी, भाई, बहन लोग भाग लिए थे, इस साल उसका तीन गुना 3 लाख 91 हजार पंजीयन हुआ जिसमें हमारी बेटियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी, पंडुम में भी पिछले साल हमारे 47 हजार भाई बहन भाग लिए थे, इस साल उम्मीद

है कि इसमें तीन गुना संख्या में वृद्धि होगी। ये प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। हम लोग अच्छी पुनर्वास नीति लाए हैं, इसका भी परिणाम है कि पुनर्वासित लोगों की संख्या, आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनको हम लोग स्कील देकर रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में जो माओवाद एक कलंक था, यह अब समाप्ति की ओर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने इसमें डेडलाईन भी 31 मार्च, 2026 तय कर दी है, उसके बाद निर्विवाद गति से हमारा ये छत्तीसगढ़ विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। सभी विषयों पर बात हुई है, हमारे सभी विधायकगण अजय चंद्राकर जी, धरमलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, राजेश मूणत जी, लता उसेंडी जी ने भी कई तरह के परामर्श दिए हैं, उनके सभी सुझावों को हम लोग अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 में शामिल करेंगे। अंत में मैं ज्यादा न कहते हुए सभी से आह्वान करते हुए कि हम सभी लोग संकल्प लें कि 2047 तक अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करें और आज जो हमारा यहां का GSDP 5 लाख करोड़ है उसको अगले 5 साल में उसका डबल करेंगे और 2047 तक 75 लाख करोड़ में अपने प्रदेश की GSDP को पहुंचायेंगे। इसके लिए हम सब लोग प्राण प्रण से काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए, माननीय सदस्यों का अधिकारियों का और पूरे छत्तीसगढ़वासियों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आज का यह दिन आप सबके, मेरे और उपस्थित सभी विधायकों के लिए जीवनभर यादगार रहेगा। क्योंकि नये विधान सभा में प्रवेश 25 साल की यात्रा के बाद पहले दिन रविवार के दिन छुट्टी छोड़कर आपने यहां अपना बहुमूल्य समय दिया, मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी साथी विधायकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। (मेजों की थपथपाहट) इस यात्रा का गौरव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जशपुर हाल से यहां तक की 25 साल की यात्रा और सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरा होने के बाद ये पहली बैठक है। एक संकल्प के साथ, एक पाजीटिव सोच के साथ, एक कल्पनाशक्ति की 2047 में छत्तीसगढ़ कहां होगा, इस जमीन के इस विधान सभा के इस हाल में आने वाले 2047 तक ये गूंजता रहेगा कि छत्तीसगढ़ हिन्दुस्तान की सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में जाने की क्षमता रखता है और ये बनकर दिखाएगा, ये आपकी संकल्पशक्ति है, ये आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की। (मेजों की थपथपाहट) मैं आज आप सबके समग्र विकास दीर्घकालीन योजनाओं पर की गई चर्चा और विजन 2047 में जो भाग लिया, मैं सबको धन्यवाद दूंगा, आज बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और उन महत्वपूर्ण सुझावों को मैंने आज संपूर्ण कार्यवाही को देखा, मैं इस पूरी कार्यवाही को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को एक एक शब्द प्रेषित करूंगा। मैं यह आग्रह करूंगा कि इन सुझावों को माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी भविष्य में प्रस्तावित नीति और योजनाओं में

समाहित कर सकें ताकि आज आपके सुझाव का आने वाले वर्ष 2047 तक बेहतर उपयोग हो सके, यही मैं चाहता हूं। आप सबको इस अवसर पर उपस्थित होने पर मैं बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(6 बजकर 25 मिनट पर विधान सभा सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 24, शक संवत् 1947) के पूर्वान्ह 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2025

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं